छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026
(फाल्गुन 06 , शक सम्वत् 1947)

[अंक 03]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपको इस आसंदी में देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप उसी गरिमा से आज सदन को संचालित करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अजय भैया, स्वागत तो मैं भी कर रहा हूँ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अजय भैया, धरम भैया धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, आपका स्वागत हैं। हम लोगों को विश्वास है कि हमें आपका पूरा संरक्षण मिलेगा।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, हमारे माननीय अजय चन्द्राकर जी रेड अलर्ट में आ गये हैं।

एक माननीय सदस्य :- सभापति महोदय, ढाई साल में पहली बार ओ हर खुश होइस हे।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, वह हमेशा रेड अलर्ट में रहते हैं।

सभापति महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, प्रश्न करिये।

बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत ग्रीनरी एवं आक्सीजोन निर्माण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

1. (*क्र. 492) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सत्य है कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत बिलासपुर शहर में ग्रीनरी एवं आक्सीजोन बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है? (ख) कंडिका "क" के अंतर्गत विगत 2021 से कहां-कहां पर वृक्षारोपण के कार्य किए गए हैं? कहां-कहां पर आक्सीजोन बनाया गया है अथवा प्रस्तावित है? वृक्षारोपण हेतु कौन-कौन से मद से राशि स्वीकृत की गई है? वर्षवार विवरण देवें? (ग) कंडिका "ख" के आक्सीजोन की वर्तमान स्थिति क्या है? किए गए वृक्षारोपण में से कितने प्रतिशत वृक्ष जीवित अवस्था में हैं? वर्षवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) बिलासपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत बिलासपुर शहर में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए उद्‌यानों का निर्माण किया गया है। आक्सीजोन का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत श्री राम टॉवर के पीछे व्यापार विहार उद्‌यान, रमजानी बाबा तालापारा उद्‌यान, वृहस्पति बाजार उद्‌यान, सिम्स उद्‌यान, हैप्पी स्ट्रीट, मैथलीशरण गुप्त उद्‌यान नर्मदा नगर, टाउन हाल उद्‌यान, नेहरू चौक से मंगला चौक के मध्य, मिनोचा कालोनी स्मार्ट सिटी सड़क, रिवर व्यू सड़क, तिफरा फ्लाई ओवर के नीचे, कोन्हेर उद्‌यान एवं बाल उद्‌यान में ग्रीनरी हेतु घास, छोटे पौधे तथा हैजिंग लगाने का कार्य किया गया है। (ख) बिलासपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत विगत 2021 से वृक्षारोपण का कार्य नहीं कराया गया है एवं आक्सीजोन का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन की मिशन अवधि मार्च 2025 में समाप्त हो चुकी है, अतएव स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्‌वारा कोई भी आक्सीजोन निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैंने बिलासपुर के आक्सीजोन के बारे में और वहां कहां-कहां पर ग्रीनरी है, कहां-कहां गार्डन हैं, उसके बारे में माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा है। उन्होंने विस्तृत जवाब देते हुए यह भी बताया है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अब खत्म है परन्तु माननीय मंत्री जी, मैंने इस प्रश्न को इसलिए पूछा था कि बिलासपुर जिले के नगर निगम में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो वार्ड नं. 1, 2, 3 और 4 हैं, उसकी पिछली सरकार में घनघोर उपेक्षा हुई थी और वहां पर विकास के कोई भी काम नहीं हुए थे। वहां उन चारों वार्डों के विकास के लिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपने और इस सरकार ने बहुत बड़ी राशि दी है। मैं आपसे सिर्फ एक मांग करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 3 में एक बढ़िया छोटा-सा गार्डन, मुक्तिधाम और उसकी एप्रोच रोड बनवाने के लिए आप अपने विभाग के लोगों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे या नहीं करेंगे? यह आपसे मेरा निवेदन है, प्रश्न भी है और यही आग्रह भी है। दोनों एक ही बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कल जो बजट आया है उसमें बिलासपुर के लिए चौकवाइस बजट पढ़ा गया था। आप भी बिलासपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे बिलासपुर का नक्शा ही बदल जाएगा। भाई साहब को प्रश्न करने की कहां जरूरत है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैंने जो पूछा है, उसके बारे में मैं बता दूँ कि आप भी उससे पीड़ित हैं। हमारे गाँव के इलाके को नगर निगम में शामिल किया गया। जिन लोगों ने शामिल किया पहले वह लोग भूटान के राजा थे और आज की तारीख में वे प्रजा हो गए हैं। मैं उन लोगों के लिए मांग कर रहा हूँ कि वहां की प्रजा के लिए आप मुक्तिधाम, एप्रोच रोड और छोटा-सा अच्छा गार्डन बनवा दीजिये। हमारे भी लोगों को शौक है। साहब, वे हमारे ही जिले के लोग हैं, आप कृपा करके उन्हें यह दे दीजिये।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू किया था। देश के सौ शहरों में बिलासपुर भी उसमें शामिल था। इसमें अनेक प्रकार के अधोसंरचना के काम हुए हैं और उसी के अंतर्गत आठ अलग-अलग स्थानों पर उद्यानों में ग्रीनरी हेतु घास, छोटे पौधे तथा हैजिंग लगाने का कार्य किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिलासपुर नगर निगम में कोई भी आक्सीजोन का निर्माण नहीं हुआ है और वृक्षारोपण का कोई भी काम नगर निगम या स्मार्ट सिटी के मद से नहीं हुआ है। बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत जो वृक्षारोपण और आक्सीजोन के काम हुए हैं, वह अलग-अलग योजनाओं से एवं अलग-अलग मद से हुए हैं। वर्ष 2017-18 में वन विभाग द्वारा व्यापार विहार में आक्सीजोन का निर्माण किया गया था। वह आक्सीजोन सही सलामत है, वहां के पौधे सही सलामत हैं। बाद में अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 'वुमेन फॉर ट्री' परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 10 महिला स्व-सहायता समूहों की कुल 50 महिलाओं द्वारा 5,000 पौधों का रोपण किया गया है और आज की स्थिति में उसमें से 4,700 पौधे जीवित हैं और बढ़ रहे हैं। जो 300

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पौधे हैं, उनको योजना, एग्रीमेंट के अनुरूप प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ में सी.एस.आर. फंड से कोनी में 2 एकड़ क्षेत्र में 1 हजार पौधे अरपा अर्पण समिति के एन.जी.ओ. के द्वारा किया गया है। गोकुलधाम में 0.5 एकड़ क्षेत्रफल में 300 पौधे हिन्दू एकता मंच एन.जी.ओ. के द्वारा तथा सिरगिट्टी में सी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा 4.2 एकड़ क्षेत्रफल में 10 हजार पौधे मियाबाकी माइक्रोफॉरेस्ट विकास के तहत रोपित किये गये हैं। बिरकोना में 20 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिये सी.एस.आर. मद से एस.ई.सी.एल. को प्रस्ताव गया है। इस तरह से वृक्षारोपण की दिशा में ये काम हुए हैं। नगरनिगम स्मार्टसिटी ने जनसहयोग से अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से अलग-अलग स्थानों पर वृक्षारोपण के काम किये हैं। ये सही है कि बिलासपुर के आसपास के कुछ नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्राम पंचायत को मिलाकर पिछली सरकार ने नगर निगम की सीमा में वृद्धि किया है। जो सीमावर्ती गांव नगर पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम में शामिल हुए हैं, वहां पर विकास के काम कम हुए थे। उन क्षेत्रों में उन कामों पर फोकस करके बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओ के लिये हमारी सरकार बनने के बाद हमने स्वीकृत किया है। और भी जो प्रस्ताव आते जायेंगे, क्रमश: स्वीकृत करते जायेंगे। अभी माननीय सदस्य ने मुक्तिधाम के लिये कहा है, इस बार हमने मुक्तिधाम के निर्माण को फोकस किया है। सभी नगरीय निकायों को राशि जारी कर रहे हैं। इनके सकरी क्षेत्र के लिये भी मुक्तिधाम का कोई प्रस्ताव आयेगा तो निश्चित रूप से परीक्षण करेंगे और विचार करके उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत् स्वीकृत कार्य</u>

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. (*क्र. 626) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के तहत् स्वीकृत कार्यों में से दिनांक 02 फरवरी, 2026 की स्थिति में पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ कार्यों की विकासखण्डवार ग्रामों के नाम सहित जानकारी देवें ? कार्य पूर्णता उपरांत किन-किन ग्रामों में इस योजना के अंतर्गत पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? जानकारी देवें ?

(ख) कण्डिका 'क' के स्वीकृत कार्यो में से विगत 02 वर्षों में किन-किन ग्रामों में धीमी गति से कार्य होने, गुणवत्ताहीन निर्माण होने, कार्य में अनियमितता बरतने आदि की शिकायतें विभाग/जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है या विभाग के संज्ञान/जानकारी में आयी है तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 02 फरवरी 2026 की स्थिति में जल जीवन मिशन योजना के स्वीकृत कार्यों मे से पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ कार्यो की विकासखण्डवार, ग्रामों के नाम, कार्य पूर्ण ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृत कार्यो में गुणवत्ताहीन निर्माण, कार्यो की धीमी गति, कार्यो में अनियमितता तथा अन्य प्रकार की शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप जो प्रश्न को लगातार लगाते थे, उसी प्रश्न को करने के लिए मैं खड़ी हूं और मेरे प्रश्न पर आपसे संरक्षण चाहती हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी और मेरे प्रश्न के उत्तर में जल जीवन मिशन योजना में 111 टंकी पूर्ण होने की जानकारी आई है, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहती हूं कि ये 111 टंकी पूर्ण हैं तो उसमें से कितने चालू हैं?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 214 योजनाएं स्वीकृत हैं, गावों की संख्या 210 है। जिसमें से बालोद विकासखंड के 89 गांव, गुरूर के 121 गांव शामिल हैं। इन 214 योजनाओं में से 102 योजनाएं पूर्ण हैं। इन 102 योजनाओं में कार्य पूर्णता के बाद 111 ग्रामों में जल की आपूर्ति की जा रही है और ये वर्तमान में स्थिति है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि 111 गावों में चालू हालत में है। मैं गांव में निरीक्षण की, मैं सभी जगह गई थी, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि 111 गावों में पूर्ण दिखा रहे हैं लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब है, किसी गांव में पानी टंकी में लीकेज है, किसी में पाइपलाइन टूट-फूट गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आपकी सरकार के समय कार्य किया होता तो इतना लीकेज नहीं होता।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, ये सरकार को ढाई साल पूरे होने को आ गए हैं, अब तो आप अपने हाथ मे ले लीजिए। मेरा ये कहना है कि कहीं भी टंकी पूर्ण रूप से नहीं चालू है। ये सिर्फ कागजी रूप में है, मेरे पास 111 गावों की लिस्ट है, उसमें डांडेसरा, करियाटोला, दानीटोला, बिच्छीबहरा गांव है, यहां कहीं भी पानी का आवागमन नहीं हो रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, रानीतराई में टंकी के खराब होने की शिकायत आई, हमने उस टंकी को डिसमेंटल किया है। नई टंकी के निर्माण का काम करेंगे। इसी तरह से सोसहपुर गांव का भी मामला आया, उस पर भी जो खराब था, उसे भी ठीक करने का काम किया है। 111 गावों में योजनाएं पूर्ण हैं, पेयजल आपूर्ति हो रही है। यदि उन 111 गावों में से किसी गांव में पानी नहीं आ रहा हो, मुझे जानकारी दें, मैं उनका परीक्षण जरूर करा लूंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यहां तो पूरे गांव हैं, मैं आपको लिस्ट दूंगी। आप पूर्ण की परिभाषा बता दीजिए कि पूर्ण की परिभाषा होती क्या है ? पूर्ण की परिभाषा बता दीजिए कि क्या होती है?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, जो स्वीकृत डी.पी.आर. है उसके अनुरूप जो काम हो गये हैं उन कामों को पूर्ण कहेंगे और पानी आ रहा है। हमने हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता के लिये उसके काम को सुचारू रूप से नीचे तक पहुंचाने के लिये अनेक कठोर-कठोर निर्णय लिये हैं और यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। यह तो नरेन्द्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके कारण इतनी बड़ी योजना आम लोगों को आजादी के बाद पहले किसी ने अब तक सोचा नहीं लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का और उस दिशा में, मैं पिछली सरकार में क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं करता लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उस योजना को सही दिशा में ले जाने के लिये पूरी ताकत लगाकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सारी योजनाओं को पूरा करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न केवल एक पाइंटेड प्रश्न है। मैं केवल यह कहना चाह रही हूं कि 111 गांव में आपके नल जल योजना का पानी ठीक से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं पहुंच रहा है। टंकी लीकेज है, कहीं पर पाईपलाईन फूटा है, कहीं पर नल का टोंटी नहीं है उसके लिये आप क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया है कि पिछले 2 वर्षों में धीमी गति से कार्य होने की 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, गुणवत्ताहीन काम होने की 8 शिकायतें हुईं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी। गुणवत्ताहीन मेरा दूसरा पाईट रहेगा, आप कृपया इसमें पहले जवाब दे दीजिये ।

श्री अरूण साव :- मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 111 गांव जहां जल आपूर्ति होने की बात हमने कही है, वहां यदि किसी गांव में नहीं हो रहा है। उसकी जानकारी दें, निश्चित रूप से परीक्षण करायेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। मैं इसकी लिस्ट माननीय मंत्री जी को दे दूंगी। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, अनियमितता बरते हैं, आपके पास जिसकी शिकायत पहुंची है उसके लिये आपने क्या कार्रवाई की, उसमें आपने क्या किया है ? आपको कितनी शिकायत मिली है, कितनी कार्रवाई हुई है, वह कितनी जगह का है ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 वर्षों में गुणवत्ताहीन काम की 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। टंकी में लीकेज उनको ठीक कराया है। मैंने अभी टंकी खराब होने की स्थिति के बारे में बताया कि रानीतराई गांव की टंकी हमने तोड़वाई है और भी कहीं पर कोई शिकायत आयेगी। आप बता दें कि यह गुणवत्ताहीन है, जांच करायेंगे, कार्रवाई करायेंगे ।

सभापति महोदय :- आप उसको भी बता दीजिये, लिखकर दे दीजिये । उमेश जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- हो गया न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय :- देखो, मंत्री जी ने दोनों बातें बता दीं। मंत्री जी ने आपको पूरा बता दिया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत गंभीर है। मेरे यहां मुजगहन, बासीन, दुबचेरा, कुलिया, रानीतराई, जैवरतला, दरबारी, नवागांव और सऊपुर । माननीय सभापति महोदय, मैं सऊपुर में गयी थी, वहां गांव वाले मेरे पास आये थे। गांव वाले आये। मेडम, टंकी लीकेज होत है, डामर पोत दे है, यह बात बोले । जब मैं वहां पर गयी तो वहां पर डामर के बदले लीकेज में जो केमिकल लगाते हैं, वह लगाया गया था। जब मैं वहां गयी तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

टंकी की जो सीढ़ी है वह पूरी जर्जर थी। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास टंकी गुणवत्ताहीन की यह फोटो भी है। सऊपर में लगातार शिकायत करने के बाद बासीन, दुबचेरा, जैवरतला, दरबारी, नवागांव लगातार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक वह टंकी उसी स्थिति में है। निमोरा में पानी टपक रहा है। मैं पटल पर रख दूंगी, निमोरा में टंकी से पानी टपक रहा है। माननीय सभापति महोदय, उसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? आप समय-सीमा निर्धारित कीजिये। क्या कार्रवाई हुई ? क्या ठेकेदार पर कार्रवाई हुई ? क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई जो उसमें संरक्षण दे रहे हैं? आप मुझे यह जानकारी दे दीजिये कि आप क्या कर रहे हैं?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो जानकारी आयी है, गुणवत्ताहीन काम हुआ है, उसकी जानकारी मुझे दे दें। निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से उसका परीक्षण करायेंगे और जो दोषी पाया जायेगा उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे ।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- हो गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक लास्ट पाइंटेड प्रश्न है कि जो आपके 99 अपूर्ण कार्य हैं उसके लिये आपने सभी में एक उत्तर बनाकर दे दिया है कि विभाग द्वारा कार्य गति बढ़ाने के लिये नोटिस जारी कर दिया है, कार्य वांछित गति से किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने स्वयं 99 जगह, मैंने बहुत सारी जगह में दौरा किया है, वहां पर कार्य आपके इसमें गति है बता रहे हैं लेकिन वहां पर कहीं कोई कार्य नहीं चल रहा है और जब मैंने ठेकेदार को बुलाया कि आप कार्य को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं तो ठेकेदरों का साफ कहना है।

श्री राजेश मूणत :- इसका ठेकेदरों से क्या लेना देना है? यह सब पिछली सरकार में ही हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अगर वहां पर काम नहीं हो रहा है तो मुझ उनसे काम करवाना पड़ रहा है। वहां आपके अधिकारी उनसे काम नहीं ले रहे हैं। उनका यह कहना है, मैं आपको उनका दर्द बता रही हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ठेकेदारों से काम लेती हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय चन्द्राकर जी, मैं आपको उनका दर्द बता रही हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ठेकेदारों से काम लेती हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उनका यह कहना है कि मैडम, हम 85 प्रतिशत काम कर चुके हैं, किन्तु हमको अभी तक पेमेण्ट नहीं हुआ है। (शेम-शेम की आवाज) अगर किसी के पास पेमण्ट नहीं रहेगा तो वह कैसे कार्य करेगा ? उन्होंने 85 प्रतिशत काम किया है। आप उन्हें 30 प्रतिशत काम का पेमेण्ट दे रहे हैं। इसमें तो सरकार है। आप सरकार लोग उन्हें पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं संगीता जी से कहना चाहता हूँ कि इसका टेण्डर कब हुआ ? आप इस पर पूरी डिबेट कर लीजिए। आप पूरे एक घण्टे की डिबेट कर लीजिए। इसका टेण्डर कब हुआ ? उसे किन लोगों ने लिया ?

सभापति महोदय :- अभी तो आपको बजट पर भी बोलना है।

श्री राजेश मूणत :- उसकी डी.पी.आर. किसने स्वीकृत की ? इसमें कितना बिल का एडवांस पेमेण्ट हुआ और इसमें क्यों नहीं हुआ ? तो यह किस-किस कार्यकाल में हुआ, आप इसके ऊपर पूरी चर्चा कर लीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोग 2 सालों से क्या कर रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- पूर्व की सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर यह हाल बनाकर रखा है। केवल बात करने से क्या होगा ?(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आपके मंत्री जी ने 2 साल में यहां सदन में 4 बार घोषणा की।

श्री राजेश मूणत :- पूर्व की आपकी सरकार ने क्या किया, आप यह बता दीजिए ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आपने 2 साल में यहां सदन में 4 बार घोषणा की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सभापति महोदय :- आप अंतिम प्रश्न कर लें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यही अंतिम प्रश्न कर रही हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपकी उदारता की बहुत-बहुत प्रशंसा है। हमने अपने संसदीय जीवन में इतना लम्बा प्रश्न नहीं सुना है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय चन्द्राकर जी, पूर्व में आपका प्रश्न भी आधे-एक घण्टे तक हुआ है। आप अपने प्रश्न में एक-एक घण्टे का समय लेते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी।

सभापति महोदय :- आप अंतिम प्रश्न कर लें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जो अब तक अपूर्ण हैं, आप उस कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने इस योजना की अवधि 2028 तक बढ़ायी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन योजनाओं के अनुरूप काम हो और नल के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें समय-सीमा निर्धारित करें।

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी आप प्रश्न कर लें। इसमें बहुत सारा प्रश्न हो गया है। आगे यही प्रश्न आना है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि 2 साल से विधान सभा में आपने इस सदन में कई बार घोषणा की है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, उनके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही हुई, आप यह जानकारी दे दीजिए ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, यह संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र का स्पेसिफिक प्रश्न है। माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, वह संजारी-बालोद विधान सभा से संबंधित नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह सदन का मामला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण साव :- माननीय सदस्य, आप प्रश्न लगाएं।मैं आपके एक-एक प्रश्न का उत्तर दूंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही हूँ कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे तो वहां पर काम वहीं का वहीं ठहरा रहेगा। वहां पानी लिकेज है और कहीं पर कोई काम नहीं चल रहा है। इसमें जितनी 99 जगहों पर कार्य अपूर्ण है, वहां पर पानी टपक रहा है। इसको मैं फोटो सहित पटल पर रखूंगी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, इस फोटो में पानी कहां दिख रहा है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, क्या आप उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे?

सभापति महोदय :- माननीय संगीता जी, माननीय आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मुझे समय-सीमा बता देंगे।

सभापति महोदय :- माननीय संगीता जी, आपने समय-सीमा की बात की है तो उन्होंने बता दिया है कि भारत सरकार ने इस योजना की अवधि 2028 तक बढ़ायी है। उसके पहले आपके क्षेत्र में कार्य पूरा करवा देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2047 तक आपके जल जीवन मिशन योजना का कार्य पूर्ण होगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इसी में एक प्वाईंटेड प्रश्न है। यह बालोद जिले का है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले सत्र में भी रोड रानी तराई की बात हुई थी, वह रोड रानी तराई ग्राम दंश झेल रहा है। वह आधे राजनांदगांव जिले और आधे बालोद जिले में आता है। राजनांदगांव जिले में वहां पर एक होटल के बाद लगातार पानी बहता है और वहां पान ठेले के बाद इधर पानी के पानी की सप्लाई नहीं है। मैंने आपसे बार-बार निवेदन किया था और आपने कहा कि हम उसमें जरूर विचार करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- बालोद में तीनों कांग्रेसी विधायक हैं। इसलिए वह स्थिति है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। आपके मन में जो भाव है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए बालोद में भेदभाव हो रहा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जो आप वह भाव पैदा कर रहे हैं। कांग्रेसी, भा.ज.पा. की बात है तो आप लोग भी पानी पीते हैं और हम लोग भी पानी पीते हैं। लेकिन जनता 2 साल बाद बताएगी कि आपको कहां से पानी पीना है। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि आप खरखरा से...।

श्री उमेश पटेल :- आपने मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया कि वह भेदभाव करते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यह बिल्कुल सच्चाई है कि बालोद जिले के साथ भेद-भाव होता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है, केवल बालोद का नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, रानीतराई का मामला है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें से आधा एरिया हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी के विधान सभा क्षेत्र में आता है और आधा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है । आपने कहा भी था । माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश भी दिया था, लेकिन अभी तक वहां के लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन योजना की ओर जरूर ध्यान देकर करवा दीजिए ।

सभापति महोदय :- आप उस ओर प्रयास करिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप वंदे मातरम् गाते हैं या नहीं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गाते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जोर से गाईए, सब काम हो जाएगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश में गिग वर्करों के लिये श्रम कानून

[श्रम]

3. (*क्र. 571) श्री अजय चंद्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रदेश में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट, रैपिडो (गिग वर्क) इस तरह की कितनी कंपनियां कार्यरत हैं ? इन कंपनियों को कार्य करने हेतु अनुमति देने की प्रक्रिया क्या है ? इन कंपनियों में कितने गिग वर्कर कार्यरत हैं? उनमें से छत्तीसगढ़ के कितने हैं? क्या इसके संबंध में कोई नियम-निर्देश हैं? (ख) क्या प्रश्नांक (क) गिग वर्करों की भर्ती हेतु शैक्षणिक या अन्य योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं? क्या इनके वेतन, श्रमावधि एवं सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता हेतु नियम-शर्ते लागू होती हैं? इसकी निगरानी करने के लिये क्या व्यवस्था है एवं किस स्तर के अधिकारी द्वारा इनकी देख-रेख की जाती है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) प्रदेश में श्रम विभाग अंतर्गत स्विगी, जोमैटो ब्लिंक इट, रेपिडो जैसे कंपनियाँ पंजीकृत नहीं है। उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) तथा कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस प्रकार की कंपनी पंजीकृत नहीं होने की जानकारी दी गयी है। उक्त कंपनियों के श्रम विभाग अंतर्गत पंजीयन नहीं होने के कारण इनमें कार्यरत गिग वर्कर की कुल संख्या तथा उनमें से छत्तीसगढ़ के गिग वर्करों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्रम विभाग द्वारा प्रवर्तित श्रम अधिनियम अंतर्गत उक्त कंपनियों को कार्य करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। (ख) गिग वर्करों की भर्ती हेतु शैक्षणिक या अन्य योग्यताएं, वेतन एवं समयावधि निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गिग एवं प्लेटफार्म वर्करों की सामाजिक सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी सीधे-साधे, सरल और बहुत ही सज्जन मंत्री महोदय हैं।

श्री उमेश पटेल :- लेकिन अभी आपने मंत्री जी के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि कुकर्म और कर्म से भी दशा निर्धारित होती है न। इसलिए मैंने कांग्रेसी कहा। वह भेदभाव के कारण नहीं कहा, कर्म-कुकर्म के कारण कहा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न है और मैं मंत्री जी का ध्यान गिग वर्कर्स पर चाहूंगा । प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय अधिनियम का हवाला दे दिया । मैं आपको एक लाईन से और अवगत कराऊंगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप भी सुनिएगा । इससे पहले मैंने आऊट सोर्सिंग कम्पनियों पर ध्यानाकर्षण लगाया था तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया, इसके लिए भी हमारे पास कोई नियम-कानून नहीं है । गिग वर्कर्स के लिए भी छत्तीसगढ़ में कोई नियम कानून नहीं है। एक मिनट की पृष्ठभूमि है । यदि इसको हम अधिनिमित कर दें तो छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका संरक्षण होगा । अभी तो उसका दोहन हो रहा है । कई लोग मर गए हैं, कई लोग जेल भेजे गए हैं और जो आऊटसोर्सिंग कम्पनियां हैं, वे ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, यह बड़ी गंभीर स्थिति है । अब आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर प्रश्न करूं, यह केन्द्रीय अधिनियम हैं, यह मत हो जाये । चूंकि मेरे प्रश्न के उत्तर में इसका उल्लेख है । आप यह बता दीजिए कि आपने उत्तर में 2020 का उल्लेख किया है तो उसको यदि आपने देखा होगा तो उसमें गिग वर्कर्स कौन सी श्रेणी में आएंगे । वे संगठित में आएंगे या असंगठित में आएंगे, यह आप मुझे बता दीजिए ।

श्री लखनलाल देवांगन :- सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही चिंतनीय प्रश्न किया है । निश्चित तौर पर यह चिन्ता का विषय है । उन्होंने इस विषय को उठाया है । जैसा कि वे पूछ रहे हैं कि गिग वर्कर्स संगठित में आएंगे या असंगठित में आएंगे ? अभी वे दोनों श्रेणी में नहीं आ रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बैठिए, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं । सभापति महोदय, प्रश्नोत्तरी में अधिनियम, 2020 का उल्लेख है । मैं आपको बता दूं कि इसके अधिनियम बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि आपने उसका उल्लेख किया है । अधिनियम नहीं बने हैं, उसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के लिए अनुकूलन करके क्या आप उस अधिनियम के तहत नियम बनाएंगे ? क्योंकि आप यह देख लीजिए कि लेबर करेंट टॉपिक है तो आप उसी अधिनियम के तहत उसी स्थिति में स्वीकार करके आप छत्तीसगढ़ में नियम बनाएंगे क्या ?

श्री लखनलाल देवांगन :- सभापति महोदय, अभी तीन वर्षों के लिए भारत सरकार ने 2020 में इसका नया अधिनियम है, जिसमें चार बोर्ड के रूप में है, उसमें नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में उन्होंने लिया है और 2025 में इसको प्रभावशील किया है, अभी इसके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नियम नहीं बने हैं । जैसे ही भारत सरकार के नियम बन जाएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हम लोग इस नियम का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे और इससे पहले छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, बाकी जैसे ही हमारी कमेटी बनी तो कमेटी अपना काम पूरा नहीं कर पायी । उसके बाद भी भारत सरकार के चार नये बोर्ड लागू हो गए और उसमें जैसे ही अधिनियम बनेगा, हम छत्तीसगढ़ में उसका अनुसरण करके हम लोग पालन करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक स्थिति मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । मेरे पास सभी नियम, राजपत्र, कांस्टीट्यूशन सब मौजूद हैं । भारत सरकार के द्वारा 2025 के नोटिफिकेशन इसलिए जारी किए गए क्योंकि भारत सरकार ने जो अधिनियम बनाए, उसके नियम नहीं बने हैं । जो नये अधिनियम बनाये हैं, उसके नियम नहीं बने हैं। नियम नहीं बने हैं इसलिए नियम बनते तक श्रम न्यायालय को ही सुनने का अधिकार दिया गया है, सिर्फ इतना ही नोटिफिकेशन में है। इससे ज्यादा नोटिफिकेशन में नहीं है। अब आप यदि उसके डिटेल में जायेंगे तो फिर वही हो जायेगा कि आपको उसी के आधार पर सुनना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि भारत देश के विभिन्न राज्यों ने इस सम्बन्ध में अपना अधिनियम और नियम, चाहे वह आऊट सोर्सिंग कम्पनी हो, चाहे गिग वर्कर्स हो, इसके बारे में नियम बना लिये हैं? इसलिए क्या आप अपना अधिनियम और नियम बनाने के बारे में विचार करेंगे क्या?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि भारत सरकार का अधिनियम, नियम बन रहा है। हम लोग उसके अनुसरण में छत्तीसगढ़ में भी उसका अनुसरण करेंगे और नियम बनायेंगे। आप भी काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। भारत सरकार का जो भी नियम बनते हैं, उसके अधीन ही नियम बनेंगे। बाकी मैंने पहले ही बताया है कि हमने एक समिति गठित किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इसीलिए संविधान का उदाहरण दिया, यह समवर्ती विषय है, समवर्ती सूची में है। हम समवर्ती सूची में आप अपने अधिनियम भी बना सकते हैं। यदि केन्द्र के अधिनियम आते हैं और यदि वह बेहतर होगा तो वह अपने आप ही लागू हो जायेगा, उसमें लागू नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन 2020 के अधिनियम के बाद, उसके नियम नहीं बने हैं। अभी यह तय नहीं है कि वह नियम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कब तक बनेंगे। जब तक नियम नहीं बनेंगे, उसके निर्देश नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ के बच्चें ऐसे ही शोषण के शिकार होते रहेंगे। मैं इस विषय पर लगातार दो साल से प्रश्न कर रहा हूं या विभिन्न अवसरों में इस ओर जा रहा हूं। इतने बड़े रोजगार के अवसर हैं, आप सुन लीजिये कि यह कितना गंभीर विषय है, छत्तीसगढ़ में कितनी आऊट सोर्सिंग कम्पनियां हैं, किसी को नहीं मालूम है। यहां कितने गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है। उनकी सेवा-शर्तें क्या हैं, किसी को नहीं मालूम है। अब चिंता की स्थिति यह है कि जो गिग वर्कर्स हैं, उसका कम्पनियों के मुकाबले यह हो रहा है कि हम 10 मिनट में सामान सप्लाई करेंगे। जो मानव अधिकार संगठन हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं कि 10 मिनट में कैसे सप्लाई होगा। ऐसी स्थिति में वर्कर्स मारे जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में चाहे वह आऊट सोर्सिंग से हो या गिग वर्कर्स हों, कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और कई लोग जेल की हवा खा चुके हैं। इस शोषण को रोकना निहायत ही जरूरी है। मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि यह समवर्ती टापिक है, समवर्ती टापिक में हम देश के विभिन्न राज्यों के अधिनियमों को बुलाकर यहां अपने परिवेश में लागू कर सकते हैं। आज की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कितनी कम्पनियां काम कर रही हैं, सरकार को यही मालूम नहीं है। इसलिए यह बहुत चिंता का विषय है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ कहें और कुछ करें। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चें जो उसके अधीन काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी। मैं प्रश्नकाल में ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। लेकिन यह एक चिंता का विषय है। दूसरे विषय में आपका उत्तर आ जाता है कि इसमें कानून नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है, हम बना रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के बच्चें शोषण के शिकार हो रहे हैं। इसलिए आप इसमें अपना खुद का अधिनियम बनायेंगे, उसके नियम-निर्देश बनायेंगे क्या ? यह आप मुझे बता दीजये ? क्या आप इस पर विचार करेंगे क्या?

सभापति महोदय, यदि विशेषज्ञ नहीं हैं, सक्षमता नहीं है तो उसके लिए संस्थाएं मौजूद हैं, जो नियम बना देंगी। यदि आप इच्छाशक्ति दिखायेंगे तो हम लोग मदद करेंगे। भारत सरकार का अधिनियम, नियम जिस दिन लागू होगा तो उस दिन वह अपने आप ही लागू हो जायेगा।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने इसके लिए समिति गठित किया था और यह प्रक्रिया में था, उसी बीच भारत सरकार ने 4 श्रम संहिता कोड लागू किया है। यह छत्तीसगढ़ में भी प्रक्रियाधीन है, जैसे ही हम लोगों का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिनियम, नियम आगे आयेगा तो निश्चित तौर पर इस पर काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि यह बड़ा चिंता का विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी प्रश्न।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, एक सेकेण्ड। मैं आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, फिर आप बोलियेगा।

डॉ. चरण दास महंत :- आपके पहले ही तो बोलना था।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके बाद नहीं बोल पाऊंगा, मेरा क्रम समाप्त हो जायेगा।।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, यह लखन लाल जी से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए आप ही कोई संतुष्टि की दवा दे दीजिये। बाकी कुछ संभव नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, संतुष्ट-असंतुष्ट का बिलकुल सवाल नहीं है। मुझे उनकी इफीसियेन्सी पर कोई संदेह नहीं है। मैंने आपका ध्यान इसीलिए चाहा कि इस देश में उदाहरण है, अनेक राज्यों ने अपने नियम, अधिनियम और नियम निर्देश बना लिये। या तो उसको मंगवा लें, अपने अनुकूल उसको बना लें या हम कब तक इंतज़ार करेंगे भारत सरकार ने जो दूसरी अधिसूचना जारी की है, अभी नियम बनने के अभाव में पुराने श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे, इस संबंध में इतनी ही अधिसूचना जारी हुई है । उस अधिनियम के लिए नियम कब तक बनेंगे, ये समयावधि अभी तय नहीं है । तब तक हम लोग क्या करेंगे? आउटसोर्सिंग में वही स्थिति है, गिग वर्कर्स में वही स्थिति है, तो छत्तीसगढ़ के बच्चे के लिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो माननीय मंत्री जी, मेरी बड़ी विनम्र आग्रह है कि राज्य विचार करे, इस देश में अधिनियम बनाने वालों की कमी नहीं है, जो आपने समिति बनाई थी, जरूरी नहीं है कि विशेषज्ञ लोग हों। काबिल लोग होंगे, मेरा किसी की काबिलियत पर आज आरोप-प्रत्यारोप का बिल्कुल विषय नहीं है। आप यह बोलिए कि रिटायर्ड जज को दे दीजिए, विधि सचिव को बोलिए, सीटिंग जज को बोलिए, आग्रह कर दीजिए कि आप इसमें अधिनियम बना दीजिए । तो यह एक इच्छा शक्ति का सवाल है और घोषणा करिए, हम अधिनियम बनाएंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि प्रक्रियाधीन है और भारत सरकार के श्रम संहिता में प्रक्रियाधीन है। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कई राज्यों ने बना दिया है, अभी किसी भी राज्य का नियम इनके लिए नहीं बना है। हम आपसे भी और विचार-विमर्श कर लेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपका सुझाव आएगा और नियम प्रक्रिया में रहेगा।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मान लो मैं इनकी बात को मान लूं, मैं सहमत नहीं हूं कि दूसरे राज्यों ने नहीं बनाया है, मैं दूसरे राज्यों का उदाहरण दे दूंगा, लेकिन यदि किसी ने नहीं बनाया है तो हम नहीं बनाएंगे, ये कोई उत्तर नहीं है। इसलिए चाहे तो आप बना सकते हैं । और प्रक्रियाधीन है सवाल है, तो भारत सरकार के पास वर्ष 2020 से लंबित है, उसके नियम अभी तक नहीं बने हैं । तो इसलिए समय अवधि और प्रक्रियाधीन का कोई अर्थ नहीं है, छत्तीसगढ़ के बच्चों को यदि ठीक करना है तो आप इच्छा शक्ति दिखाइए, यह मेरा आग्रह है । नहीं तो फिर कोई बात नहीं।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप जी।

जिला जांजगीर-चांपा में सी.एस.आर. मद से कराए गए कार्य

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (*क्र. 213) श्री ब्यास कश्यप : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जांजगीर-चांपा जिले में औद्योगिक इकाईयों द्वारा सीएसआर मद अंतर्गत विगत तीन वर्षो में कितनी राशि व्यय की गई है? इस राशि से कितने कार्य कराए गए हैं? प्रदायित राशि का ब्यौरा औद्योगिक संयंत्रवार प्रदान करें? (ख) सीएसआर मद से कराए गए कार्यो की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? (ग) क्या सीएसआर. मद से कार्यो के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाती है? यदि हां, तो विगत दो वर्षो में किन-किन जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी अनुसार जांजगीर-चांपा में औद्योगिक इकाईयों द्वारा सीएसआर मद अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कुल राशि 10,54,57,658 रुपये व्यय की गई है। इस राशि से कुल 47 कार्य कराए गए हैं। प्रदायित राशि का ब्यौरा औद्योगिक संयंत्रवार **संलग्न प्रपत्र** †[1] अनुसार है। (ख) कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में सीएसआर मद से कराए गए कार्यों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। जिला जांजगीर-चांपा में सीएसआर मद अंतर्गत स्वीकृत होने वाले कार्यों की सूची माह जुलाई, 2025 से जिले की वेबसाईट https://janjgir-champa.gov.in/en/notice_category/information-about construction-work पर सार्वजनिक रूप से अपलोड की जा रही है। (ग) कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी अनुसार सीएसआर मद से कार्यों के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाती है। विगत दो वर्षों में माननीया सांसद जांजगीर-चांपा के अनुशंसा से 04 कार्यों हेतु कुल राशि 25,00,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने वाणिज्य उद्योग मंत्री से जो जानकारी चाही थी, जानकारी आ चुकी है और मैंने जांजगीर-चांपा जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा सी.एस.आर. मद अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है, और इस राशि में कितने कार्य कराए गए हैं, संपादित राशि का ब्यौरा औद्योगिक संयंत्रवार प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो जानकारी आई है और इस जानकारी में ऐसे संयंत्र खास करके जो कि शासकीय हैं, एन.टी.पी.सी. (NTPC) या कि गेल इंडिया (GAIL India), अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना। परंतु हमारे जिले में भी और ऐसे बहुत से औद्योगिक घराने हैं, के.एस.के. (KSK) जो अब जे.एस.डब्ल्यू. (JSW) के नाम से या कि मध्य भारत पेपर मिल नहीं पी.आई.एलऋ (PIL) के नाम से ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। इनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए उतनी राशि प्रदान नहीं की गई है, और क्यों नहीं की गई है, इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र के सी.एस.आर. मद के बारे में पूछा है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 10 करोड़ 54 लाख 57 हजार

[1] † परिशिष्ट - ''एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

658 रुपया और जो-जो कार्य हुए हैं, उसकी सारी सूची उनको उपलब्ध करा दी गयी है कि कौन से कार्य हो चुके हैं, कौन से कार्य अपूर्ण है, कौन से काम अभी प्रारंभ हैं, ये सारी जानकारी सूची में उनको उपलब्ध करायी गयी है और सी.एस.आर. भारत सरकार के नियंत्रण में रहते हैं और सी.एस.आर. में खर्चा करने का प्रावधानित प्रक्रिया है, जिसके तहत सी.एस.आर. मद से खर्चा होता है और निश्चित तौर पर जो-जो वहां के क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण मांग करते हैं और भी अलग-अलग विभागों से मांग आता है, उसके अनुसार से वह कार्य पूर्ण होता है। माननीय विधायक जी जो पूछ रहे हैं, वहां के सांसद की अनुशंसा से, सांसद महोदय की अनुशंसा से भी कार्य हुए हैं। उनकी अनुशंसा से भी दो कार्य के लिए वह अनुशंसित किए हैं, वह प्रक्रियाधीन है, जल्दी उनकी भी अनुशंसा स्वीकृत होगी। निश्चित तौर पर सी.एस.आर. मद का पैसा निरंतर रूप से क्षेत्र के विकास में लगता है और विकास हो रहा है। हम लोग भी कोरबा में रहते हैं, वहां भी बहुत सारे औद्योगिक घराने हैं। हम ही सब लोगों से पूछकर ही सी.एस.आर. मद का काम होता है। उनका भी जो भी कहीं पर कुछ है, तो निश्चित तौर पर अनुशंसा करते रहें, उनके भी काम की स्वीकृति होगी।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जिला में CSR मद हेतु सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में जो प्रस्ताव आए थे, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता न देकर जिलाधिकारी यानी कलेक्टर महोदय द्वारा अपने ढंग से काम को बांट दिये गये हैं और कई काम ऐसे बांटे गए हैं, जो कि आज भी प्रारंभ नहीं हुए हैं। शहरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत भी को एजेंसी बनाकर काम प्रदान किये गये हैं। यह सूची में मेरे पास उपलब्ध है। जब माननीय कलेक्टर के महोदय के माध्यम से समिति बनती है, उसमें सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठकर जिस काम की अनुशंसा करते हैं, उन कामों के प्रति सूची क्यों नहीं भेजी जाती और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा अपने हिसाब से क्यों काम बांट दिए जाते हैं? आपने कहा है कि हमारे भी प्रस्ताव हैं। हम तो चाहते थे कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय विधायक हों, माननीय सांसद हों, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हों, जनपद पंचायत अध्यक्ष हों, वे सब बैठें और आपके पास जो राशि है, उस राशि को उनकी आवश्यकता के हिसाब से बांटा जाए। लेकिन ऐसे कई कार्य आए हैं, जो कि अभी अप्रारंभ हैं और उस राशि से अनावश्यक काम कराए गए हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। एक और बात है। जैसे हम DMF की राशि की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष गांव, अप्रत्यक्ष गांव की बात

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

आती है, उसी प्रकार से प्रत्येक औद्योगिक घरानों के ग्राम पंचायत की इकाइयों का एक निश्चित सर्कल तय रहता है। क्या उस सर्कल से बाहर जाकर काम देना भी न्यायोचित है? ऐसे बहुत सारे काम हैं, जिनकी माननीय सांसद महोदय ने भी अनुशंसा की है, चाहे वह ग्राम बिर्रा हो, कर्रा हो, नेगुडी हो, बरबसपुर हो, ये ग्राम सर्कल से 25-30 किलोमीटर दूर हैं। इन गांवों की सूची में नाम ही नहीं है, लेकिन उन गांवों के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ब्याज की राशि को बांट दिया गया है। क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि यह कैसे बांटा गया है? सर्वेसर्वा कलेक्टर महोदय ही हैं तो फिर समिति का क्या औचित्य?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि CSR मद का एक समिति बनी है। CSR मद का कोई समिति नहीं बनी है, DMF की जरूर समिति बनती है। CSR मद में उद्योग या तो वह स्वयं दे सकता है या किसी काम के लिए कलेक्टर के अनुशंसा पर भी काम होता है और अलग-अलग विभागों के माध्यम से भी काम होता है। कलेक्टर के पास जो राशि आती है, उसको कलेक्टर जांच कराता है कि काम कैसे गुणवत्ताविहीन हुआ, काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। कई कामों को जो उद्योगपति अपने हिसाब से काम देते हैं, उसको कलेक्टर भी जांच कराता है और उसकी जांच भारत सरकार के माध्यम से होती है। मैंने पहले ही कहा है कि राज्य शासन को CSR मद में हस्तक्षेप करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। बाकी कलेक्टर को उद्योग से जो राशि मिलती है, वह उस राशि को आवंटित करता है। उस राशि का देख-रेख पूरा कलेक्टर के नियंत्रण में होता है। आप जो कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत को कैसे काम दिया गया? ग्राम पंचायत को भी कलेक्टर काम काम दे सकते हैं। ग्राम पंचायत को भी 50 लाख तक का काम दिया जा सकता है।

श्री ब्यास कश्यप :- शहरी क्षेत्र में काम दिए गए हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, शहर में एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया है। शहर में ग्राम पंचायत एजेंसी बनेगी?

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक रखी गई थी। बैठक में जो प्रस्ताव मंगाए गए थे, उन प्रस्तावों का एक भी काम नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि कलेक्टर महोदय या सांसद महोदय की अनुशंसा पर काम हो रहे हैं तो जनता ने हमारे ऊपर भी भरोसा किया है, जनता ने हम लोगों को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चुनकर यहां अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। हमारी बातें कब रखी जाएंगी? जब आपने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका एक कार्य क्षेत्र रहता है, उतने प्रभावित गांव रहते हैं, प्रभावित गांवों पर ही काम देना है, लेकिन उस कार्य क्षेत्र से हटकर दूसरे गांवों में काम देने का क्या औचित्य है?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं रहता है। क्षेत्र के विकास और स्थिति को देख कर काम स्वीकृत किए जाते हैं और अनुशंसा सभी के लिए जाते हैं। अनुशंसा की प्राथमिकता के आधार पर काम की स्वीकृति होती है। माननीय विधायक जी के माध्यम से भी दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 करोड़ 69 लाख 30 हजार रुपये की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से सी.एस.आर. मद से काम कराए जाते हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- आप कृपया करके बता दीजिये कि ऐसे कौन से काम हैं, जिनकी मैंने अनुशंसा की? यह मुझे जानकार भी खुशी होगी, मुझे जनता को बताते बनेगा।

श्री लखनलाल देवांगन :- आपने जो अनुशंसा की है, वह यह है कि वाटर जोन स्पॉट, ग्राम पंचायत कुदरी में ओपन जिम, पेंटिंग समतलीकरण, पेचिंग कार्य, सी.सी. रोड, प्रतीक्षालय, सामुदायिक भवन निर्माण, आपका 1 करोड़ 30 हजार का एक प्रस्ताव है। दूसरा, कुदरी, बसंतपुर, लछनपुर, जर्वे, उसीबोड, उदयबंद, मड़वा, तेंदूभांठा, पाली, सरको, करमंदी, सिवनी, कन्हाईबंद, खोखसा सामुदायिक भवन, सी.सी.रोड, चबूतरा, पचरी निर्माण इत्यादि का 1 करोड़ 69 लाख का आपका प्रस्ताव है ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे प्रस्ताव पर सहमति बनेगी ? मैंने जो गांव चयन किया है वह अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत आने वाले प्रभावित गांव है, मैं उनसे बाहर नहीं जा रहा हूँ । आप इसकी घोषणा यही पर कर देते?

श्री लखनलाल देवांगन :- देखिये, मेरे को घोषणा करने का अधिकार नहीं है ।

श्री ब्यास कश्यप :- ठीक है, नहीं है तो अनुशंसा कर दीजिए?

श्री लखनलाल देवांगन :- आप कलेक्टर के साथ बैठता हूँ बोल रहे हैं तो कलेक्टर के साथ बैठकर विचार-विमर्श करके काम को करवाईयेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आपके पास जो प्रस्ताव आया है, वह कलेक्टर महोदय के द्वारा ही आया है । आपने इसके पहले जिस बात को स्वीकार किया है, 10 करोड़ की राशि में से अधिकांश काम अप्रारंभ है, मैं तो चाहूँगा कि आप उन कामों को रोक दीजिए । वहां नेशनल हाईवे और फोरलेन बनने का है, वहां गेट निर्माण का था और वहां काम चालू नहीं हो पाया है। आप उसका उपयोग दूसरे कार्यों में कर लीजिए, ताकि गांव के विकास में काम आ जायेगा । शासकीय छोड़ कोई भी प्रायवेट, जितने भी औद्योगिक घराने हैं, उनके द्वारा एक नया पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है, मैं माननीय सभापति महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पूर्व में डॉ.रमन सिंह जी की सरकार के समय जांजगीर में सी.एस.आर. मद से मोदी की गारंटी योजना के अंतर्गत इंजिनियरिंग कॉलेज के लिये प्रस्ताव था...।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक क्वेश्चन 15-15 मिनट लगा रहे हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, आपकी भी बारी आयेगी । हमको तो कभी-कभार मौका मिलता है । मैं छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह करूँगा कि मोदी जी की गारंटी है कि भविष्य में इंजिनियरिंग कॉलेज हो, वहां पॉलिटेक्नीक कॉलेज संचालित है, आप पॉलिटेक्नीक कॉलेज को अपग्रेड करने के लिये आप उसको भी शामिल कर लीजिए । आपके पास चार-पांच काम ऐसे हैं ताकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाये। सी.एस.आर. से दो करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है, पैसा देकर जमीन संरक्षित है, उसके बाद भी इस प्रकार से हो रहा है ? सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय की इस पर कृपा बने, मैं यही कहना चाहता हूँ ।

श्री लखनलाल देवांगन :- चलिये, धन्यवाद ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी । इसी विषय में...।

श्री भूपेश बघेल :- अनुज शर्मा जी, आप यहीं तक सीमित रहें, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके बारे में थोड़ा कहना था । सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं कलेक्टर को निर्देश नहीं दे सकता और कलेक्टर के साथ बैठ जाईये। हम लोग यदि कलेक्टर के पास बैठते तो फिर यहां क्यों बैठे हैं ? जब सारा काम कलेक्टर को ही करना है, आप निर्देश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते तो मंत्री किस बात के लिये बने हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश जी स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने घोषणा करने की बात की है, मैं उनको घोषणा नहीं करता हूँ बोला है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- निर्देश नहीं दे सकता बोले हो । घोषणा करोगे तो एक्जिक्यूट करने की बाध्यता है । इसे कलेक्टर कैसे नहीं करेगा?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- रिकार्ड निकालकर दिखवा लीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी बोलेंगे तो कलेक्टर कैसे नहीं करेगा?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पूरे प्रदेश में कलेक्टर ही चला रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- मतलब यह है कि आपका कलेक्टर पर कंट्रोल नहीं है?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ग्राम पंचायत को शहर में एजेंसी बनाया गया है, जबकि ग्राम पंचायत को शहर में एजेंसी नहीं बनाया जा सकता ? सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी उसमें कार्यवाही करेंगे क्या ।

श्री राघवेन्द्र सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक प्वाइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। आपके विभाग द्वारा ही 22-3-2022 का एक पत्र है कि जितने जनप्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्र के हैं, कलेक्टर उनकी एक बैठक बुलायेगा, जांजगीर-चांपा में कितनी बार यह बैठक बुलाई गई और हमारे जिले में ५ विधायक कांग्रेस के हैं, आप ही के जवाब में आया है कि उनको प्राथमिकता देना है, कितने काम आज तक स्वीकृत किये हैं, आप यह बता दीजिए ? अप्रैल खत्म होने को है, कितने काम कांग्रेस के विधायकों की अनुशंसा से स्वीकृत हुये हैं और आपके विभाग के निर्देशानुसार मीटिंग कितनी बार हुई है?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, उनके कई कामों की स्वीकृति हुई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कितने विधायकों से ? ये प्रश्न में नहीं है। माननीय ब्यास जी ने जो प्रश्न लगाया है, उनकी जो अनुशंसा है, मैंने उसको विस्तृत रूप से बताया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, आपके जवाब में है कि सी.एस.आर. मद के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाती है, हमारा सीधा आरोप है कि वहां पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखन लाल देवांगन :- सभी जगह स्थानीय जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया जाता है। मैंने भी पहले उदाहरण के रूप में...। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, नहीं दिया जा रहा है, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- नहीं दिया जा रहा है। आप दिया जा रहा है बोल रहे हैं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- नहीं दिया जाता है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, आप आश्वासन दे दीजिए कि हम लोगों को दिया जाएगा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, गांव के काम ला शहर में आ के करत हे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- डॉ. चरणदास महंत।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी आप आश्वासन दे दीजिए कि इन लोगों का काम प्राथमिकता में करायेंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, विधायकों का सुनिश्चित किया जाए कि सी.एस.आर. मद में से इतना दिया जाएगा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, विधायक की अनुशंसा जरूरी करिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी एक आश्वासन तो दे दीजिए।

प्रश्न संख्या 05 (*क्र. 603):- xx xx

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश में एस.टी.पी. निर्माण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

6. (*क्र. 467) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कुल कितने एस.टी.पी. चालू हालत में हैं? कब से चालू हैं? वास्तविक ट्रीटमेन्ट कैपेसिटी कितनी है? कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है? स्थान का नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी बतावें? (ख) प्रदेश में कितने एस.टी.पी. निर्माणाधीन हैं? कब से निर्माणाधीन हैं? अनुबंध के अनुसार निर्माण पूर्णता तिथि क्या है? कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई थी? कितनी व्यय हुई? कितनी शेष है? निर्माण की भौतिक स्थिति क्या है? निर्माण में विलम्ब को कारण सहित एस.टी.पी. निर्माण स्थल का नाम एवं एस.टी.पी. की पृथक-पृथक क्षमता सहित जानकारी देवें? (ग) कितनी क्षमता के कितने एस.टी.पी. प्रदेश में स्वीकृति प्रक्रिया में कब से हैं? वर्तमान में क्या स्थिति है? कितनी राशि प्रस्तावित है? कितने कार्य प्रारंभ हो गए? कितनों का कार्य प्रारंभ होना शेष है? स्थान का नाम, क्षमता, राशि सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें?

(घ) प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के तरल अपशिष्ट को नदियों में प्रवाहित करने की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) प्रदेश के 12 नगरीय निकायों में संचालित 21 एस.टी.पी. का विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र-'अ'[22] अनुसार है। (ख) प्रदेश में निर्माणाधीन 33 एस.टी.पी. की विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) राज्य के 68 नगरीय निकायों में 96 एस.टी.पी. परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति, उनके वर्तमान स्थिति एवं स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र-'स' अनुसार है। प्रगतिरत् एवं अप्रारंभ कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (घ) प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के तरल अपशिष्ट को नदियों में प्रवाहित करने की रोकथाम हेतु मिशन अमृत 2.0 योजना अंतर्गत 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले (जनगणना 2011 अनुसार) 05 नगरीय निकायों एवं स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत 02 नगरीय निकायों में एस.टी.पी. का निर्माण किया जा रहा है तथा 01 लाख से कम जनसंख्या (जनसंख्या 2011 अनुसार) वाले 72 नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

[22] परिशिष्ट ''दो''

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

2.0 के अनुपचारित जल प्रबंधन घटक अंतर्गत एस.टी.पी. निर्माण (इन्टरसेप्शन एवं डायवर्सन ड्रेन सहित) का कार्य किया जा रहा है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र-'ब' एवं 'स' अनुसार है।

डॉ. चरणदास महंत :- आदरणीय सभापति महोदय, हमारे साथियों ने पर्याप्त समय ले लिया, मेरा प्रश्न बहुत लंबा था, मैं इसको आधा कर देता हूं। आप समझिए, आप विद्वान मंत्री हैं। माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा था कि प्रदेश में कितने एस.टी.पी. लगे हैं। आपने मुझे जवाब दिया कि 18 एस.टी.पी. लगे हैं और रात में संशोधन आ गया कि 21 एस.टी.पी. लगे हैं। फिर मैं देख रहा हूं कि 22 जनवरी, 2026 को विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आपके विभाग ने ये कहा है कि 24 एस.टी.पी. बने हैं। 21 और 24 में से कौन सा सही है, यह बता दीजिए तो फिर मैं उस हिसाब से आपसे प्रश्न करूंगा।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि बाद में संशोधित उत्तर सदन में सभी सदस्यों को माननीय विधान सभा ने उपलब्ध कराया है। 12 निकायों में 21 एस.टी.पी. संचालित है। उनकी क्षमता उनका विवरण कहां पर हैं, कैसे हैं, ये सारा बताया है। अभी जो संख्या के बारे में बात आई है, वह नगरीय निकायों में नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नहीं है, वह नया रायपुर में बना है, वह आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आंकड़े में वह अंतर आ रहा है। आपको विस्तृत उत्तर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार केन्द्र सरकार मिलकर एस.टी.पी. के निर्माण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। वर्तमान में 12 स्थानों पर 12 नगरीय निकायों में 21 एस.टी.पी. स्वीकृत है, जिनकी क्षमता 402.60 एम.एल.डी. है जो सभी संचालित है। 16 नगरीय निकाय में 33 एस.टी.पी. के निर्माण प्रक्रिया चल रही है जिसकी क्षमता 366.50 एम.एल.डी. की है, जो 68 नगरीय निकाय हैं, उनमें 96 एस.टी.पी. के निर्माण के लिए अलग-अलग स्टेज में प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, डी.पी.आर. आदि बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसकी क्षमता कुल मिलाकर 179.93 एम.एल.डी. है। आज की स्थिति में 949.03 एम.एल.डी. क्षमता के लिए काम चल रहा है। शेष 101 नगरीय निकाय बचते हैं, उनके लिए कार्ययोजना बनाने का काम चल रहा है। निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन की अलग-अलग योजनाएं हैं, उसमें सीवरेज का वॉटर, गंदा पानी, सेप्टिक टैंक का पानी है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमने पुख्ता योजना तैयार की है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, सौभाग्य से इन्होंने सक्ती में एक एस.टी.पी. 7 करोड 49 लाख 83 हजार की दी है, जुलाई में मैंने पूछा था कि आप कौन सी स्थिति में है। इन्होंने बताया कि निविदा प्रक्रियाधीन है। फिर मैंने दिसंबर में विधान सभा प्रश्न के माध्यम से पूछा तो भी आपने बताया कि निविदा प्रक्रियाधीन है। दो साल बाद मैं फिर पूछ रहा हूं और यह तीसरी बार है कि मैं पुन: विधान सभा में इस प्रश्न को पूछ रहा हूं कि एस.टी.पी. की क्या स्थिति है? आपने पिछली बार भी कहा था कि निविदा प्रक्रियाधीन है। आपके अधिकारियों ने एन.जी.टी. को रिपोर्ट भेज दी है और वह बोलते हैं कि एस.टी.पी. चालू है। आप इतना बता दीजिये कि यह प्रक्रियाधीन है या चालू है?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि सक्ती में 1 एस.टी.पी. निर्माण 4 एम.एल.डी. क्षमता की 7 करोड़ 49 लाख 87 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 15.03.2023 को हुई थी। पहली निविदा दिनांक 08.08.2023 को आमंत्रित की गई। फिर हमारी सरकार बनने के बाद उस समय जो काम प्रारंभ नहीं हुए थे, उन सब कामों की समीक्षा के लिए उसके आगे की कार्यवाही रोकी गई और उसके बाद दिनांक 03.01.2025 को फिर से स्वीकृति प्राप्त हुई। दिनांक 17.01.2025 को निविदा जारी की गई। उसमें 3 फर्मों द्वारा भाग लिया गया। न्यूनतम निविदा दर 66.50 प्रतिशत बहुत अधिक होने से उस निविदा को निरस्त किया गया। यही स्थिति तीसरी निविदा में हुई। 64.96 प्रतिशत अधिक दर पर निविदा भरी गई और उसी तरह से अभी जब चतुर्थ निविदा हुई तो निविदाकार ने 9.99 प्रतिशत अधिक दर की निविदा भरी, लेकिन बाद में उसने एक पत्र लिखा कि मेरे से यह गलती हो गई थी। उन्होंने इस तरह से उस टेण्डर को withdraw कर लिया। अब विभाग ने इस बात को लगातार देखा कि यह रेट क्यों नहीं आ रहा है तो फिर हम उसकी टेक्नोलॉजी को चेंज करके नये सिरे से उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से आप और जानकारी मंगवा लीजिए, क्योंकि हर बार आपके विभाग से गलत-गलत उत्तर आता है। तीन विधान सभा सत्रों में गलत उत्तर आये और चौथी बार आपने स्वयं सच्चाई को स्वीकार किया। आपकी सरकार आई तो जितने भी काम शुरू नहीं हुए थे, उन सब कामों को आपने निरस्त कर दिया और आपने फाइल भी मंगवा ली और फाइल में चेंजिंग भी कर दी। फिर इधर-उधर से किसी बहाने से वह स्वीकृत हुआ तो आपने कह दिया कि अब 34 प्रतिशत ज्यादा है, इसलिए आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसको कैन्सिल कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि 9 प्रतिशत कम रेट भरा है तो उसको भी आपने कैन्सिल कर दिया। निविदा प्रक्रिया कितने दिन तक चलती है, निर्माण कितने साल में होता है तो मैं यह समझता हूं कि इन सबके लिए जवाबदार आपका चीफ इंजीनियर है, जो यहां पर बैठा हुआ है। आप एन.जी.टी. को गलत जानकारी देते हैं। जो बंद है, खराब है, निविदा चल रही है, उसको आप कह देते हैं कि चालू है क्योंकि जब वहां से बत्ती पड़ती है तो वह संभल नहीं पाते हैं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि यह जो गुमराह करने वाले आपके अधिकारी बैठे हैं, उनके लिए किस प्रकार का ईनाम या सजा का प्रावधान है?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कामों को निरस्त नहीं किया था। जो अप्रारंभ काम थे, उसकी हमने समीक्षा की है। उन कामों की आवश्यकता है या नहीं है और जिन कामों की आवश्यकता होती है, उन सब कामों को स्वीकृति देते हैं। यह महत्वपूर्ण काम है, इसलिए हमने इस काम को भी स्वीकृति दी है। हमने निविदा जारी की है और हम निविदा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 35 प्रतिशत नहीं कहा। last में तीसरी निविदा में जो रेट आई थी, वह 64.96 प्रतिशत थी। चौथी निविदा में निविदाकार ने भरा तो 9.99 प्रतिशत था, परंतु वह पत्र लिखता है कि मैंने गलती से यह रेट लिख दिया है। मैं इतने में कभी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नई टेक्नोलॉजी आई है और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इस काम को आगे बढ़ायेंगे। हम प्रतिबद्धता है। हम जब लगातार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं तो वह माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का क्षेत्र है और सक्ती हमारा जिला मुख्यालय है तो निश्चित रूप से हम गंभीर हैं और जहां तक एन.जी.टी. में गलत जानकारी भेजने का मामला है तो निश्चित रूप से मैं इसकी जानकारी लूंगा और यदि गलत जानकारी भेजी गई होगी तो इस पर निश्चित रूप से परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, 5 मिनट बचा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके रायपुर नगर निगम में चंदनीडीह में एस.टी.पी. स्वीकृत है और आपने उसकी क्षमता 75 एम.एल.डी. बताई है, जिसमें 51 एम.एल.डी. उपयोग हो रहा है । इसी तरह यह कार्य पूरा सफल हो गया, ऐसा आपके विभाग से उत्तर मिला था। यह 82 करोड़ का काम था और अभी भी सीवरेज से गंदा पानी और जहरीला पानी पूर्ण रूप से निकल रहा है। ऐसे कामों के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं ? क्या आप उसके लिए इनाम घोषित करने वाले हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- मंत्री जी, इसको सुनिश्चित करा दें, काम जल्दी हो जाए, इनका आशय यही है। यह बार-बार बढ़ रहा है, वह काम जल्दी हो जाए तो काम आ जाएगा।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गंभीर हैं और इसलिए जब चौथी बार टेंडर हुआ..।

सभापति महोदय :- चलिए, राजेश मूणत जी।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं एक और प्वाईंट बता देता हूं। मेरे ही क्षेत्र के चांपा में आपने एस.टी.पी. की क्षमता 5.5 एम.एल.डी. कही थी, आज वह मात्र 0.75 एम.एल.डी. पानी दे रहा है। मतलब आपने जितनी क्षमता का बनाया था, वह उसका 15 प्रतिशत पानी दे रहा है। इस तरह से पूरे प्रदेश में क्षमताविहीन काम हुए हैं। अब आप यह मत कह दीजिएगा कि यह हमारे समय का काम है। ऐसे कामों के लिए मैं आपको किसे सस्पेंड करने के लिए कहूं कि आप थोड़ा सोचें? यह शांति पूर्वक प्रश्न है।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी क्षमता ही नहीं है। उतने सीवरेज का वाटर नहीं आ रहा होगा, इन कारणों से पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा होगा। इसके अलग-अलग कारण होते हैं और किस कैपेसिटी में उसके टेक्निकल निर्माण में या उसकी क्षमता ही नहीं..।

सभापति महोदय :- क्या राजेश मूणत जी को पुकारें ? उसमें 4-5 प्रश्न हो जायेंगे।

श्री अरूण साव :- जितनी क्षमता और एस.टी.पी. की जो प्लानिंग है, मैंने आपको ...।

सभापति महोदय :- एक प्रश्न हो जाएगा। राजेश मूणत जी।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति, मैं थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूं कि जो एस.टी.पी. का निर्माण करते हैं, उसको आने वाले समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करते हैं कि धीरे-धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो वह पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को ही मैच करे इसलिए अधिक क्षमता के एस.टी.पी. का निर्माण करते हैं। मैंने आने वाले कई सालों का पूरा डाटा बताया है।

सभापति महोदय :- ठीक है। माननीय राजेश मूणत जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, आधा मिनट। आप देख लीजिएगा कि यह चांपा में जो बना हुआ है, उसमें जहां मुहाने से पानी निकलता है, उसको बंद कर दिया गया है। शायद वहां मंदिर है या जो कुछ भी है इसलिए उसकी क्षमता नहीं बढ़ पा रही है तो आप मुहाने को खोलने के लिए बोल दीजिए। यह बहुत छोटा-सा काम है।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, निश्चित रूप से माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है, मैं इसमें संज्ञान लेकर अवश्य कार्यवाही करूंगा।

<u>चिंगरी तथा पीहर नाले का दूषित पानी खारून नदी में आने से रोकने हेतु किए गए उपाय</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (*क्र. 45) श्री राजेश मूणत:- क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सत्य है खारून नदी के पास 81.88 करोड़ रुपये व्यय कर 75 एम.एल.डी. क्षमता के घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने के बाद भी चिंगरी तथा पीहर नाले से आ रहा गंदा पानी नदी के निर्मल जल को प्रदूषित कर रहा है? यदि हां तो क्यों तथा इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये गए? (ख) चिंगरी तथा पीहर नाले से आ रहे गंदे तथा दूषित पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए नगर निगम रायपुर द्वारा रुपये 11 करोड़ की कार्य योजना नगरीय प्रशासन विकास विभाग को पिछले 1 वर्षों से भेजे जाने के बाद भी स्वीकृति हेतु लंबित है? यदि हां क्योंग तथा स्वीगकृति कब तक दी जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हॉ। खारून नदी के पास 81.88 करोड़ रुपये व्यय कर 75 एम.एल.डी. क्षमता के घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) का निर्माण किया गया है जो कि पूर्ण रूप से क्रियाशील है। चिंगरी नाला का दूषित जल नाले में बनाये गये पिकअप वियर से ओवर फ्लो होकर नदी में प्रवाहित हो जाता है। चिंगरी नाला का लाईनिंग तथा अप्रोच मार्ग नहीं होने से शिल्ट सफाई की समस्या, वियर की कम ऊंचाई तथा वृहद मात्रा में प्लास्टिक/सॉलिड वेस्ट प्रवाहित होकर पिकअप वियर के मुहाने को बाधित करने से ओवर फ्लो की स्थिति निर्मित हो रही है। इस हेतु मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन कर प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। (ख)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चिंगरी तथा पीहर नाले से आ रहे गंदे तथा दूषित पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए नगर निगम रायपुर द्वारा रूपये 11 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गयी है। उक्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुक्रम में नगर पालिक निगम रायपुर से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद और नेता जी का भी धन्यवाद। मेरा प्रश्न सीधे रायपुर की खारून नदी को लेकर है। माननीय नेताजी का प्रश्न एस.टी.पी. को लेकर था। क्या खारून नदी के अंदर एस.टी.पी. का गंदा पानी मिल रहा है और इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है ? रायपुर शहर की पूरी जनता, मुख्यमंत्री जी, सभापति और पूरा मंत्रिमंडल खारून का पानी पीता है। जहां पर ऑलरेडी सरकारी जगह थी, 7 एकड़ सरकारी जगह होने के बाद भी 8 कि.मी. दूर जाकर एस.टी.पी. का निर्माण किया गया। डी.पी.आर. किसने बनाया ? किसने स्थान को चिन्हित किया? आज भी खारून के अंदर वह गंदा पानी मिल रहा है। उसमें किस अधिकारी की रिस्पांसिबिलिटी है? मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि क्या आप उसको सुनिश्चित करेंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जिस एस.टी.पी. की बात कर रहे हैं, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति 28.11.2017 को जारी हुई थी और इसकी तकनीकी स्वीकृति एवं आगे की कार्रवाई नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में..।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि गंदे पानी रोकने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग की कोई योजना है तो बता दें ? कुल 30 सेकंड बाकी हैं। यह राजधानी का विषय है।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, निश्चित रूप से इसके लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। समिति ने परीक्षण कर लिया है और परीक्षण करके नगर निगम को ...।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं खुद तीन महीने से कमिश्नर से लेकर सब जगह घूमकर आ गया हूं। रायपुर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है। मैं इससे ज्यादा आपको और क्या कह सकता हूँ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- यही तो विकसित भारत है।

श्री राजेश मूणत :- क्या आप उस गंदे पानी को रोकेंगे?

श्री अरूण साव :- हम आपकी गंभीरता से वाकिफ है और इसलिए हमने कमेटी बना ली है। जैसे ही नगर निगम का प्रस्ताव आयेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, समिति कुछ नहीं कर रही है। महापौर और कमिश्नर चले गये। सिर्फ कागजों में समिति बनने से क्या रायपुर की जनता को शुद्ध पानी मिल जायेगा?

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 12.00 बजे **<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>**

01. अधिसूचना क्रमांक

(i) 112/सीएसईआरसी/2025, दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (पांचवा संशोधन), 2025 तथा

(ii) 113/सीएसईआरसी/2025, दिनांक 20 नवम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्ययप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) 112/सीएसईआरसी/2025, दिनांक 22 अगस्त, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (पांचवा संशोधन), 2025 तथा

(ii) 113/सीएसईआरसी/2025, दिनांक 20 नवम्बार, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 पटल पर रखता हूं।

02. छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूं।

03. अधिसूचना क्रमांक अधिसूचना क्रमांक रूल-5/107/2025-ट्रांसपोर्ट, दिनांक 2 जनवरी 2026

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

परिवहन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल-5/107/2025-ट्रांसपोर्ट, दिनांक 2 जनवरी 2026 पटल पर रखता हूं।

04. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2014) तथा छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2014) तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 पटल पर रखता हूं।

05. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-25 (दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-25 (दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक) पटल पर रखता हूं।

06. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अनुसूचित जाति विकास मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) पटल पर रखता हूं।

समय : 12.03 बजे

नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा जाना

सभापति महोदय :- नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय : 12.04 बजे

नियम 267 ''क'' के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

सभापति महोदय :- नियम 267 ''क'' के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, नियम 267 ''क'' के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखता हूं।

समय 12.04 बजे

राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

सभापति महोदय :- षष्ठम् विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर,2025 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से 3 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- षष्ठम् विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से 3 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

पृच्छा

सभापति महोदय :- शून्यकाल। जिस माननीय सदस्य को मैं अनुमति दूंगा, सभापति महोदय वह जनहित में अपनी बात को रखेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा के कुरूर थाना के अंतर्गत मिरीहटोला निवासी है। पुराणिक जोशी नाम के जो अपने घर में मेहमाननवाजी के तहत् वह अपने घर में शराब का सेवन कर रहा था, उसी बीच 3 आरक्षक आते हैं और उनको पकड़कर थाना ले जाते हैं और थाना में ले जाकर उनको दबावपूर्ण ढंग से 30,000 रुपये की मांग की जाती है। माननीय सभापति महोदय, 30,000 रुपये के बदले वह घर में आता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, 25,000 रुपये की व्यवस्था करके उनको देता है, उसके बाद वह दिनभर लोगों के पास घूमता है, रोता है, बिलखता है और रात को, यह 21 तारीख की बात है। वह 22 तारीख की रात को सुसाईड कर लेता है। (शेम-शेम की आवाज) माननीय सभापति महोदय, यह गंभीर विषय है और इसमें तुरंत तत्काल 3 आरक्षक को निलंबित किया जाये ।

सभापति महोदय :- आपने इसमें कोई सूचना दी है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी ।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया है।

सभापति महोदय :- हो गया, ठीक है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धन्यवाद ।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति महोदय, महासमुंद जिले के सराईपाली तहसील के अंतर्गत ग्राम जंगलबेड़हा में मैसर्स गोदावरी पावर प्लांट इस्पात लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 102 हैक्टेयर भूमि सौलर परियोजना बर लीज में दिये गे हावय लेकिन परियोजना के निर्माण कार्य बिना ग्राम सभा के वैधानिक सहमति के ही प्रारंभ कर दिये गे है, जो कि कानूनन अवैध हावय। विधानसभा में तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में माननीय मंत्री महोदय हा जवाब दे रिहिस है कि कोनो भी प्रकार के ग्राम सभा के अनुमति नइ लिये गे है। संबंधित संस्था ला ग्राम सभा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी तक के जारी नइ करे गे है, नइ मिल पाये हावय। मोर जंगलबेडहा क्षेत्र हर काबर कि अनुसूचित क्षेत्र मा आथे और अनुसूचित क्षेत्र मा भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन मा ग्राम सभा सर्वोपरि होथे और ओमन के अनुमति के बिना कोनों भी परियोजना वैध नइ माना जा सकय ऐखर बावजूद स्थल में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिये गे हावय। जो कि संविधान पंचायत अधिनियम अऊ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खुला उल्लंघन हावय । लीज डीड के कंडिका-9 मा तथा कलेक्टर महासमुंद के राजस्व आदेश ई-कोर्ट प्रकरण वर्ष 2024-2025 मा स्पष्ट प्रावधान है कि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कोनो भी पेड़ के कटाई नइ करे जा सकय ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अगर अइसे होथे, पेड़ बिना अनुमति के काटे गे हे ता लीज निरस्त हो जही, अइसे कंडिका में लिखाय हावय। ऐखर बावजूद ये परियोजना स्थल मा बड़े पैमाना मा पेड़ के अवैध कटाई होय हे, जेखर पुस्टि तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन में होय हावय, ये कृत्य हर भारतीय वन अधिनियम 1927 वन संरक्षण अधिनियम ।

सभापति महोदय :- वह संक्षेप में आ गया न। पूरा पढ़ने का नहीं है, आपकी बात आ गयी । दलेश्वर साहू जी ।

श्रीमती चातुरीनंद :- माननीय सभापति महोदय, मोर बात पूरा नइ होय है।

सभापति महोदय :- मैंने सुन लिया न, मैंने आपकी बात सुन ली। यह आधा मिनट, एक मिनट का रहता है।

श्रीमती चातुरीनंद :- माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट । बिना अनुमति के अवैध कटाई होए है।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं। आपने इसमें कोई सूचना दी होगी न ?

श्रीमती चातुरीनंद :- हां, जी ।

सभापति महोदय :- हां, तो ठीक है न। उसमें विचार कर लेंगे ।

श्रीमती चातुरीनंद :- माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहत हंओं कि का विधानसभा स्तरीय एक जांच टीम के गठन होही? मैं मांग करत हंओं कि विधानसभा स्तरीय जांच टीम के गठन होवए ।

सभापति महोदय :- शून्यकाल में आपने अपनी बात रख दी है, उस पर आगे...।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, यह पूरे प्रदेश में ग्राम पटेल को 3 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है, मैंने इसका ध्यानाकर्षण दिया है। दूसरा, शहरी आजीविका मिशन से जुड़े हुए कर्मचारियों को 6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है। कृपया इसको देख लें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जांजगीर-चांपा जिले में हुई धान खरीदी और उस धान खरीदी में कई लोगों का धान नहीं खरीदने के कारण वह कुछ काम किये जैसे कि टॉवर पर चढ़ जाना, आत्महत्या का प्रयास करना, उनके ऊपर एफ.आई.आर. होना, उनका धान नहीं बिकना और एफ.आई.आर. होकर जेल में बंद कर देना और कई किसान अभी भी सेवा सहकारी समिति के गेट पर, अपने धान को बिक्री करने के लिये गेट पर बैठे हुए हैं उनको थाने में अंदर कर दिया गया है तो आग्रह है कि धान खरीदी के विषय में कम से कम हमारे जिले में ही साढ़े 6 करोड़ से अधिक की राशि सरकार को, जो ऋण लिये हैं उनको लेना है तो कम से कम पूरे प्रदेश में ऐसे जो किसान कर्जदार हैं, उन किसानों के धान को लेने के लिए कृपा करें। मैं लिंकिंग के धान की बात कह रहा हूँ ताकि वह ऋण से मुक्त हो जाएं और छत्तीसगढ़ सरकार को उसकी राशि भी मिल पाये। ऐसे किसान जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, उस एफ.आई.आर. को खत्म किया जाये। प्रदेश में अन्यथा ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। यह तात्कालिक...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आजकल तो किसानी नहीं करस ।

श्री ब्यास कश्यप :- भईया, मैं ही करथो। तैं चलना, इहां से मोर संग खेत।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं खेत जावस नहीं।

श्री ब्यास कश्यप :- भईया, मैं ही खेत जाथव। मैं ही पूरा खेती करथौ। मोर जनदर्शन हा खेत में लगथे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल(डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र डोंगरगढ़ विधान सभा के खैरागढ़ जिले के अंतर्गत एक गांव लछनाटोला है, जिसका विस्थापन हो चुका है। वहां जब एक बार प्रधानपाट बैराज बना तो उसको विस्थापित करके लछनाटोला बनाया गया, उस लछना गांव को लछनाटोला बनाया गया। अब फिर से उस लछनाटोला को विस्थापन करने के आदेश आ गये हैं और जो लमटी डेम है, वहां पर उसका काम चालू होने वाला है। जिस समय ग्राम लछनाटोला बना तो उनको कुछ मुआवजा की राशि मिली थी। उस समय फिर से व्यस्थित करके, अपनी जमीन और घर पूरी व्यवस्था की और वहां पर आदिवासी अंचल के लोग बसे। अब फिर से उनको व्यवस्थापन मिलेगा तो आज की स्थिति में एक आम जनता और गरीब आदमी के लिए जमीन खरीदना बहुत ही नामुमकिन वाली स्थिति है और वहां पर पूरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आदिवासी लोग बसे हुए हैं, जिनको जमीन के बदले जमीन चाहिए और तभी वहां पर वह व्यवस्थापित होंगे और वह लमटी डैम बन सकेगा, ऐसी उनकी मांग है। मैंने इस पर आपका ध्यानाकर्षित किया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही):- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाशिवरात्रि के दिन रात में माहुद बी ग्राम है, जहां 3 साल की मासूम का शव कब्र से निकालकर, उसका सिर गायब कर दिया गया। मैंने उसके संबंध में ध्यानाकर्षण लगाया है और साथ ही 6 महीने पहले उसी से लगे ग्राम सिनाभाठा में तंत्र-मंत्र के चक्कर में एक तांत्रिक की सरेआम हत्या भी हुई थी। इसके साथ ही दिनांक 11 फरवरी, 2026 को ग्राम सांकरी का एक छात्र है, जिसका नाम नुमन कुमार साहू है, एक दिन पहले उसके परिजनों को स्कूल में बुलवाया जाता है और उनके साथ क्या बात हुई, यह पता नहीं। लेकिन सुबह दूसरे दिन वह छात्र अपने घर में आत्महत्या कर लेता है और अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पायी। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि इसमें उचित कार्यवाही हो।

श्री रामकुमार यादव(चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहत हौं कि चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में जो किसान मन धान बचे हे, आज जब बड़ा मुश्किल से पैसा ले बर जावत हे तो ओ मन 4.00 बजे ले उठके लाईन लगाए रहिथे अउ ओकरे फायदा उठाते हुए, वहां पर बोलथे कि शाम हो ही तो लिंक फेल होगे, पइसा खत्म होगे। जेमन 1 लाख में 1 हजार रूपया देथे, ओमन ला पइसा दिये जाथे तो मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहत हौं कि अइसे न हो कि जो किसान खून पसीना ला बहाथे ओला बड़ा सम्मानपूर्वक पइसा मिलना चाहिए।

श्री उमेश पटेल(खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, जो सूचना ब्यास कश्यप जी ने दी है। यह पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है और यहां बहुत सारे किसान कर्जदार हैं जिनके धान नहीं बिकने के कारण, आज भी वह कर्जदार हैं और इसमें बहुत सारे जिलों से अलग-अलग आंकड़ें आ रहे हैं, जिसमें किसान बचे हैं, ऐसा आया है। जिनको आखिरी समय में टोकन नहीं मिला है जिनको किसी तरह की परेशानी आयी। हमने इसकी ध्यानाकर्षण के माध्यम से सूचना दी है तो आपसे आग्रह है कि इसको स्वीकृत करके, यहां मौका दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- अब ध्यानाकर्षण की सूचना लेंगे। आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ सदन सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय :- आप इसके बाद में बोलिए। आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री विजय शर्मा गृह मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा व्यवस्था का प्रश्न है। इसे मैंने पिछले सत्र में भी उठाया था। एक सत्र निकल गया। यहां सदन में जो तीनों तरफ टी.व्ही. लगी हुई है, उसमें यह पता नहीं चलता है कि यहां कौन से सदस्य बोल रहे हैं और अभी क्या विषय चल रहा है। उस समय यह कहा गया था कि हम इसको अगले सत्र तक ठीक कर लेंगे। दूसरा, एक विषय यह है कि पिछले सत्र में आसंदी ने यह व्यवस्था दी थी कि माननीय सदस्यों को जो जानकारी अंग्रेजी में वितरित की जाएगी, उसकी हिन्दी कॉपी भी उपलब्ध करवायी जाएगी। मुझे इतनी मोटी अंग्रेजी में जानकारी मिली थी, मुझे अभी तक उसकी हिन्दी कॉपी नहीं मिली, उल्टे मुझे अंग्रेजी में इतनी मोटी एक जानकारी और आ गयी। आप दोनों में व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, कवासी लखमा जी से समझ लेबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोरे काम के बात करथव। तीसरी बात, या नहीं तो एआई में अनुवाद करवा लेंगे, मान लीजिए कि यदि यह व्यवस्था विधान सभा द्वारा नहीं होती है तो एआई की व्यवस्था सभी माननीय विधायकों को दे दी जाये। क्योंकि आज एआई के बारे में माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रतिक्रिया दी है । दोनों में कोई व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय :- उसमें बात कर लेंगे। अब ध्यानाकर्षण लेंगे। सर्वश्री अजय चन्द्राकर जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण में क्या आप मेरा साथ देने के मूड में नहीं हैं?

समय : 12:16 बजे **<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>**

(1) प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की जाना

सर्वश्री अजय चन्द्राकर (कुरूद), (श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा)) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- प्रदेश में नशीली पदार्थों जैसे चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन, अफीम, डोडा, नशीली गोलियां की तस्करी पर लगाम लगाना अब असंभव सा हो गया है, अवैध तस्करी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। प्रदेश में बीते 4 माह में ही कई तस्करी की घटना घटित हुई हैं, जहां दिनांक 31 जनवरी, 2025 को राजधानी रायपुर व दुर्ग-भिलाई अंतर्गत ही कई पान की दुकानें सूखे नशे से संबंधित गोगो स्मोकिंग कोन, रोलिंग पेपर और परफेक्ट रोल की बिक्री कर रहे हैं, इसके साथ-साथ ऑनलाईन तक आसानी से बेची जा रही है । जहां प्री रोल्ड कोन्स, मंकी किंग, ग्लास बॉन्ग, क्रशर फिल्टर टिप्स फ्लेवर हुक्का कोल आदि ऑनलाईन बेची जा रही है। रायपुर के खरोरा थाना अंतर्गत दिनांक 20 मई, 2025 को गांजा की तस्करी की जा रही थी। दिनांक 27/12/2025 को न्यू ईयर पार्टी के लिये करोड़ों की ड्रग्स सप्लाई की गयी, जिसमें कोकीन, एमडीएमए, अफीम, डोडा, टैबलेट्स और सिरप धड़ल्ले से परोसा गया। दिनांक 23/06/2025 को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रोड, चक्रधरनगर थाना अंतर्गत 250 पेंआजोसीन इंजेक्शन व नाइट्राजेपम टैबलेट ओड़ीसा से सप्लाई की गई । बिलासपुर शहर के हर चौक चौराहे में गांजा, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप इत्यादि आसानी से उपलब्ध कराये जा रहे हैं । छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के आरक्षक ही ऐसे नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं, दिनांक 11 फरवरी, 2026 को टिकरापारा थाना अंतर्गत आरक्षक द्वारा खुले आम हेरोइन बेच रहा था। किन्तु प्रशासन इन अवैध तस्करों को पूर्णरूप से रोकने में असमर्थ रहा है, तथा इसको रोकने के लिये कोई ठोस योजना अब तक नहीं बना पायी है, इसके साथ-साथ तस्करों पर कड़ी कार्यवाही तक नहीं की गयी। नशीले प्रदार्थों के तस्कर धड़ल्ले से राज्य के कोने-कोने तक पैर पसारे हुये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं, इसके कारण अपराध भी बढ़ रहा हैं, छत्तीसगढ़ धीरे-धीरे नशे के आगोश में डूबते जा रहा हैं प्रशासन की इस नाकामी के कारण जनता में प्रदेश सरकार के प्रति काफी रोष व आक्रोश व्याप्त हैं।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में नशीली पदार्थ जैसे चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोईन, अफिम, डोडा, नशीली गोलियों की तस्करी पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है, वस्तु स्थिति यह है कि शासन अवैध नशीली दवाई, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों के तस्करी एवं बिक्री रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

प्रदेश में विगत 04 माह में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के कुल 399 प्रकरणों में 679 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गांजा 6791 किया, ब्राउन शुगर 37 ग्राम, अफीम 484 ग्राम, हेरोईन 264.35 ग्राम, कोकिन 16.56 ग्राम, एमडीएमए 23.84 ग्राम, डोडा 512.880 किग्रा एवं नशीली दवाईयां 98231 नग जप्त किया गया है।

जिला रायपुर व दुर्ग अंतर्गत मादक पदार्थ पीने का साधन जैसे गोगो, स्मोकिंग कोन, रोलिंग पेपर आदि के बिक्री के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित नशा सेवन की सामग्रियों पर कार्यवाही करते हुए 18 अनावेदकों के विरुद्ध धारा 223, 106, 126, 135(3), बीएनएसएस की कार्यवाही की गई है। पुलिस आयुक्त, रायपुर क्षेत्रांतर्गत उक्त सामग्रियों को प्रतिबंधित करने हेतु आदेश भी पारित किया गया है।

समय: 12.20 **(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)**

जिला रायपुर में दिनांक 20 मई 2025 को थाना खरोरा अंतर्गत अपराध क्रमांक 308/2025 धारा 20 बी, (2) (C) एन.डी.पी.एस. एक्ट दर्ज कर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 27.894 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

न्यायालय पेश किया गया है। साथ ही उक्त प्रकरण में 01 फरार आरोपी की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 98,46,330/- रूपये को फ्रीज भी कराया गया है।

माह दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में रायपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए कुल 09 प्रकरण पंजीबद्ध कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे गांजा 2.959 किलोग्राम, हेरोईन 47.49 ग्राम, अफिम 1.75 ग्राम, एम.डी.एम.ए. 23.84 ग्राम एवं डोडा 2.150 किलोग्राम जब्त किया गया है।

जिला रायगढ़ में दिनांक 23.06.2025 को उड़ीसा से नशीली दवाईयां तस्करी करते पाये जाने से थाना चक्रधरनगर में अपराध क. 278/2025 धारा 22, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट दर्ज कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 250 नग पेंआजओसीन इंजेक्शन एवं 160 नग नाईट्राजेपम टेबलेट जब्त किया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

बिलासपुर पुलिस द्वारा ड्रग नेटवर्क के विरूद्ध सघन व प्रभावी कार्यवाही करते हुए विगत 02 वर्षों में 181 प्रकरणों में 306 आरोपियों को गिरफ्तार कर, गांजा 1254 किलोग्राम, इंजेक्शन 3839 नग, टेबलेट व कैप्सूल 31,184 नग, सीरप 1253 नग, गांजा का पौधा 05 नग, अफिम 2.013 किलोग्राम एवं हेरोईन 34.84 ग्राम जब्त किया गया है।

दिनांक 11 फरवरी 2026 को थाना टिकरापारा में आरोपी आरक्षक से 01 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) जब्त करते हुए अपराध क. 119/2026 धारा 21, 21बी, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में 01 अन्य आरोपी से 5.5 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) व 01 नग जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तारी करते हुए प्रकरण में धारा 25 आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है।

राज्य में वर्ष 2025 में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के कुल 1288 प्रकरणों में 2342 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गांजा 16,999.7 किलोग्राम, ब्राउन शुगर 141 ग्राम, अफिम 1259 ग्राम, हेरोईन 2.039 किलोग्राम, चरस 27.68 ग्राम, कोकिन 23.56 ग्राम, एम.डी.एम.ए. 70.46 ग्राम, डोडा 1524 किलोग्राम, हशीश तेल 20.432 किलोग्राम एवं अन्य नशीली दवाईयां 2,41,138 नग जब्त किया गया है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

वर्ष 2026 में (31 जनवरी 2026 तक) कुल 146 प्रकरणों में 257 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गांजा 3090 किलोग्राम, ब्राउन शुगर 8.85 ग्राम, अफीम 277.2 ग्राम, हेरोईन 123.8 ग्राम, डोडा 15.29 किलोग्राम, नशीली दवाईयां 59,270 नग जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही किया जा रहा है। विभाग द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

शासन द्वारा नशीले पदार्थ के रोकथाम हेतु राज्य के सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है एवं 10 जिलो में ए.एन.टी.एफ. हेतु 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में End to End विवेचना की जाकर आरोपियो एवं उनके सहयोगी सप्लायर के विरुद्ध Financial Investigation की कार्यवाही भी की जा रही है। वर्ष 2025 में 16 आरोपियों की 13,29,54,735/- रूपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज कराई गई है। वर्ष 2024 से 31 जनवरी 2026 तक 145 आदतन आरोपियों के विरूद्ध PIT-NDPS Act की कार्यवाही की गई है। अवैध मादक पदार्थों के शिकायत हेतु जारी "मानस" टोल फ्री नम्बर- 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। स्कूल-कॉलेजों, गांव-कस्बों, सार्वजनिक स्थानों एवं थाना चौकियों के महत्वपूर्ण स्थानों पर जनचौपाल, बैनर-पोस्टर, एवं सोशल मीडिया के माध्यम से नशे से दूर रहने हेतु लगातार नशामुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

शासन के ठोस प्रभावी कार्यवाही से मादक पदार्थों के Supply व Demand Network को तोड़ा जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश की जनता में रोष व आकोश व्याप्त है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने के पहले कुछ बात बताता हूं, उसको सुन लीजिये, छोटी-छोटी घटना है। यदि ये प्रभावी हुए तो परिणाम क्या होंगे? आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हो। अभी मेक्सिको में एक तस्कर का एनकाउंटर किया गया, रेंचो। समझ रहे हैं साहब? वहां मेक्सिको में 13 राज्यों में विद्रोह हो गया कि इसको एनकाउंटर क्यों किये? ये तस्करों का प्रभाव है कि आधा मेक्सिको वे चलाते हैं और आधा मेक्सिको सरकार चलाती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- 90 परसेंट मेक्सिको वही चलाते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी बात आपको बता दूं, अभी आप सोशल मीडिया देखते होंगे तो रायपुर में गांजा की पैकेजिंग का एक कारखाना पकड़ा गया है और ऐसी सी.सी.टी.वी. वे लगाकर रखे हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा बना है, जिसमें यह दिख जाता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं या आम आदमी आ रहा है। तीसरी बात आपको बता दूं, आज के समाचार पत्र में है, जहां से आप चुने जाते हैं, आप जहां से आप आते हैं वहीं से 5 करोड़ रुपया का 9 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। । अब एक चौथी चीज़ बता रहा हूं फिर मैं प्रश्न करता हूं। मेरी constituency में दहदहा एक गांव है। 35 बच्चों ने अपनी नस काट ली और वह कोई कोरियन टास्क में नहीं था कि कोई चैलेंज मिला हो। वह सिर्फ नशे के लोग स्कूल के अंदर पहुंच गए थे और वे उन बच्चों को लत में डाल दिए थे। बाकी आंकड़े तो मैं आपको बताऊंगा जो बताना होगा प्रश्न के बाद कि छत्तीसगढ़ में कितनी भयावह स्थिति है। माननीय भूपेश बघेल जी बैठे हैं, उधर जब मैं बैठता था तो मैं श्री रविंद्र चौबे जी को हमेशा एक लाइन बोलता था कि आप जब बोले मेरे साथ चलिए 5 मिनट में आपको नशा उपलब्ध करवाऊंगा, मेरे साथ रायपुर के किसी जगह पर बैठिए और आज स्थिति उससे कहीं ज्यादा खराब हुई है, सुधरी नहीं है ये आपको बता देता हूं। आपने जितना उत्तर दिया, उसमें यह बताया है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं, उसके सामाजिक प्रभाव क्या हैं और उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, इसके बारे में आपका जो उत्तर है, वह मौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त अधिकारी-कर्मचारियों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप मुझे यह बताएंगे कि अधिकारी-कर्मचारी या और भी दूसरे लोग जो काम करते हैं जैसे गांजा और दवाई की सप्लाई करते हुए एम.आर. लोग भी पकड़ में आए हैं । एम.आर. लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आपने कितने लोगों के ऊपर क्या-क्या कार्रवाई इन 6 महीनों में की है? अधिकारी-कर्मचारी या एम.आर. या उस नागरिक क्षेत्र के जो लोग हैं, वह तस्कर जो 4 बार किये हैं, 5 बार किये हैं, उसको छोड़ दीजिये, तो थोड़ा सा बताइये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ये ध्यानाकर्षण लाया है और ये वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण है और सबके लिए चिंता का विषय है, बहुत काम करने का विषय है, इसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं है। इसमें मेक्सिको की जो घटना इन्होंने बताई है, ईश्वर की दया से भारत में कोई ऐसी स्थिति नहीं है और यहां भारत में न होगी, भारत में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सब ठीक हो जाएगा। रायपुर में गांजा की पैकेजिंग वगैरह के संदर्भ में आज जो उन्होंने देखा होगा तो उसमें यह है कि सेंसर वाला कैमरा लगा था। सामान्य है, सेंसर वाला कैमरा जब भी कोई मूवमेंट होता है तो वह उसको कैच करता है । तो है ये सामान्य सब जगह लगता है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गांजा की पैकेजिंग की जो फैक्ट्री जैसी है या जहां पर गांजा पैकेट बनाया जा रहा था, उसको नहीं पकड़ा गया, उसको पुलिस ने ही पकड़ा है और ऐसी सारी ही कार्रवाइयां होंगी, उसमें संशय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, कवर्धा का जो विषय है, यह बहुत बड़ा है । 9 क्विंटल से भी ज्यादा गांजा पकड़ा गया है। अब विशेष बात यह है कि स्ट्रेटजी बदली गई है। स्ट्रेटजी बदल कर हम एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करते हैं। जहां गांजा पकड़ा गया उस व्यक्ति को ही पकड़ कर प्रकरण को समाप्त नहीं माना जाता है। प्रकरण को समाप्त तब माना जाता है कि ये कहां से लेकर आ रहा है और किसको देने जा रहा है। वहां तक हम निकाल लेते हैं तब वह प्रकरण समाप्त माना जाता है। इस एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई में अभी जो कवर्धा से ही निकल कर आया है, उसमें भी यह था कि यह राजस्थान जाने वाला था। राजस्थान में किसके पास जाने वाला था, यह भी अभी जाँच में है। अब जिसके पास जाने वाला था, उस पर भी राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कार्यवाही करना, इस पूरे चैन को नेस्तनाबूद करने की कार्यवाही इस पर की जा रही है। कवर्धा के प्रकरण का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया, इसलिए मैं इसकी जानकारी दे रहा था। चन्द्राकर जी, कुरुद में जो कुछ प्रकरण हुआ है, उसको आपने मुझे बताया। मुझे इस विषय का बड़ा आश्चर्य है और इस विषय का बड़ा दुख है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ वहाँ चलूंगा और हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके सामाजिक प्रभाव कैसे हैं, यह जरूर एक चिंता का विषय है। दोनों ही प्रकार के विषय हैं। नशे के लत के बढ़ने के कारण हम समाज में विभिन्न ऐसी स्थितियाँ देखते हैं, जिससे अपराध भी बढ़ जाता है। माननीय सभापति महोदय, इस पर क्या कार्यवाहियाँ हो रही हैं और उन पुलिस की कार्यवाहियों से क्या फर्क आ रहा है? कार्यवाहियाँ दो तरह की हैं। एक तो सामाजिक स्तर पर हम क्या करते हैं, एक मसला होता है; दूसरा पुलिस क्या करती है, एक मसला होता है। अध्ययन करके मुझे जो बात समझ में आई है, उस आंकड़े के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (N.D.P.S.) के जितने भी कार्यवाहियाँ होती हैं, उसमें कभी Financial Investigation

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के मामले नहीं हुआ करते थे। विष्णु देव जी की सरकार में यह Investigation प्रारंभ हुए हैं और अब हम Financial Investigation के मामले में काम कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला Financial Investigation का काम हुआ है, वह बिलासपुर से शुरू हुआ है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सबसे पहले एक प्रकरण हुआ है। बिलासपुर के उस प्रकरण में 02 जनवरी, 2025 को इसका पहला रिजल्ट आया और उस प्रकरण में 16 लाख रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की गई। फिर बिलासपुर में ही 04 फरवरी, 2025 को एक और प्रकरण सामने आया, वह भी सिविल लाइन थाना क्षेत्र का प्रकरण था, उसमें 1 करोड़ 70 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की गई। उसके बाद वहाँ पर 04 फरवरी को फिर से एक प्रकरण सामने आया, उसमें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। 13 फरवरी को फिर प्रकरण हुआ, उसमें 1 करोड़ 80 लाख की संपत्ति वहाँ फ्रीज़ की गई और 15 अप्रैल को फिर हुआ और 14 लाख की संपत्ति फ्रीज़ की गई। यह संपत्ति फ्रीज़ करने के कारण मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि बिलासपुर में अब यह नेटवर्क टूट गया है। बिलासपुर में नेटवर्क टूटने से अब यह सारी घटनाएँ कम हुईं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी कहना चाहता हूँ कि हम इस पर Financial Investigation करते हैं, सफेमा (SAFEMA) का कोर्ट होता है, जहाँ से हम आर्डर लेकर के आते हैं। प्रदेश में विगत दो वर्षों में ऐसे 16 प्रकरणों में 13 करोड़ 29 लाख 54 हजार 735 रुपये के प्रॉपर्टी अटैच करने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, यह प्रैक्टिस पुलिस विभाग में माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार के पहले छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस प्रैक्टिस को किया है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहा है तो नशे के कारोबार से कमाये हुए पैसे को वह छह महीना जेल काट कर के आएगा और उसके बाद उसको enjoy करेगा। यह नहीं करने दिया जाएगा उसका प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा। उसके ऊपर Burden of Proof भी होता है। वह कोर्ट में जाकर यह बताएगा कि नहीं, यह प्रॉपर्टी मैंने नशे के व्यापार से नहीं, कहीं और से कमाई है तो उसको वह Proof करना होगा। इसलिए ऐसे प्रकरण बनाकर 16 प्रकरण प्रदेश में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक विषय हैं। क्या कदम उठा रहे हैं? ऐसा माननीय सदस्य के माध्यम से पूछा गया है। मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। Anti Narcotics Task Force (A.N.T.F.) का गठन हुआ है, उसके लिए 100 पदों की स्वीकृति भी हुई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं आपके पूरे उत्तर को इसलिए सुन रहा हूँ कि इस माध्यम से प्रदेश के तस्कर सुनें। आप उत्तर अच्छा दे रहे हैं, इसलिए मैं उत्तर सुन भी रहा हूँ। A.N.T.F. के 100 पद बाद में आयेंगे। पहले मेरा मूल प्रश्न उत्तर आ जाये। आप पूरा पढ़ देंगे, फिर मैं क्या पूछूँगा? नहीं तो ध्यानाकर्षण के बजाय सत्यनारायण जी की कथा हो जाएगी।

श्री विजय शर्मा :- आपने यह कहा है कि सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं उन्हीं कदमों को आपसे यह कहूँगा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं और नवीनता लिए हुए हैं, यह नवाचार है। मैंने आपसे एक बात कही है कि SAFEMA के कोर्ट में इस विषय पर, N.D.P.S. के विषय पर हम कभी नहीं गए थे, अभी गए हैं। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि 1988 का पिट एन.डी.पी.एस. एक्ट है। इस पिट एन.डी.पी.एस. में प्रिवेंटिव एक्शन्स लेते हैं, जिसमें नारकोटिक्स के क्षेत्र में जो अपराधी हैं, उन अपराधियों को प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए पहले ही पकड़ लिया जाता है। ऐसे 145 आर्डर छत्तीसगढ़ में हुये हैं, यह भी ऐसा अभ्यास है कि जो विष्णु देव साय जी के सरकार है, उसके पहले यह नहीं हुआ था, कोई केस नहीं था । मैं तो बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा अभ्यास जो है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इतना लम्बा उत्तर है और मैंनें भी आप लोगों को बधाई दिया कि यह उत्तर अपराधियों तक पहुंचे, यह मैंने समर्थन किया है । दूसरा प्रश्न तो आये । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास सरकारी आंकड़े है तो ज्यादा सार्थक रहेंगे । हमारे संविधान में वेल्फेयर स्टेट की एक परिकल्पना है, मैंने प्रश्नकाल में भी एक सामाजिक विषय उठाया था और यह भी एक सामाजिक विषय है । आपक शब्दों में हैप्पीनेस इंडेक्स है, समाज कितना संतुष्ट है, अपराधविहीन है, यह भी वेल्फेयर स्टेट का इंडेक्स है । आपको एक ऑंकड़ा बता देता हूँ । छत्तीसगढ़ में साढ़े तीन-साढ़े चार लाख गांजा उपयोगकर्ता बढ़े हैं । अफीम इंजेक्शन 1.5 से 2 लाख और ये सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के आंकड़े हैं । किशोर बच्चे 10 से 17 साल वाले 40 हजार प्लस है, जो इनहेंलर या कफ सिरप पी रहे हैं और नशे से 250 से 300 मौतें हो रही है । यह सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के आंकड़े हैं । मैं इसको इसलिये बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो हॉट-स्पॉट उभरे हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, बस्तर जिसमें सुकमा विशेष तौर पर शामिल है । मैं माननीय रामविचार जी को व्यक्तिगत चर्चा में कह रहा था कि आप चिंता कीजिए कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बलरामपुर को क्या बनाने जा रहे हैं, मंत्री बनने के अलावा आपके कुछ सामाजिक दायित्व भी है, मैंने यह कहा था । बलरामपुर, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, जिसका आपने नाम लिया, अब मुझे यह बताईये कि इसके बढ़ने के कारण क्या है और आपने जो 100 पद स्वीकृत किये हैं, कब किये हैं, कौन-कौन से जिले से लिये हैं, कब तक इसकी प्रतिपूर्ति हो जायेगी ? आप डिप्टी सी.एम.भी हैं और अधिकांश में उत्तर यही आता है कि समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है । मैं अभी 5 हजार शिक्षक भर्ती में पूछा हूँ तो यही बताया है कि समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है । चूँकि यह उससे ज्यादा गंभीर मामला है, पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो बाकी शिक्षक को करेंगे क्या? मैंने आपको कुछ हॉट-स्पॉट बताये हैं । कवर्धा का नाम नहीं लिया है, आज पहली बार कवर्धा छपा है । यह 100 पद कौन-कौन से जिलों के लिये है और कब तक इन जिलों में ट्रेनिंग करके थाना में पहुंच जायेंगे?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि एन्टी नारकोटिक्स कोर्ट सभी जिलों में है । सभी जिलो से होकर इसमें एक व्हाट्स एप भी बनायेंगे तो कोर्ट में 10-10 लोगों की नियुक्ति होगी । एंटी नारकोटिक्स साक्ष्य कोर्ट के लिये अलग से पुलिस की भर्ती नहीं होती है । इसमें जो उपलब्ध बल हैं उसमें से काम लिया जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा है । 100 नवीन पदों के बारे में आपने कहा है ।

श्री विजय शर्मा :- आप सुनिये ना?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पूरी बात सुनूँगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे नये फोर्सेस के गठन किये जाते हैं तो मूल हमारे बल की संख्या है उसमें कमी होती है तो उस कमी को भरा जाता है । मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, राजनीतिक तौर पर तो यह कह दूँगा कि एएनटी का गठन तो वर्ष 2022 से हुआ है, लेकिन उसमें डेपुटेशन पर ही काम चलाया गया, नये पद नहीं लाये गये । अभी नये पद की स्वीकृति पिछले बजट में ही हमको हुई है और यह 100 पद है । जिन जिलों के लिये हुई है, मैं वह भी आपको कह देता हूँ । रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों के लिये हुई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपने जो हॉट-स्पॉट गिनाये हैं यह वही हॉट-स्पॉट के लोग हैं । सभापति महोदय, इसमें एक-दो स्थान और है, जहां पर 10 लोग नहीं जा रहे हैं, वहां पर काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है । अन्य बलों से लेकर एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स का गठन करके उस पर काम किया ही जा रहा है । नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से जो भी निर्देश आते हैं, जो भी योजनायें बनती है, उस पर काम किया जा रहा है, काम करने में दिक्कत नहीं है । मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा था। ये पिट एनडीपीएस पर कार्रवाइयाँ कैसे हुई हैं या अन्य विषयों पर कार्रवाइयाँ अभी पुलिस के द्वारा कैसे की जा रही है। गाड़ी जब्ती की बात है वह भी आपको एक बार बता देता हूँ। मतलब पिछले 2 महीनों में 296 गाड़ियाँ ज़ब्त की गईं और 150 गाड़ियां नीलाम की गई। ये नीलाम गाड़ी का नीलाम करना, चूँकि ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं होता है, इसमें अन्य सारे विभाग होते हैं, ये बड़ा काम होता है। परंतु इतना यहाँ पर किया गया है। वेलफेयर स्टेट की कल्पना में हैप्पी इंडेक्स की जो बात है और उसमें जो स्थितियाँ आपने छत्तीसगढ़ की कहीं, कमोबेश ये अनेक स्थानों पर है और उस पर प्रखरता से काम चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, दोनों ही स्तरों पर इस पर काम हो रहे हैं। एनकॉर्ड की बैठकें पहले नहीं हुआ करती थीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कब नहीं होती थीं, अभ्यास में नहीं था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इसमें किसी को दोष देने वाला मामला नहीं है। लेकिन अब प्रत्येक जिले में नियमित प्रतिमाह बैठक होती है। ये नार्कोटिक्स को-ऑर्डिनेशन की जो बैठकें हैं, चूँकि नार्कोटिक्स का मामला, एक मामला है जो अवैध काम कर रहा है, उनके पास अवैध सब्सटेंस है, उसके लिए पुलिस उत्तरदायी होती है, परंतु जो सामाजिक प्रभाव है, उसके लिए सबको उत्तरदायी होना होता है। इसलिए एनकॉर्ड बना हुआ है और इसके माध्यम से जब इसकी बैठक होती है तो उसमें जिला शिक्षा अधिकारी भी होते हैं, उसमें सी.एम.एच.ओ. भी होते हैं, उसमें कलेक्टर भी होते हैं, उसमें एस.पी. भी होते हैं और ये सारे के बीच में को-ऑर्डिनेशन करके जिलों में ये सुनिश्चित किया जाता है कि पूरी पर्याप्त कार्रवाइयाँ हों, ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों जिससे हम इन मामलों से उभर कर सामने आ सकें, इसका अभ्यास अच्छे से प्रारंभ हो गया है और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 6 महीनों में ही हम छत्तीसगढ़ में इसमें बहुत अच्छी स्थिति में आएँगे।

सभापति महोदय :- माननीय, इसमें पर्याप्त उत्तर आ चुका है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैंने सिर्फ दो प्रश्न किया है। मैं तो उत्तर ही सुन रहा हूँ और जानबूझकर सब सुनें और समझें करके उनके उत्तर को रिकॉर्ड में ला रहा हूँ । इसीलिए मैं टोका-टाकी नहीं कर रहा हूँ । माननीय, आपको एक चीज ध्यान में ला दूँ कि नशा में कार्रवाई से नशा दूर नहीं होगी। मैंने जो आँकड़े बताए, वह सामाजिक न्याय मंत्रालय के थे, नशामुक्ति केंद्र का उल्लेख है, वह छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग का विषय है। यदि मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वह स्वास्थ्य विभाग का विषय है। आपने आम पब्लिक में जागरूकता के जो छोटे-छोटे विषय बताए हैं - जन चौपाल और कुछ अन्य बताएं हैं, अब इन छोटे विषय में तो मैं पूछ ही रहा हूँ, लेकिन इसके को-ऑर्डिनेशन के लिए आप क्या करेंगे? क्या कदम उठाएँगे? आपको मैं बता दूँ कि आप अभी यहाँ से निकलकर किसी माननीय विधायक को भेजिए और जो आपका मानस टोल-फ्री नंबर है, उसको लगवाइए। यहीं तुरंत भेजिए, बाद में नहीं, अभी हमारी-आपकी बात हो रही है, लॉबी में भेज दीजिए और 1933 लगवाइए चालू है या बंद है? दिखवाइए। दूसरी बात, आपने जितने जन-जागरूकता के स्कूल-कॉलेज कार्यक्रम बताए हैं, स्कूल-कॉलेज के आसपास 1500 मीटर के दायरे में नशे के सामान हर तरह के उपलब्ध हैं। जनजागरुकता के लिए आपके बजट, फंड और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कौन करता है? आपके पास कौन सी एजेंसी जो करती है? मैंने पुलिस को यह काम करते नहीं देखा है, एक। दूसरी बात, शैक्षणिक परिसर के आसपास इस तरह के बिक्री के लिए कोई कदम उठाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे क्या, दो ? तीसरी बात जो इंटर-डिपार्टमेंट एक्शन होना चाहिए इसको रोकने के लिए, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, यह बताने का कष्ट करें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात को पिछली बार ध्यान नहीं दिया। मैंने इसी विषय को उठाया है कि अगर नशे का व्यापार करते कोई मिलता है तो उसको पकड़ना, उस पर कानूनी कार्यवाही करना पुलिस का काम है।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या शैक्षणिक परिसर में प्रतिबंध लगाएंगे, यह बताईए ?

श्री विजय शर्मा :- तैं मोला बोलन तो दे गा। नशे का व्यापार करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ना पुलिस का काम है, सारे शैक्षणिक संस्थानों में स्थिति क्या है, कोई मेडिकल शॉपकीपर है तो उसके यहाँ जाकर कार्यवाही करना है, पुलिस सक्षम है या नहीं है या उसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स की आवश्यकता है तो स्वास्थ्य विभाग उसमें क्या करेंगे। ऐसे ही अगर रिहैबिलिटेशन करना है तो रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाएगा, उसकी व्यवस्था कैसी है। ऐसे विभिन्न विभागों के बीच

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को-आर्डिनेशन के लिए ही नारकोटिक कोआर्डिनेशन 'एनकॉर्ड' जो मैंने आपसे कहा, उसकी बैठकें अब नियमित रूप से प्रत्येक जिले में कलेक्टर के साथ, कलेक्टर की अध्यक्षता में होती हैं। इसकी मॉनिटरिंग की कमेटी स्टेट लेवल पर है, जो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से यहां पर उसकी बैठक होती है। इन सारे ही विभागों के बीच समन्वय करना होता है, इसलिए कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी के मुखियाई में यह बैठक होती है। इसी के माध्यम से सभी विभागों के बीच में यह समन्वय होता है। माननीय सुशांत शुक्ला जी ने अभी बाहर जाकर फोन किया, जैसा कि माननीय अजय चंद्राकर भाई साहब ने कहा तो उन्होंने आकर मुझे बताया कि वह नंबर चल रहा है तो मैंने कहा कि आप मुझे मत बताइये, आप माइक पर बता दीजियेगा कि 1933 नंबर चल रहा है और 1933 नंबर में आप शिकायत भी करेंगे। मैं आपको 1933 नंबर की एक और बात बता दूं कि जब 1933 नंबर में कॉल जाता है तो वहां से बहुत सारे फीडबैक आते हैं और उस फीडबैक के आधार पर 145 फीडबैक आये और 145 फीडबैक में से 17 पर, एक मिनट मैं आपको इसको और कन्फर्म कर देता हूं। हमने 14 प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज की। हमने उसमें 125 प्रकरण लिये और 125 प्रकरण के बाद 14 प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज की गई। 1933 नंबर पर कॉल करके किसी ने कहा तो उस पर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और उस पर कार्रवाई हुई है। 1933 नंबर भी ठीक से काम कर रहा है। आपकी चिंता का विषय बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रेरणादायी है। हम सब मिलकर इसको और आगे बढ़ायेंगे। स्कूल के परिसर के आसपास का मामला है तो यह बात वस्तुत: चिंता की है। अगर माननीय सदस्य के ध्यान में कहीं पर ऐसी स्थिति है तो वह चिंता का विषय है। उसको एनकॉल्ड के माध्यम से अगली बैठकों में इसको रखकर मैं सोचता हूं कि प्रदेश भर में लागू करना अच्छा होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। आपके उत्तर रिकॉर्ड में आ गये हैं। यदि यह सरकार की चिंताओं में ही शामिल है तो यह मेरे लिए बहुत है या मैं सदन के लिए कह सकता हूं। यह जो आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया है, इसके संबंध में मैंने पूछा है कि इसको पुलिस विभाग करता है या समाज कल्याण विभाग करता है या स्वास्थ्य विभाग करता है? गांव, कस्बों, सार्वजनिक स्थानों में जन चौपाल, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया आदि और इसके लिए मैंने आपके विभाग के बजट को पढ़ा तो बजट बुक में इस तरह के कामों के लिए मुझे बजट नहीं दिखे। यदि 1933 चालू है तो आप बधाई स्वीकार कर लीजिये। मैंने 3 दिन पहले उस पर फोन लगवाया था, जब यह लाल पत्ता मिला तो इसको लगाकर देखिये। तब मुझे रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन रिस्पांस मिला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो आप बधाई लीजिये। इसके लिए बजट और इस तरह के कामों के लिए एजेंसी और इसकी निरंतरता, निरंतरता का मतलब है कि यह लगातार चले। नशा मुक्ति केन्द्र के ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. की व्यवस्था और निगरानी की जाये। मैं इसको उत्तर क्या कहूं, इस पर आप एक और वक्तव्य दे दीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सदस्य जी, इन सारे ही महीन प्रश्नों के उत्तर आप ही जानते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि आपने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर देता हूं। मैं आपसे पुन: कहना चाहूंगा और मैंने पहले भी कहा कि सारे ही विभागों के बीच के समन्वय का जो केन्द्र है, इन्स्टीट्यूशन है, एनकॉल्ड है, एनकॉल्ड की बैठकें पहले नहीं हुआ करती थीं। अब एनकॉल्ड की बैठकें हर महीने हर जिले में होती हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं टोक रहा हूं।

श्री विजय शर्मा :- भैया, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उन बैठकों के माध्यम से।

श्री अजय चंद्राकर :- वह एनकॉल्ड की बैठकों पर ही केन्द्रित है। मैंने एनकॉल्ड की बैठक के बाहर का प्रश्न पूछा है। मैं उसको तीन बार सुन चुका हूं। मैंने आपको उसके लिए बधाई भी दी है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं। आप मेरी बात सुनिये, उस बैठक में ही निर्णय हो करके और सारे विभागों के समन्वय से इन जन जागरूकता के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं।

सभापति महोदय :- धरमलाल कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, आज हम लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ खुशहाली की दिशा में जा रहा है और आर्थिक रूप से सम्पन्नता भी आ रही है। लेकिन यदि हम छत्तीसगढ़ के भविष्य के बारे में चिंता करे तो वह हमारे युवा हैं। यदि आपके पास सारे संसाधन हैं, आर्थिक रूप से सम्पन्नता आ रही है, खुशहाली आ रही है, लेकिन यदि युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ गई तो सब कुछ होते हुए भी छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है और आगे चलकर हम जो कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना के बाहर जाकर उसको वह अंधेरे की ओर या पीछे ढकेल रही है। जिस प्रकार से आप और हम समाचार पत्रों में, टी.व्ही. के माध्यम से लगातार यह देख

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे हैं कि विभाग कार्रवाई भी कर रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, उसके चालान भी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उसमें जिस प्रकार से युवाओं की जो सक्रियता है, उसमें कमी आनी चाहिये और वह लिंक टूटनी चाहिए। यह मुख्य चिंता का विषय है। इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि हम युवा पीढ़ी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं ? आपने अभी बहुत सारे उपाय बताएं हैं, बहुत सारे कारण बताये हैं। आपने बैठकों के बारे में और गिरफ्तारियां भी बताई हैं। लेकिन उसके बाद भी जो नशे की ओर जा रहे हैं, उनका रुझान कैसे खत्म हो? उसमें एक नशा नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के नशे हैं। उसमें जब तक उनकी सक्रियता रहेगी तो हम कार्रवाई तो करते रहेंगे लेकिन शायद हम उन्हें बचाने में सफल नहीं होंगे। इसलिए उसमें हमारी जो कार्रवाई है, एक तो हम उसमें जो आपराधिक कृत्य हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें उनको दबोचना, उनको पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका लिंक टूटे लेकिन दूसरी ओर उनको सामाजिक सरोकार के दृष्टिकोण से, जागरूकता के दृष्टिकोण से नशे से दूर करने के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं, उसमें और क्या सार्थक पहल हो सकती है जिससे हमारी युवा पीढ़ी नशे से दूर हो तभी मैं समझता हूं कि हमारा प्रयास कारगर होगा और इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का मार्गदर्शन, उनकी चिंता सब कुछ जायज है और उन्होंने सही कहा कि अगर प्रदेश के युवा नशे की चपेट में आ जाएंगे तो कैसे होगा। माननीय सभापति महोदय, पुलिस की कार्यवाही से आगे और क्या-क्या हो सकता है, यह अवश्य सबकी चिंता का विषय है । सरकारी तौर पर मैंने आपको बताया कि पुलिस के विभाग में भी ऐसे अनेक काम हैं जो पहली बार किए जा रहे हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ किए जा रहे हैं। जिसमें प्रॉपर्टी अटैच करने का काम, इसमें पिट एन.डी.पी.एस. का काम, इसमें गाड़ियों को राजसात करके नीलाम कर देने का काम किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मैंने बैठक की और उसके बाद अनेक स्थानों पर यह कार्रवाई चल रही है। माननीय सभापति महोदय, ये कार्यवाहियां हैं और उसके साथ-साथ इस कार्रवाई में जो लोग सामने आए, जो नशे की लत वाले हो गए थे, उनको पुनर्वास केंद्रों में भी ले जाने का काम किया जा रहा है। जैसे शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र, मोवा रायपुर में है। उस शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र, मोवा रायपुर में कुछ लोगों को रिहैबिलेट करने के लिए भी ले जाया गया है परंतु परिवार तैयार नहीं होते हैं, वह व्यक्ति स्वयं तैयार नहीं होता है, अनेक ऐसी और परेशानियां आती हैं। ये चिंता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुत आवश्यक है। हम सबको मिलकर समग्रता के साथ इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। जहां तक मसला पुलिस का है तो मैं सोचता हूं कि पुलिस ने अद्‌वितीय कार्य किए हैं। पुलिस विभाग ने भी अपने ही लोगों पर कार्रवाई की है। माननीय सदस्य ने कहा कि एक व्यक्ति नशे के केस में लिप्त था तो ऐसे 12 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इसमें जो भी लिप्त पाया गया, उनको बर्खास्त किया गया, उनकी नौकरी खत्म की गई, उन पर एफ.आई.आर. की गयी और उन्हें जेल में डाला गया है। पूरी दृढ़ता के साथ इस कार्रवाई को किया गया है। शेष बात यह है कि पूरे ही प्रदेश के युवाओं की जो चिंता है, जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में, देश प्रदेश के भविष्य के संदर्भ में, तो मैं सोचता हूं कि इसमें और मंथन करके और आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक विषय है। चूंकि ध्यानाकर्षण का विषय नशीले पदार्थों की बिक्री के लिए है और माननीय गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य अभी तक आया है। इस पूरी चैन के बीच में जो सबसे बड़ा लैकुना है वह मेडिकल से संबंधित है। इसमें नशे के लिए जो दवाइयां उपलब्ध होती हैं, उस पर कार्रवाई का विषय गृहमंत्री जी के वक्तव्य में उल्लेखित नहीं हैं। जब दवाइयों की उपलब्धता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं होलसेल यानी सी.एण्ड.एफ. प्राप्त दुकानें, जो मेडिकल दुकानें होती हैं या जो आपकी रिटेल की दुकानें हैं, वहां से ये दवाइयां आसानी से बाजार में उपलब्ध होती हैं। गृहमंत्री जी के पूरे वक्तव्य में एक भी बार यह कथन नहीं आया कि उन पर क्या कार्रवाई हुई। दूसरा, नशीली पदार्थों में एक अवैध शराब का भी विषय आता है। जब हम 1933 नंबर में फोन करते हैं, तो वह उसको आबकारी का विषय बताते हैं। मेरे क्षेत्र में लोफंदी, गुंदैया, सेमरताल, जलसो, बटियारी, घुटकु, तखतपुर विधान सभा के, कोटा विधान सभा के जनपद पंचायत में रानीगांव अवैध शराब की बिक्री का केंद्र है। परंतु जब हम 1933 में फोन करते हैं या स्थानीय थाने में फोन करते हैं तो आबकारी का विषय बनाकर उसको टाल दिया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में होलसेल दवाइयों के माध्यम से जो उनके व्यापारी हैं, जिनके माध्यम से बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयां बाजार में उपलब्ध होती हैं, इस पर पुलिस की क्या-क्या कार्रवाई आज दिनांक तक सुनिश्चित हुई है? इस पर हमें जानकारी उपलब्ध करा दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने 1933 पर जो कॉल किया और उनको ध्यान भी आया, तो यह एन.डी.पी.एस. के लिए है। यह नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो एक्ट है, उसके अंतर्गत जो कार्रवाईयां की जा सकती हैं, जिसमें शराब को छोड़कर बाकी सब कुछ है, वह उसी के लिये है। इसलिए मेरा विनम्रता से आग्रह है कि अवैध शराब एक मामला अलग है। ये बात बहुत गंभीर और बहुत अलग मामला है। अवैध शराब भी उतना ही गंभीर है, परंतु उसकी क्रियाविधि दूसरी है। इसमें जो मेडिकल स्टोर हैं, मेडिकल से संबंधित लोग हैं, वहां पर पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती। वहां पर हमको स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेना होता है और इसके लिए मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ दिनांक 26/11/2024 को बैठक की। उसमें दोनों ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण थे। उन अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद रायपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाईयां सारे ही ऐसे लोगों पर की गईं, जिसका पूरा आंकड़ा मेरे पास है कि कितनी वहां पर दुकान हैं, कितने वेरीफिकेशन किये गये, कितने को सस्पेंशन किये गये और फाइनली कितने कैंसिल कर दिये गये। सभापति महोदय, यह सारी डिटेल मेरे पास है। इसके साथ एक और नया नवाचार किया गया है, वह भी आपको बताना चाहता हूं। दिनांक 24 मार्च 2025 को दुर्ग में पूरे ही संभाग के जितने भी मेडिकल दुकान के संचालक थे, सबको बुलाकर, एक साथ बैठाकर यह समझाया गया कि इन-इन चीजों को अगर आप अपनी दुकान में रखते हैं और बेचते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपने कब मंगाया, कितना मंगाया, कितना बेच रहे हैं, किसको बेच रहे है अन्यथा आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जायेगी। इस ताकीद को करने के बाद उस पर भी बहुत तेजी से कार्रवाईयां की गईं। आप कहेंगे तो ये पूरा आंकड़ा है, मैं पढ़कर के बता सकता हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। मैं बिलासपुर के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। जब मैं मेडिकल दुकानों में कार्रवाई की बात करता हूं तो बिलासपुर के थाना सिविल लाईन, सरकंडा, तारबहार के अंतर्गत आने वाले मिनी बस्ती, तालापारा, खमतराई, बहतराई और अन्य स्थानों पर जो दवाई की बड़ी मात्रा पकड़ाई गई है, उसको किसने दिया, इस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है। प्रश्न यही उठता है कि कोनी जिसको हम एजुकेशन हब के रूप में डेव्हलप कर रहे हैं, वहां पर नशे का व्यापार, खासकर मेडिकल से संबंधित नशे का व्यापार चरम पर है। इस पर कार्रवाई करने के लिए क्या व्यवस्था देंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है, माननीय सदस्य क्षेत्र के संदर्भ में बहुत चिंतित हैं, बहुत अच्छा विषय है। इतने स्पेसीफिक हैं कि वहां पर जा करके कोनी में क्या हो रहा है, मैं अभी अचानक आपके सामने कैसे बता दूं। लेकिन जो भी हो रहा होगा, मैं उनको इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं 24 घंटे आपेक साथ खड़ा हूं। आप बिल्कुल ध्यान देकर बतायें, उस पर पूरी कार्रवाई करवायेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का एक वक्तव्य आया था कि शाला परिधि के अंदर शराब, नशा के संबंध में कोई बातें आती हैं तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गुंडरदेही और उसके बाउण्ड्रीवाल के जस्ट आगे शराब की दुकान है। वहां शराब लेकर आते हैं, उस परिधि के अंदर बैठने की बढ़िया व्यवस्था है, वहां बैठकर डेली शराब पीते हैं। अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो आधे घंटे के अंदर मैं माननीय मंत्री जी को पूरा वीडियो के साथ फुटेज उपलब्ध करा दूंगा। वहां बैठकर पीते हैं। वैसी ही स्थिति अर्जुन्दा शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्वामी आत्मानंद स्कूल है, उसके प्रीमाइसेस में 2-3 दुकान हैं, एक में अंडा बिकता है, एक में पूरा किराने का सामान मिलता है और सारे संसाधन हैं। बच्चे लोग पीछे बैठकर शराब पीते हैं। अर्जुन्दा में कारगिल चौक है, वहां नशे का व्यापार लगातार चल रहा है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इसलिए जवाबदारीपूर्वक कह रहा हूं इसी नशा के कारण पिछले महीने मेरे घर के 100 मीटर सामने मुख्य मार्ग में 27 साल के एक युवक की शराब के नशे में हत्या हुई थी। मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि मैं स्थानीय पुलिस को लगातार प्वाईन्ट भी देता हूं, लेकिन कार्रवाई शून्य के बराबर है। उस संबंध में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री को सच में बधाई कि नशा को रोकने के लिए बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। एक छोटा सा प्रकरण आया था। अभी आपने बताया कि किस तरीके से आप संपत्तियां राजसात कर रहे हैं। जिसके घर में भी नशा का आदी युवक होता है, उसके घर वाले भी उतना ही परेशान होते हैं, जितना समाज परेशान होता है। पर उसको घर से बाहर नहीं कर सकते। अभी एक केस आया था जिसमें नशे का आदी युवक पकड़ाया, पर उसके पिताजी, भाई की संपत्ति को राजसात कर लिया गया। वह लड़का नशे का आदी है, अब लड़के को मार तो नहीं सकते, घर से भगा तो नहीं सकते, पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसके पिताजी की संपत्ति को राजसात करना कहीं न कहीं अमानवीय है। इस पर जरूर काम होना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी आपके थानों में ड्रोन चल रहा है, ड्रोन से रात में चेकिंग हो रही है।

समय : 1.00 बजे

अभी परसों मेरे पास फोन आया कि खेत में बैठकर 5 लोग शराब पी रहे थे, पुलिस आयी और उनको पकड़कर ले गयी । अगर अपने खेत में भी बैठकर शराब नहीं पी पायेगा, पुलिस उसको अनाधिकृत रूप से अंदर कर देगी तो आदमी कहां बैठे, कहां जाये और किस तरीके से बचे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आज एन.डी.पी.एस. की चर्चा कर लेते हैं । शराब पर चर्चा होगी तो बड़ी दूर तलक जायेगी । (हंसी) मैं इसमें आपको निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ गुंडरदेही के संदर्भ में माननीय सदस्य की चिंता थी कि बाउंड्रीवॉल...।

श्री भूपेश बघेल :- गृहमंत्री जी, आप ईशारा किधर कर रहे हैं ?

श्री विजय शर्मा :- आप चिंता न करें । (हंसी) मतलब मैं आपकी तरफ ईशारा कर रहा था । मैंने कहा न कि मैं आपकी तरफ ईशारा कर रहा था ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, गृहमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही । यदि दूर तलक जायेगी तो जाने दीजिये लेकिन उसमें चर्चा कराईये । भागिए मत, समय तय करिये, अभी सत्र चल रहा है और निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए।

श्री विजय शर्मा :- जरूर-जरूर ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है । मैं माननीय विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य से आग्रह करूंगा कि प्रक्रिया के तहत् आ जायें, चर्चा उस पर तैयार है । करें तो सही । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशांत शुक्ला :- प्रक्रिया तो करवायें । प्रक्रिया करें, यह क्या होता है ? चर्चा किसी और चीज की चल रही है और किसी और का, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विधिवत अनुमति लीजिये और चर्चा करवाईये । कौन मना कर रहा है ?

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए ।

श्री दिलीप लहरिया :- अनुमति के बाद ही चर्चा होगी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं?

सभापति महोदय :- मंत्री जी का जवाब आ रहा है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं कहां चिंता कर रहा हूं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बहरहाल एन.डी.पी.एस. के बारे में पहले बात कर लेते हैं । मैं पुन: कहता हूं कि अगर शराब वाली जो आप बात कर रहे हैं उस पर बात होगी तो दूर तलक जायेगी । आप चर्चा करवाईये, किसने मना किया है ? लगाईये, प्रक्रिया है उस पर करवाईये । गुंडरदेही का विषय है, जो आप कह रहे थे, मैं नि:संदेह उस पर ध्यान देता हूं, व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देता है और उस पर क्या हुआ है, मैं आपको कंफर्म भी फोन करके मैं जरूर कर दूंगा, जो कार्रवाईयां होंगी । दूसरा मेरा मसला यह है कि गुंडरदेही है, आपका क्षेत्र है, आप वहां पर हैं, यह शराब की दुकान वहां पर कब से खुली है, इसकी एक-बार चिंता भी कर लेनी चाहिए । आप मेरी बात समझ रहे हैं, यह शराब की दुकान कब से खुली है, इसकी चिंता आज सदन में अचानक, इसको पहले भी करना चाहिए था । दूसरा, जो माननीय सदस्य ने कहा कि एक युवक जो नशे का आदी है, उसके कारण परिवार भी पीड़ित है और समाज भी पीड़ित होता है । उसके घर वालों की संपत्ति प्रॉपर्टी अटैच कर ली गयी, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं होता है, एक भी प्रकरण नहीं होता है, इसमें बहुत स्पष्टता के साथ भाव है कि नशे के व्यापार करने वाले की संपत्ति अटैच करनी है वह गुनहगार है और जो नशे का आदी हो चुका है, वह बेचारा है उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाना है ऐसा है । ऐसे प्रकरण भी होते हैं जिसमें नशे का आदी व्यक्ति ही व्यापारी होता है तब इस कार्रवाई को वहां पर किया जाता है । आप बिल्कुल नि:संदेह इसमें चिंता न करें, जो भी है, अब ड्रोन वगैरह का मामला है उसको फिर जैसे आएगी प्रक्रिया तब कर लेंगे।

सभापति महोदय :- वैसे इसमें बहुत चर्चा हो गयी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बालेश्वर साहू (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक इसी में है। एक छोटा सा, मेरे क्षेत्र का एक मामला है । माननीय उपमुख्यमंत्री जी, बड़ेरवेली सक्ती जिले का मामला है, जैजेपुर विधानसभा । यहां लगभग 3 दिनों पहले रात के 2 बजे नई शराब दुकान खोलने के लिये मटेरियल गिरा दिया गया है और पंचायत की 200-300 महिलायें लगातार वहां बैठी हुई हैं कि हम लोग अपने गांव में खोलने नहीं देंगे लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स लगी हई है और उनका कहना है ।

सभापति महोदय :- उसको अलग से। नहीं, वह हो गया। इसमें आ गया है। उसको अलग से लिखकर दीजियेगा।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, कम से कम सुन तो लीजिये।

श्री राजेश मूणत :- अब फिर आबकारी में कुछ बोलेंगे।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह गांव की महिलाओं की मांग है, सुन तो लीजिये । माननीय उप मुख्यमंत्री जी, निवेदन है कि वह अभी भी बैठी हुई हैं अगर हो सके, ग्राम पंचायत भी लिखकर दे दिये हैं कि हम अपने गांव में नहीं खुलवाना चाहते हैं । कलेक्टर महोदय से भी बात हुई है ।

सभापति महोदय :- आपकी बात रिकॉर्ड में आ गयी ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से गृह विभाग के बारे में सब-कुछ बताया । राजधानी में पुलिस विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है जब से कमिश्नर प्रणाली आयी है । (मेजों की थपथपाहट) कईयों को दर्द जरूर होगा, किसी ने कहा कि ड्रोन से फोटो ले रहे हैं, घर में पियो न भई, किसने मना किया है और पीने वालों का लाईसेंस बना लो, आप तो चखना घर खोल-खोलकर परेशान हो गये, आधे जेल में, आधे बेल में और आधे इंतजार में, इसमें काहे परेशान हो ? लेकिन मेरा एक सुझाव है कि राजधानी में जो सूखा पदार्थ आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए जिस प्रकार का रैकेट चल रहा है। अगर कोई ऐसे लोग जो इसकी सूचना दें, आप जिसकी नेटवर्क को तोड़ना चाहते हैं तो पुलिस विभाग जितने का माल पकड़ाएगा, क्या उसके ऊपर कोई ईनाम की घोषणा करेंगा। जैसे एक्साईज़ में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कोई माल पकड़ाता था, कस्टम ड्यूटी में माल पकड़ाता था, उसमें कुछ मिलता है। अगर इस प्रकार से हमें कहीं से कोई सूचना मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी क्या है कि जो सूचना तंत्र होता है, उसका नाम उजागर हो जाता है और बाद में न्यूसेंस वैल्यू उनसे बदला लेती है। हम समाज में जागरण की दृष्टि से ऐसा कर सकते हैं। खासकर मेरे विधान सभा में एक आग्रह करना चाहता हूँ यहां पर जितने शिक्षण संस्थान हैं, वह मेरी विधान सभा क्षेत्र में है लगभग वहां पर 20 से 22 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं चाहे वह एन.आई.टी. हो, आयुर्वेदिक कॉलेज हो, साईंस कॉलेज हो, रविशंकर विश्वविद्यालय हो तथा वहां जितने हॉस्टल्स हैं और इसके आसपास जितना सूखा नशे का पदार्थ बिक रहा है, इन थानों को चिन्हित कर दें। एक इसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से विचार कर दें। मेरा यही निवेदन है।

सभापति महोदय :- आप उसके ऊपर विचार कीजिएगा।

श्री संदीप साहू :- माननीय सभापति महोदय, बेमेतरा का एक छोटा सा विषय है।

सभापति महोदय :- अब हो गया। इसमें बहुत चर्चा हो गई ।

श्री संदीप साहू :- माननीय सभापति महोदय, बेमेतरा का एक छोटा सा विषय है। यह बहुत गंभीर विषय है।

सभापति महोदय :- अगला ध्यानाकर्षण राघवेन्द्र कुमार सिंह।

(2) जांजगीर-चांपा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कियान्वयन में अनियमितता की जाना.

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह:- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

भारत सरकार द्वारा आम नागरिकों को सुलभ, किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की गई थी, किन्तु प्रदेश के जांजगीर-चांपा जिले में जमीनी स्तर पर इनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। जिले का स्वास्थ्य महकमा गरीब लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं का सही ढंग से कियान्वयन नहीं हो रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रम जैसे:- टी.बी. (क्षय रोग), मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ रोग नियंत्रण, मोतियाबिन्द ऑपरेशन, सिकलसेल (एनीमिया) एवं अन्य कार्यक्रमों की न तो नियमित स्क्रीनिंग हो रही है और न ही उनका उचित उपचार किया जा रहा है। इस वर्ष जिले में संदिग्ध मरीजों की पहचान, जांच व ईलाज का लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 30-35 प्रतिशत के आसपास है, जो अत्यंत चिंताजनक है। इतना ही नहीं सिकलसेल (एनीमिया) की जांच में जांजगीर-चांपा जिले की स्थिति प्रदेश में सबसे अंतिम पायदान पर है। सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के हर ब्लॉक में सिकलसेल स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित करने एवं हर नागरिक को सिकलसेल (एनीमिया) कार्ड जारी करने का वादा किया था, किन्तु यह घोषणा धरातल पर दूर की कौड़ी प्रतीत होती है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से क्षेत्र की गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूरन निजी अस्पतालों में उपचार कराने जाना पड़ रहा है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो गरीब और ग्रामीण आबादी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएगी। उचित उपचार नहीं मिलने से आम लोगों में शासन-प्रशासन के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- यह कहना सही है कि भारत सरकार द्वारा आम नागरिकों को सुलभ, किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, किन्तु यह सही नहीं है कि प्रदेश के जांजगीर-चाम्पा जिले में जमीनी स्तर पर इनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। जिले का स्वास्थ्य महकमा गरीब लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, वस्तुस्थिति यह है कि जिले में 01 जिला अस्पताल, 01 सिविल अस्पताल, 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ही 155 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) संचालित हैं। इनके माध्यम से जिले की जनता को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से जनवरी, 2026 तक जिला अस्पताल जांजगीर में ओ.पी.डी. के माध्यम से 1,14,090 मरीज एवं आई.पी.डी. के माध्यम से 10,245 मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा चुकी है। जिला अस्पताल में 83 मेजर सर्जरी एवं 279 मरीजों की माइनर सर्जरी के माध्यम से सेवायें दी गई हैं। जिला अस्पताल में इस अवधि में लैबोरेटरी के माध्यम से 3,01,317 जांच एवं एक्स-रे के माध्यम से 14,218 मरीजों को एवं सोनोग्राफी के माध्यम से 2767 मरीजों को सेवायें प्रदान की गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जनवरी, 2026 तक जिला अस्पताल में 2196 प्रसव कराया गया है, जिसमें से 1446 सीजेरियन सेक्शन के माध्यम से कराया गया है।

यह कहना भी सही नहीं है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रम जैसे :- टी.बी. (क्षय रोग), मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ रोग नियंत्रण, मोतियाबिन्द ऑपरेशन, सिकलसेल (एनीमिया) एवं अन्य कार्यक्रमों की न तो नियमित स्क्रीनिंग हो रही है और न ही उनका उचित उपचार किया जा रहा है। सही यह है कि मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 19,193 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया जा चुका है तथा उनमें से 98.62 प्रतिशत का 04 या उससे अधिक ए.एन.सी. जाँच की गई है। जिले में कुल प्रसव के विरूद्ध संस्थागत प्रसव 99.99 प्रतिशत है। जिले में कुल 18,679 शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण किया गया है तथा चिरायु कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,91,142 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 96.9 प्रतिशत बच्चों का उपचार किया जा चुका है। जिले में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 14,999 संदेहास्पद व्यक्तियों की जांच कर, कुल 967 टी.बी. मरीजों की पहचान कर उपचार किया गया है, जिनमें अपेक्षित उपचार सफलता दर 95 प्रतिशत है।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत रक्त पट्टी परीक्षण संख्या लक्ष्य के विरूद्ध 117 प्रतिशत है तथा धनात्मक कुल 13 मरीजों का शत प्रतिशत उपचार किया गया है। कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 181 धनात्मक मरीजों के 6439 संपर्क व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है एवं शत प्रतिशत पी.ई.पी. की दवाई का सेवन कराया जा चुका है। जिले का कुष्ठ प्रभाव दर प्रति 10,000 की जनसंख्या में 1.52 है, जो राज्य के औसत कुष्ठ प्रभाव दर 1.84 से कम है। जिले में इस वर्ष दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक कुल 2166 मरीजों के मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कर उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान की गई है।

यह कहना भी सही नहीं है कि सिकलसेल (एनीमिया) की जांच में जांजगीर-चाम्पा जिले की स्थिति प्रदेश में सबसे अंतिम पायदान पर है। सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के हर ब्लॉक में सिकलसेल स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित करने एवं हर नागरिक को सिकलसेल (एनीमिया) कार्ड जारी करने का वादा किया था, किन्तु यह घोषणा धरातल पर दूर की कौड़ी प्रतीत होता है। वस्तुस्थिति यह है कि सिकल सेल (एनीमिया) हेतु जिला जांजगीर-चांपा में लक्षित जनसंख्या 6,89,899 के विरुध्द 6,93,283 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। सिकल सेल

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

चिन्हांकित सभी मरीजों का नियमित उचित उपचार किया जा रहा है। प्रदेश में जांजगीर-चांपा जिले की स्थिति सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्य में राज्य स्तर पर 9वें पायदान पर है। सरकार द्वारा अपनी घोषणा पत्र में प्रदेश के हर ब्लॉक में सिकलसेल स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु प्रदेश के कुल 146 विकासखण्डों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सिकलसेल स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित किया जाना है। अतः योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में राशि रु. 500.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला जांजगीर-चांपा के अन्तर्गत 3,89,013 नागरिकों को सिकलसेल जेनेटिक कार्ड वितरित किया गया है। जिले में चिन्हांकित सिकलसेल मरीजों को निःशुल्क दवाईयां, निःशुल्क ब्लड ट्रान्सफ्युजन एवं परामर्श संबंधित सेवायें दी जा रही है। यह सही नहीं है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से क्षेत्र की गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूरन निजी अस्पतालों में उपचार कराने जाना पड़ रहा है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो गरीब और ग्रामीण आबादी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएगी, अपितु सही यह है, कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र की गरीब और ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाए निःशुल्क प्रदान की जा रही है। अतः आम लोगों में शासन-प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, आपकी ओर से जो जवाब दिया गया है, उसमें आपने कई आंकड़े दिए हैं, जिसमें मैं आपका ध्यानाकर्षण उन्हीं आंकड़ों की तरफ ले जाना चाहूंगा । इतने लंबे समय 1 अप्रैल से लेकर जनवरी तक जिला अस्पताल में 83 सर्जरी तक नहीं हो पाई । उसके बाद इसमें बच्चों के उपचार की बात हो रही है । माननीय मंत्री जी, आप मोतियाबिन्द आपरेशन का आकड़ा पढ़ रहे हैं, आप ही के विभाग का आकड़ा है कि दिसम्बर,2025 तक सिर्फ 15 आपरेशन हुए थे। इसका मतलब है कि क्या बाकी आपरेशन बाहर किए जा रहे हैं ? जांजगीर चाम्पा में सिकलसेल की बहुत दिक्कत है, इस बात से सब अवगत हैं। 6 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग तो की गई है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो वह आकड़ा 3 हजार से ऊपर नहीं गया है, यह आपके जवाब का आकड़ा है। मंत्री जी, मैं आपको आपके कुछ और आकड़ें बताना चाहूंगा। क्योंकि पूरे एन.एच.एम. को लेकर मेरा सवाल था। आपके विभाग ने सिजेरियन का जो जवाब दिया है उसमें प्रसव के बाद 48 घंटे तक जो महिलाएं अस्पताल में रूकीं, क्योंकि उनका सिजेरियन हुआ, उसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

96 तो अकलतरा में थे। बलौदा-0, बम्हनीडीह-0, जांजगीर अर्बन-0, नवागढ़-0, पामगढ़-0 है। ये आपके विभाग का यह आकड़ें हैं।

माननीय मंत्री जी, एनीमिया मुक्त भारत की बात हो रही है। ओव्हर आल दिसम्बर तक का आकड़ा दे दिया है कि 96% है। लेकिन अगर ब्लाकवार समीक्षा करेंगे तो अकलतरा ब्लाक सिर्फ 41% है। इसके बाद फैमिली प्लानिंग की बात करें तो Permanent Method of Serialization है, इसमें अकलतरा 14%, बलौदा-0, बम्हनीडीह-0, जांजगीर-0, नवागढ़-0, पामगढ़-0 है। ये आप ही के आकड़ें हैं। हम लोग सिकलसेल की बात कर रहे हैं, मंत्री जी आप लगभग उस जिले से लगे हुए हैं। आपका कोरबा जिला है। आपको वहां की वस्तुस्थिति पता है कि वहां सिकलसेल की कितनी दिक्कतें आती हैं। आपके आकड़ें स्वयं बता रहे हैं कि आपने 6 लाख से ऊपर लोगों का सिकलसेल स्क्रीनिंग किया है। लेकिन कार्ड वितरण सिर्फ 52% लोगों को हुआ है। अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो हमारे यहां कलेक्शन ही 2,903 यूनिट हुआ है। हम लोग लाखों की बात कर रहे हैं और जब हम लोग सिकलसेल की बात करते हैं तो आपको पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। यहां पर मोतियाबिंद की बात हुई, हम वहां पर लगातार आपरेशन कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमने जांजगीर-चाम्पा जिले में सिर्फ 47% टारगेट ही एचीव किया है। उसमें भी दिसम्बर, 2025 का आकड़ा इनके विभाग के द्वारा दिया गया है कि जिला अस्पताल में 15 से 20 सर्जरी हुई है तो बाकी सर्जरी क्या प्रायवेट में हो रही है? अगर ऐसा है तो हम जिला अस्पताल में क्या कर रहे हैं। बाकी हम लोग शासकीय अस्पतालों में क्या कर रहे हैं ? ये आकड़ें हैं। लेकिन मैं आकड़ों में जाना नहीं चाह रहा था। चूंकि इसमें आकड़ों की बात आई है इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, डायबिटिज और हायपर टेंशन, ये तो बहुत सामान्य सी चीजें हैं, जिसका हमें रेग्युलरली चेकअप करना चाहिए। 30 दिसम्बर, 2025 तक के आकड़ें हैं। हमने बी.पी. जांच में सिर्फ 37% का टारगेट एचीव किया है और डायबिटिज की जांच में 33% टारगेट एचीव किया है। यहां पर डायबिटिज और बी.पी. तक की जांच नहीं हो पा रही है।

सभापति महोदय :- आप सीधा प्रश्न पूछिये कि आप क्या चाह रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सीधा आकड़ें बता रहा हूं। मंत्री जी ने जो आकड़ें बताये हैं, चाहे ओरल ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल का हो, सर्वाइकल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कैंसर की जांच में हम लोग 38% पर हैं। हमारा जिला लगभग एन.एच.एम. या बाकी जो कार्यक्रम है, वह नीचे है। हम लोग ओव्हरल प्रोग्राम से नीचे हैं। हम लोग डिलिवरी की बात कर रहे हैं, हम लोग उसमें नीचे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके एक और आकड़ा रखना चाहता हूं। अगर हम शिशु स्वास्थ्य की बात करें तो बी.सी.जी. वैक्सीनेशन तक टारगेट का 60% एचीव किया हुआ है। अगर हम इन पायदानों से नीचे चल रहे हैं तो माननीय मंत्री जी इस बात बताने का कष्ट करें कि आखिर यह व्यवस्था कैसे सुधरेगी ? आयुष्मान का पैसा नहीं जा रहा है, लोगों का ईलाज नहीं हो पा रहा है, जो स्वास्थ्य मिशन से सारी चीजें चलनी है, वह चल नहीं पा रही है। माननीय मंत्री जी, आप इसका जवाब दें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, राघवेन्द्र जी युवा और जागरूक विधायक हैं। क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। परन्तु मैं बताना चाहूंगा कि आपने जैसा प्रश्न पूछा था, मैंने उसका जवाब तो दिया है। परन्तु हमारी नीचे तक की संस्थाएं हैं, आपको मालूम ही है कि जिला अस्पताल के साथ ही साथ एक सिविल अस्पताल भी है। स्व. बी.डी. महंत के नाम से है। हमारे यहां 8 सी.एस.सी. हैं, 25 पी.एच.सी. हैं। 133 ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मन्दिर है, तो अगर इतने बड़ी संस्थाओं में अगर आपको संस्थावार जानकारी चाहिए तो वह भी दे दूंगा, लेकिन कुछ आंकड़े जो आपने कोट (Quote) किया है, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बजट में 2000 का बेस मानते हैं, लेकिन उतना लम्बा हम नहीं मानेंगे। पिछले दो साल पहले जब से हमारी सरकार का यहां जिम्मा हमको मिला तो मैं बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में पूरे जिले का जो ओ.पी.डी. था, 11,74,635 था और अभी की स्थिति में 31 दिसंबर तक इस साल में 14,23,417 है। मतलब लगभग 37 प्रतिशत ओ.पी.डी. हमने बढ़ाया। आई.पी.डी. की बात करेंगे, तो आई.पी.डी. भी उस कालखंड में 29,986 था जो अभी 31 दिसंबर तक में 32,860 है जो 25 प्रतिशत ऊपर है। यदि सुविधा नहीं होगी तो ये बढ़ेगा कैसे? और बाकी चीज़ों को भी मैं आपको बता देता हूं कि सिकल सेल और अन्य चीज़ों की भी आपने जो जानकारी चाही है जैसे टी.बी. का उस कालखंड में 22,692 स्क्रीनिंग उस समय हुआ था। लेकिन हमारे समय पिछले साल में, इस साल का रिकॉर्ड आया नहीं है, 49,710 लोगों का हुआ है, जो 120 प्रतिशत हुआ। वैसे यह क्षेत्र लगभग मलेरिया मुक्त है, 13 लोग ही कुल पॉजिटिव मिले, फिर भी हमने लगभग 2,23,000 लोगों का चेक किया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कुष्ठ उस क्षेत्र में है, मैं जानता हूं कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में है, जिसमें जांजगीर-चांपा भी प्रभावित है। उसको हम विशेष फोकस किए हैं और यही कारण है कि 2,23,896 लोगों का हमने कुष्ठ का भी जांच किया जो हमारी सरकार बनने के उस समय 2023 में एक साल में कुल 1,05,000 हुआ था। तो हमने डबल स्क्रीनिंग किया। मोतियाबिंद की जैसे आप बात कर रहे थे, तो मोतियाबिंद का जो आंकड़ा है, इस साल 2,478 लोगों का हमने उपचार किया है, 2,756 उसमें पॉजिटिव मिले थे..।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, इसमें आप बता दीजिए, सरकारी अस्पतालों में कितना हुआ है और प्राइवेट में कितना हुआ है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं सरकारी का ही आंकड़ा दे रहा हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- नहीं, मेरे पास आपकी ही रिपोर्ट है, ये सरकारी आंकड़ा नहीं है। सरकारी अस्पताल का नहीं है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए सुनिए ना, मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं, सदन में तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- नहीं, मंत्री जी, यह आंकड़ा सरकारी नहीं है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपको हॉस्पिटल-वाइज अलग से दे दूंगा कि कहां-कहां है। वैसे सामान्यतः जो है मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन जिला अस्पतालों में ही हम अभी ज्यादा कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जहां-जहां सी.एच.सी. में व्यवस्था है, वहां कर रहे हैं। नीचे पी.एच.सी. वगैरह में हम नहीं कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है मैं इस साल का आपको जो दिया हूं, वह तो रिकॉर्ड में है आप निकलवा भी लीजिएगा और आयुष्मान की जो आप बात कर रहे थे, तो आयुष्मान के माध्यम से पूरे जांजगीर-चांपा जिले में हम लोगों ने कुल जो संख्या है, एक मिनट आपको मैं यह जानकारी दे दे रहा हूं । आप जो पिछला पेमेंट वगैरह बोल रहे हैं कि बचा है, नहीं हो रहा है, पेमेंट रेगुलर हो रहे हैं। यह आयुष्मान का है, ये 11,28,000 हमको जो लक्ष्य मिला था, उसके विरुद्ध में हमने वहां 10,20,000 कार्ड बनाए हैं, जो 91 प्रतिशत है और वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करूं तो हमने 32,460 आयुष्मान के जो प्रकरण हैं, सिर्फ जांजगीर-चांपा जिले के प्रकरण का उन्हीं के हॉस्पिटलों में हम किए हैं, जो 38 करोड़ 16 लाख

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रुपये का उपचार हुआ है, जिसमें 19 करोड़ 96 लाख रूपये का हमने भुगतान भी कर दिया है और अभी भुगतान की प्रक्रिया चालू है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है। जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ है, सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज नहीं हो रहा है, मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं मंत्री जी। मोतियाबिंद सिर्फ हम लोग 54 प्रतिशत कर पाए हैं। अभी तक बहुत लोग वहां पर घूम रहे हैं और मधुमेह और कम से कम डायबिटीज और जो बेसिक चीजें हैं जैसे हाई बी.पी. की जांच होना, ये तक हम लोग 50 प्रतिशत नहीं पहुंच पा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और स्पेसिफिक आपसे निवेदन कर रहा हूं मंत्री जी, हमारे यहां जिला अस्पताल और अकलतरा सी.एच.सी. को छोड़कर डिलीवरीज़ नहीं हो रही हैं ब्लॉक्स में, सी-सेक्शन वाली। तो उसके लिए अब आप क्या आगे करेंगे, क्योंकि डिलीवरी एक ऐसी चीज है जो हर एरिया में कम से कम हम लोगों के लिए सी-सेक्शन आज कॉमन हो गया है। तो सी-सेक्शन के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, इसके बारे में आप बता दें। और ये जितने हम लोगों के परसेंट 45 या 50 से कम हैं जो हमने टारगेट नहीं अचीव किया है, ये अगले एक महीने में कैसे अचीव होगा, इसका आप स्पेसिफिक जवाब दे दें।

सभापति महोदय :- हां, मंत्री जी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, डिलीवरी दो प्रकार से होती है। एक तो सामान्य रूप से जो प्रसव है, वह हम कर रहे हैं और आपको खुशी होना चाहिए कि जिले का 99.99% हम संस्थागत प्रसव करा रहे हैं। मतलब घर में प्रसव का सिर्फ एकाध लोगों का हमारे रिकॉर्ड में है कि घर में प्रसव किन्हीं कारणों से हो गया होगा। जो बी.डी. महंत सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर सिजेरियन हो रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाकी जगहों में Gynecologist की कमी होने की वजह से हम महतारी एक्सप्रेस के माध्यम से लाते हैं और जिले के उन केंद्रों में डिलीवरी करा रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जांजगीर से सबसे ज्यादा दूर कोई हॉस्पिटल पड़ता है तो वह बलौदा क्षेत्र पड़ता है, जो कोरबा से लगा हुआ एरिया है। वहां स्थिति यह है कि बलौदा ब्लॉक में एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है, Gynecologist भी नहीं है और एक लेडी आर.एम. (RM) भी नहीं है। वहाँ पर अगर कोई प्रसव कराने हॉस्पिटल जाता है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो वहाँ से या तो वे बिलासपुर जा रहे हैं या कोरबा जा रहे हैं। वहाँ पर लेडी डॉक्टर की उपलब्धता ही नहीं है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- राघवेंद्र जी, वैसे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो आज तक कभी नहीं हुआ, वह हमारी सरकार ने आपको मेडिकल कॉलेज भी दे दिया, नर्सिंग कॉलेज भी दे दिया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मोला आर.एम. तो दे देवौ। मैं हर दू साल ले मांगत हौं, मंत्री जी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, यह बड़ा चीज हुआ, जो कभी-कभी 100 साल में होता है, हमने वह दो चीज दिया है। क्योंकि वह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी सहृदयता के साथ ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज दिये हैं। खैर वह तो अलग विषय है। माननीय सभापति महोदय, जो बलौदा क्षेत्र है, वहाँ हम संस्थागत सामान्य प्रसव करा रहे हैं और जो सिजेरियन है, उसके लिए नजदीक में महतारी एक्सप्रेस हमको तत्काल मिल जाता है और वहाँ से जिला केंद्र या जरूरत पड़ने पर वहाँ से कोरबा भी जाते हैं। लेकिन आप महिला चिकित्सक की मांग कर रहे हैं, उस पर मैं विशेष रूप से ध्यान भी दूँगा। हम उपलब्धता के अनुसार वहाँ भेजेंगे भी, वह हमारी प्राथमिकता में रहेगी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हाँ, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- भैया, पामगढ़ में भी भेज दीजियेगा। वहां महिला चिकित्सक नहीं है। पामगढ़ C.H.C. है, लेकिन अभी तक वह P.H.C. के सेटअप में है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, एक स्पेसिफिक प्रश्न है। मैं एक छोटी-सी बात रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- नहीं, हो गया। अभी बहुत सारी चर्चाएं होनी है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ कि जो इतने सारे आँकड़े रखे गए हैं और यह बोला गया। मंत्री महोदय जी एक बार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह आश्वासन दे दें कि मंत्री जी वहाँ या तो आ जाएँ, हम जनप्रतिनिधियों को भी बुला लें और वहाँ की जो वस्तुस्थिति है, जो इन आँकड़ों में शायद नहीं आ रही है। मंत्री जी, आप भी चाहेंगे कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार आ जाइए, आँकड़ों के साथ हम लोगों को बिठा लीजिए। क्योंकि आदरणीय प्रभारी मंत्री जी से तो हम लोग बहुत बार निवेदन किए हैं, लेकिन वे आते हैं, हम लोगों को बुलाते नहीं हैं। इसलिए कम से कम आप आ जाएँ और आप हम लोगों को एक बार बुला लें, फिर हम लोग आपको वस्तुस्थिति बता देंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवल :- देखिए, यह तो हमें खुशी होगी। आपके क्षेत्र में मेरा दौरा तो रहता ही है। मैं आपके जिले में गया भी हूँ, लेकिन बैठक नहीं ले पाया। वहां के प्रभारी मंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं। हम लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं देखते कि यह भा.ज.पा. का व्यक्ति है या कांग्रेस का व्यक्ति है। आप पूछ लीजिए कि मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहां-वहां मैं विधायकों को बुलाता ही हूँ। इसलिए निश्चित रूप से जब भी मैं आप लोगों के क्षेत्र में आऊँगा, तब हम आपके साथ बैठेंगे और जो भी हमारे विधायकगण हैं, वह समय निकालेंगे तो हमें खुशी होगी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- अभी मैं शून्यकाल की सूचनाएं दूंगा। आप लोग बैठिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी बीमारी है, जैसे शुगर, बी.पी. की दवाई की व्यवस्था थोड़ा सुनिश्चित कराइए। क्योंकि सी.एच.सी., पी.एच.सी. में दवाइयाँ नहीं हैं, शुगर की स्ट्रिप नहीं रहती है, लोग बाहर जाते हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, मैं पूरे सदन के सभी लोगों को बोलता हूँ कि अक्सर कई बार सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया में दिखता है कि यहाँ दवाई नहीं है, वहाँ दवाई नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा नंबर आप सभी के पास होगा। अगर कहीं भी दवाई की कमी है। चूंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और खरीदी के लिए भी हमने ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अभी ध्यानाकर्षण पर बहुत लंबी चर्चा हुई है।

एक माननीय सदस्य :- माननीय सभापति जी, मैं अंतिम पंक्ति की तरफ खड़ा हूँ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, दवाई रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि दिनांक 07.06.2023 को 544 उप-स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनाने के लिए आपने अनुमति दी थी। उसमें लगभग आधे से ज्यादा भवनों के निर्माण हो गए हैं, लेकिन उसके पैसे आवंटन के अभाव में अभी तक राशि जारी नहीं हुई। माननीय मंत्री जी, आपको दो-तीन बार पत्र भी दिया हूँ। कम से कम वह भवन निर्माण हो जाए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक मिनट। आप इकट्ठे जवाब दे देना। माननीय सभापति महोदय, यह मामला श्री राघवेन्द्र सिंह जी का है। वह मूल ध्यानाकर्षण है, सब लोग पूछेंगे तो यह मामला हल नहीं होगा । माननीय मंत्री जी, यह जांजगीर जिले का मामला है, आप मीटिंग लूँगा करके बोल दीजिए । मीटिंग लेकर उसको हल कर दीजिए और कार्यवाही आगे बढ़ाईये ।

सभापति महोदय :- अब मैं शून्यकाल की सूचनायें लूँगा ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- वह अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी जिज्ञासा को ठीक कर लें । राघवेन्द्र जी आप तो संतुष्ट हो गये हैं ना ।

श्री राघवेन्द्र सिंह :- मंत्री जी, अभी एनाऊंस कर दीजिए । अगले महीने एनाऊंस तो कर दीजिए कि आप आगे मीटिंग लेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 1.31 बजे **<u>नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>**

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा:-

1. श्री सुनील कुमार सोनी
2. श्री रोहित साहू
3. श्री उमेश पटेल
4. श्री विनायक गोयल
5. श्रीमती अंबिका मरकाम

समय: 1.32 बजे

<u>अनुपस्थिति की अनुज्ञा</u>

1. श्री दयालदास बघेल, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-70 नवागढ़

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-70 नवागढ़ के सदस्य श्री दयालदास बघेल द्वारा फरवरी-मार्च 2026 सत्र में दिनांक 23 फरवरी 2026 से दिनांक 27 फरवरी 2026 तक सभा की बैठक में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है । उनका आवेदन इस प्रकार है :-

आवश्यक कार्य हेतु छत्तीसगढ़ से बाहर जाने के कारण मैं फरवरी-मार्च 2026 सत्र में दिनांक 23 फरवरी 2026 से दिनांक 27 फरवरी 2026 तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा । उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 70 नवागढ़ के सदस्य श्री दयालदास बघेल द्वारा फरवरी-मार्च 2026 सत्र में दिनांक 23 फरवरी 2026 से दिनांक 27 फरवरी 2026 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये ।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है । माननीय सदस्य को अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई।

2. श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-01 भरतपुर सोनहट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-01 भरतपुर सोनहट की सदस्य श्रीमती रेणुका सिंह सरूता द्वारा फरवरी-मार्च 2026 सत्र के दौरान सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है । उनका आवेदन इस प्रकार है :-

स्वास्थ्यगत् कारणों से मैं फरवरी-मार्च 2026 में सत्र की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊँगी । उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-01 भरतपुर सोनहट के सदस्य श्रीमती रेणुका सिंह सरूता द्वारा फरवरी-मार्च 2026 सत्र में सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये। मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है। माननीय सदस्य को अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई।

समय: 1.33 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुये)**

समय: 1.34 बजे **<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>**

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

1. श्रीमती भावना बोहरा
2. श्री रोहित साहू

समय: 1.35 बजे

<u>माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

सभापति महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, तीसरे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, मैं आज से 26 साल पहले मध्यप्रदेश के विधान सभा में कृतज्ञता ज्ञापन पेश किया था और 26 वर्षों के बाद आज मुझे यह अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष ने, जो दिया है उसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद । सभापति महोदय, मैं ऐसे मुख्यमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव के लिये खड़ा हूँ...।

श्री भूपेश बघेल :- धर्म भैया, आप राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता प्रस्तावक हैं और बोलने के लिए खड़े हुए हैं लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ट्रेजरी बेंच पूरा खाली है और जो अधिकारी दीर्घा है वह भी पूरा खाली है। एक तो यह सरकार राज्यपाल के अभिभाषण पर पहली बार ऐसा हुआ है कि उसमें चर्चा किए बिना बजट ले आई। दूसरा यह देख लीजिए कि सत्ता पक्ष के लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल एक-दो मंत्री बस बैठे हैं। अधिकारी दीर्घा तो पूरा खाली है, जब तक अधिकारी लोग ना आ जाएँ, क्योंकि आप बोलेंगे और उसको कोई नोट करने वाला नहीं है।

सभापति महोदय :- अधिकारी बैठे हुए हैं।

श्री भूपेश बघेल :- कौन बैठा है, कौन-कौन अधिकारी है भई ?

सभापति महोदय :- देखिए न उधर बैठे हुए हैं। वे फ्रंट में नहीं हैं, पीछे बैठे हुए हैं, इसलिए दिख नहीं रहा है। आप शुरू करिए।

श्री भूपेश बघेल :- बाहर में चपरासी वगैरह हों, उन्हें लाकर सामने बैठा दीजिए भाई। (हंसी) हमें तो अधिकारी से मतलब है, वह भरा रहना चाहिए।

सभापति महोदय :- मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, आप शुरू कीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- मुख्यमंत्री बैठे हैं लेकिन अधिकारी कहां हैं ?

सभापति महोदय :- मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आप शुरू कीजिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय, आपकी आपत्ति मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है और इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) मैं उस मुख्यमंत्री की सरकार का कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए खड़ा हूँ जो इस प्रदेश की 31 प्रतिशत गरीब आदिवासी परिवार के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) उन्हें श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश के 3 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने का अवसर दिया है और उन्होंने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में अपने कामों से यह बताया है कि इस प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और आदिवासी तथा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण की क्या-क्या योजनाएँ कर सकते थे। सभापति महोदय, चुनाव के पहले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी पार्टी के नेताओं ने भी इस प्रदेश का दौरा किया। इस प्रदेश के दौर में चुनाव के समय जनता से आपने भी वादा किया और हमने भी वादा किया। उन वायदों में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो-जो गारंटियाँ दी थीं, सरकार बनने के बाद 100 प्रतिशत उसका अक्षरशः पालन हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने किया। पूरे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं का सम्मान होना, उनको हर जगह समर्थन देना और हर जगह अवसर देना, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है। इसीलिए पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में भी 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने एक योजना लॉन्च की - ''महतारी वंदन योजना''। इस योजना में हम 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपये देने का क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया:

जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता बसते हैं, यह हमारे मुख्यमंत्री जी का मूल ध्येय है। इसीलिए हम इस प्रदेश की आधी आबादी माताओं और बहनों की तकदीर और तस्वीर को सँवारने का काम कर रहे हैं । उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, पदों को देने के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं कोई बहुत तैयारी करके भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आँकड़े नहीं बोलूंगा। मैं दो, चार, पाँच बिंदुओं को बोलकर अपना भाषण खत्म भी कर दूँगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश का निर्माण किया। यह जानते हुए भी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन्होंने इस प्रदेश का निर्माण किया। इस प्रदेश के लिए कोई खूनी क्रांति नहीं की गई, इस प्रदेश के लिए कोई बहुत बड़ा हिंसा भी नहीं हुआ था। इस प्रदेश को माँगने पर एक महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका निर्माण किया। इसीलिए आज हम 25 साल से छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय धरम भैया, आपने भी इस बात का समर्थन किया कि अधिकारी दीर्घा में अधिकारी नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, उस समय भी मैंने कहा कि ट्रेजरी बेंच से कोई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, लेकिन न मुख्य सचिव हैं, न अपर मुख्य सचिव हैं, न प्रमुख सचिव हैं। कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं और इतनी गंभीर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी तो नदारत हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब अधिकारी लोग आ जाएं, तब आप हम लोगों को यहां बुलवा लीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे।

समय : 1.41 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोध में.</u>

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

<u>माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर):- माननीय सभापति महोदय, राज्य की स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ की इस नयी विधानसभा में जहाँ हम खड़े होकर आज कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, इसका उद्घाटन व लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इसके शिलान्यास पर भी जाना चाहता हूँ। जब इसी भवन का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शिलान्यास हुआ था तो हम सब as a MLA यहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन वह शिलान्यास, जो लोग संविधान की बात करते हैं, दो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग नीचे थे और जो संवैधानिक पद पर नहीं थे, उन लोगों ने इस भवन का शिलान्यास किया। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, हमारी पार्टी संविधान में आस्था रखती है और इसीलिए जब इसका उद्घाटन हुआ, तो पांच-पांच संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस शानदार मंदिर और इमारत के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी थे, माननीय राज्यपाल जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी थे, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी थे। इस तरह से हमने इस संसदीय मंदिर को, संसदीय कार्यवाही के इस मंदिर को संसदीय पदों पर बैठे हुए लोगों के हाथ से लोकार्पण कराया। यह इस सरकार की संसदीय व्यवस्था में और संविधान के ऊपर आस्था का प्रतीक है। इसलिए बार-बार जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, उन्हें संविधान के बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) हम इस साल को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। 25 लाख 24 हजार किसानों से समर्थन मूल्य पर 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है और हम लोगों ने 33,431 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। कृषक उन्नति योजना के तहत होली के पहले 10,292 करोड़ रूपये का भुगतान करने का निर्णय हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया है। हम छत्तीसगढ़ के 24 लाख 72 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देने जा रहे हैं। भूमिहीन कृषक मजदूरों का भी इस सरकार ने ख्याल रखा है। राज्य के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषक मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोदो और रागी जैसे मिलेट्स की खेती में बहुत संभावनाएं हैं। इनके बीजों की आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। खेती-किसानी से जुड़ी अर्थव्यवस्था बिना पशुपालन और मछली पालन के नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. किया है और सहकार से समृद्धि योजना के तहत 488 नवीन डेयरी समितियों का गठन किया गया है। महासंघ द्वारा दूध का क्रय मूल्य 35 से बढ़ाकर 36 रुपये 50 पैसे करके किसानों की तरक्की का काम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। ये मछली की खेती, डेयरी की खेती, ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण जनों के लिए साइड बिजनेस के रूप में बहुत बड़ा काम करती है और उनके जीवन का स्तर आगे बढ़ाने में काम आती है। छत्तीसगढ़ में 7,580 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य पालन का काम निजी क्षेत्रों में हो रहा है। सरकारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में जो काम हो रहा है, वह अलग है। हम इसे वर्ष 2047 तक तीसरे स्थान पर पूरे देश में लाने का प्रयास करेंगे। सभापति महोदय, ये लोग बोलते हैं कि वर्ष 2047 तक, वर्ष 2047 की बात करते हो। हां, हम बात करते हैं। वर्ष 2047 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि पूरा देश और छत्तीसगढ़ उसमें आगे रहे। यह हमने कहाँ कहा कि 2047 तक श्री विष्णु देव साय ही मुख्यमंत्री रहेंगे? यह हमने कहाँ कहा कि 2047 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे? सभापति महोदय, एक जिम्मेदार आदमी, एक जिम्मेदार शासक, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, एक जिम्मेदार राजनेता का यह धर्म होता है कि वह अपने देश, अपने प्रदेश और अपने क्षेत्र के विकास का दूरगामी रोडमैप रखेगा, तब उस दिशा में चलकर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आज ही हम आगे का नहीं सोचेंगे, तो आगे चलकर हम कुछ भी नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, सिंचाई हमारी बहुत प्राथमिकता में है। 2 वर्षों में श्री विष्णु देव साय की सरकार ने 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की वृद्धि की है, जिससे राज्य में कुल विकसित सिंचाई क्षमता 21,76,000 हेक्टेयर हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, 73,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई सुविधा में विस्तार और पुनर्स्थापन के लिए 477 सिंचाई योजनाओं के लिए 1874 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी दी गई है। हमारी सरकार ने मातृशक्ति के लिए प्राथमिकता से योजनाएं बनाई हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह जो अधिकारी दीर्घा है, उसमें कौन लोग बैठेंगे इसके लिए अध्यक्ष के स्थायी आदेश में कुछ निर्देश हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि अधिकारी दीर्घा में कौन से स्तर के अधिकारी बैठ सकते हैं और कौन से स्तर के नहीं और कौन से स्तर के लोग अभी बैठे हैं। आप अध्यक्ष के स्थायी आदेश देख लीजिए, उसमें निर्देश हैं। यदि उसका पालन नहीं हो रहा है तो उसके संबंध में आप व्यवस्था दीजिए कि यह पालन क्यों नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय :- ठीक है। आप जारी रखें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप इसमें आगे बढ़ें। उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। इस तरह की वृत्तियां बार-बार होंगी कि अध्यक्ष के स्थायी आदेश का उल्लंघन होगा।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आप जारी रखें। मैं उसमें दे रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर में व्यवस्था के बारे में बोल दीजिए कि बाद में दूँगा या पहले दूँगा।

सभापति महोदय :- आपने मेरे संज्ञान में इस बात को लाया है। मैं उसको बाद में लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, परंतु अभी जो मौजूद हैं, उसकी जांच अभी होगी तभी यह स्पष्ट होगा कि कौन से स्तर के अधिकारी को बैठना चाहिए और कौन से स्तर के अधिकारी बैठे हैं। बाद में उसकी रिलिवेंसी खत्म हो जाएगी।

सभापति महोदय :- मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्योंकि वह अध्यक्ष के स्थायी आदेश में है कि कौन-कौन बैठ सकते हैं और कौन-कौन नहीं बैठ सकते हैं। मैं उल्लंघन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वह तो उन लोगों की मर्जी है, वे जब आए तब आएं।

सभापति महोदय :- सभापति महोदय, माननीय विष्णु देव साय जी ने सिंचाई के क्षेत्र में 477 सिंचाई योजनाओं के लिए 1874 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। हमारी माताओं-बहनों के लिए हमने 137 महतारी सदन का निर्माण कार्य पूरा किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप अभी व्यवस्था देंगे कि बाद में देंगे कि कोई निर्देश जारी करेंगे ? आपकी कोई व्यवस्था आ जाए, मैंने प्रश्न उठाया है।

सभापति महोदय :- आपने मेरे ध्यान में लाया, मैंने उस बात को आपको बता दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, लेकिन अभी तत्काल में जो स्थितियां हैं, उसको देखकर आप जाँच करवा रहा हैं या कुछ भी उसमें आपके कोई निर्देश आ जाएं या कोई व्यवस्था आ जाए क्योंकि वह स्थाई आदेश में शामिल है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- इसमें दिया हुआ है कि इस दीर्घा में अवर सचिव के पद से अनिम्न शासन के वे अधिकारी बैठ सकते हैं जिनको सदन में चलने वाले कार्य के संबंध में उपस्थित रहना अपेक्षित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो मैं जानता हूँ इसलिए उसका उल्लेख किया। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जो लोग मौजूद है, यह स्थिति बदल जाएगी। उसका उल्लंघन हुआ है या उसका पालन हुआ है, उस संबंध में कोई नया निर्देश जारी होगा कि उसको ऐसे ही बनाए रखा जाएगा, मैं इसमें व्यवस्था चाहता था इसमें क्या होगा? जब तक इसमें व्यवस्था नहीं होगी तब तक गंभीरता समझ में नहीं आएगी। यह विधानसभा के संचालन का मामला है। यह आपके निर्देशों का मामला है।

सभापति महोदय :- अध्यक्ष के स्थाई आदेश में जो अधिकारी दीर्घा के बारे में दिया हुआ है ना मैंने उसी को पढ़ करके आपको बताया।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, अब मैं बोलूँ?

सभापति महोदय :- आप जारी रखिये। जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, 137 महतारी सदन पूर्ण कर लिए गए हैं और 212 महतारी सदन का निर्माण करवाकर हम हमारी माताओं-बहनों को गाँव में सुविधा देने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक वहां पर शांति न हो। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस सदन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस प्रदेश में आतंक का साया जो बस्तर और अन्य हमारे हिस्सों में था, वह साया हट चुका है और विकास का उजाला, विकास की रोशनी इस पूरे प्रदेश में फैली हुई है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, गृहमंत्री जी को और देश के यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये तय किया कि मार्च 2026 के पहले तक हम नक्सली हिंसा से इस देश को, प्रदेश को मुक्त करा देंगे। कभी आज से 20 साल, 02 साल, 04 साल पहले कोई भी नक्सली हिंसा खत्म होने की बात जब करता था तो लोग भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आज आपने देखा कि बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े वो नक्सली लीडर जिनके कारण पूरा बस्तर भयाक्रांत था, अशांत था, आज हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, 532 माओवादी न्यूटराइज किये गये हैं, 2704 माओवादी आत्मसमर्पण किये हैं, 2004 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। न केवल वह गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि धूर नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में नियद नेल्लानार नाम की योजना बनाकर

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

उन गावों में 17 विभागों की भागीदारी के साथ 25 कल्याणकारी योजनायें और 18 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ हम दे करके वहां पर शांति और अमन का पैगाम भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो विष्णुदेव साय ने किया है और ये बहुत ही बहादुरी का काम है। हमारा इतना सुंदर बस्तर जो केरल से बड़ा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, अब उनके समझ में तो आयेगी नहीं। आतंकवाद को जो बढ़ावा देते रहे, नक्सलवाद के ऊपर जो राजनीति करते रहे, वह नक्सल के विषय पर इतना अच्छा बोल रहे हैं, पह पलायन करके चले गये। हमारे बहन (माननीय सदस्या यशोदा नीलाम्बर वर्मा की ओर मुखाबित होते हुए) को धन्यवाद दूंगा, कम से कम उनकी तरफ से बैठी हैं, उसके लिए धन्यवाद। इस बहन का तो कम से हम हमारी तरफ से ताली बजाकर स्वागत कर दें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इनको बताता हूं और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी भी उसको सुनें। आप जैसा बोले न कि ये लोग चले गये हैं, नहीं समझेंगे। मैं इनको बताता हूं कि ये यहां पर क्यों आये थे और क्यों चले गये।

मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे

मुद्दा है कि सूरज को कैसे हटाया जाये।(मेजों की थपथपाहट)

अब आप विष्णुदेव साय जी सूरज हैं, आप चमकते हुए सितारे हैं। अगर मै कहूं कि आप जंजीर पिक्चर के अिमताभ बच्चन हैं और अभी भी कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन से कम नहीं हैं। (मेजों की थपथपाहट) सीधा आदमी, सरल आदमी, भोला आदमी, गरीबी को देखा हुआ आदमी, गांव की तकलीफ को देखा हुआ आदमी, गांव के लोगों की परेशानी में आंख के आंसू पोछना जिनका स्वाभाव है, वह आदमी, आपके नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि आप लोगों के दर्द को जानते हो और लोगों के दर्द की दवा भी जानते हो। अगर इनने दर्द दिया है तो दवा आप देंगे। सभापति जी, मैं तो और बोलूंगा। मुख्यमंत्री जी, जरा सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी सुनिये न, मैं आपके ही लिये यहां लाया हूं। अब ये तो हैं नहीं, आपको ही सुनाना पड़ेगा। सभापति जी, ये हमारे हर उसका विरोध करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(माननीय सदस्य रामकुमार यादव जी के सदन में आने पर)

श्री राजेश मूणत :- रामकुमार यादव जी, आईये, आपका स्वागत है।

श्री रामकुमार यादव :- आपका स्वागत मैं 2047 में करूंगा।

श्री राजेश मूणत :- तब तक वहीं बैठना। चलो, कम से कम हमारा एक भाई और सही दिशा में आया।

श्री धर्मजीत सिंह :- कौन सरकार चला रहा है, अभी पूछूंगा कि सरकार कौन चला रहा है। मुख्यमंत्री जी ये इस उम्मीद में बैठे हैं कि आप बहुत सज्जन आदमी हैं, इनको लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाये । आप बहुत भले इंसान हैं इसलिये लग रहा है कि यह राजनीतिक तिकड़मबाजी नहीं जानते करके और यह हमारी सरकार को बदनाम करने, उखाड़ फेंकने का सपना देख रहे हैं लेकिन मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि यह वह पार्टी है, जिसको मैं अभी समझा हूं । मैं तो आप सब लोगों में से जूनियर हूं, मैं जूनियर हूं, मेरा दांव-पेंच तो सब उधर का ही है । (हंसी) मैं उधर का सब जानता हूं, समझ गए न । उधर रहता न तो मैं उधर बात कर लेता लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं कि जिसकी जड़ें बंजर जमीन में पनपी हों । (वाह-वाह की आवाज) जिसकी जमीन बंजर जमीन में पनपी हों, जो दो लोकसभा सीट में रहे और वहां से जो देश में 15 साल से सरकार कर रहे हैं वह पार्टी उसका वजूद जिनकी जड़ें बंजर जमीन में पनपी हों, उसका वजूद गिरे हुए पत्तों से नहीं आंकते । (मेजों की थपथपाहट) हमारे गिरे हुए पत्तों को देखकर के हमारा वजूद, हमारी औकात, हमारी हैसियत, हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत मत आंकियेगा, धोखा होगा, धोखा और एक-बार आपको फिर से वहीं पर दो साल के बाद जाना होगा।

श्री रामकुमार यादव :- हुजूर, अगर आपके परमिशन हो तो।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, बोलना-बोलना । तोर बर फुल पॉवर हे।

श्री रामकुमार यादव :- ये जतका बोलत हें न ओ कांग्रेस के ही पढ़ाए-लिखाय ला बोलत हें।

श्री धर्मजीत सिंह :- तें नया बात का बताये भई। मैं तो खुद बोलत हंओं।

श्री सुशांत शुक्ला :- तें काय अनते बोलत हस का, उहू ला बता दे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो खुद बोला कि मैं इस पार्टी में सबसे जूनियर मैं ही हूं । उम्र में सबसे बड़ा हूं लेकिन जूनियर हूं और दांव-पेंच तो मैं उधर का ही जानता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- हम तो कहते हैं कि खाते इधर का और गाते उधर का।

श्री सुशांत शुक्ला :- रेस्टहाऊस में तो बईठ के नइ खाएस कम से कम।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं । सुनो, अर्जुन को कहा गया कि आप हमारे साथ रहिये तो अर्जुन ने यह कहा कि मैं पांडवों के साथ रहूंगा, अस्त्र रखा हूं, न शस्त्र चलाउं, रथ हांकओं और दांव बताओं । (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र नहीं रखूंगा, शस्त्र नहीं चलाउंगा, रथ हाकूंगा और दांव बताउंगा, सारे दांव मुझको मालूम हैं।

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- सरकारी रथ के कृष्ण हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे एक-एक दांव मालूम है, उसमें अभी थोड़ी देर के बाद आउंगा। हम अपने विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी के सारथी हैं । (मेजों की थपथपाहट) रथ चलायेंगे, इस प्रदेश में विकास की गंगा बहायेंगे और इसीलिये बस्तर में 146 सड़क, पुल-पुलियों के लिये 1109 करोड़ रूपये, सिर्फ बस्तर के लिये 1109 करोड़ रूपये । (मेजों की थपथपाहट)

(माननीय सदस्य, श्री रामकुमार यादव के सदन से बाहर जाने पर)

श्री राजेश मूणत :- कहां चले?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने इसी दो साल में 9 हजार करोड़ रूपये नगर के विकास के लिये बांटा है । (मेजों की थपथपाहट) आपको और क्या चाहिए ? न्यूयार्क बन जायेगा, सोचते हैं । वाशिंगटन बना दें, यह छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ रहने दो और उसमें जो विकास हो सकता है उसको करने का काम हम कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट)

(माननीय सदस्य, श्री दलेश्वर साहू एवं श्री रामकुमार यादव के सदन से बाहर जाने पर)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री राजेश मूणत :- चलो, एक और को ले जाओ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 728 मोबाईल टॉवर चालू किये गये हैं ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, वह दोनों चले । दो बेचारे, बिना सहारे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- कहां जा रहे हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, 449 मोबाईल टॉवरों को फोर जी में अपग्रेड किया गया है । शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं बस्तर की बात बता रहा हूं कि 31 नयी प्राथमिक शालायें, 19 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गये हैं । धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की संकल्पना को पूरा करने के लिये पी.एम.जन.मन. धरती आवा । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस पी.एम.जन.मन. योजना में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक गांव, छोटा सा गांव, बैगा गांव, वहां इस योजना में सड़क बनी और आजादी के पहली बार वहां पर कोई विधायक गया और पहली बार वह लोग सड़क देखे हैं । यह पी.एम.जन.मन. योजना की ताकत है । (मेजों की थपथपाहट) इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है । हमारे प्रदेश में एक ट्राईबल गेम हुआ, खेलो इंडिया के ट्राईबल गेम को बिलासपुर में आपने किया, ट्राईबल गेम में हमारे बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखायी । (मेजों की थपथपाहट) वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। हमारी ताकत क्या है, इनको हमारी ताकत मालूम होना चाहिए । माइकल किण्डो ओलम्पियन हमारे जशपुर-कुनकुरी का था, वहां माइकल किण्डो जैसे ओलम्पियन छुपे हैं, उनको निकालने का काम कौन कर रहा है, यह माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हमारी संस्कृति की झलक पूरी पूरी दुनिया में लोग देखना चाहते हैं। हमारी आदिवासी संस्कृति महान संस्कृति है, उनका खान-पान बोली, सभ्यता, वेशभूषा सब अलग है। मैं तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उनके करीब हमेशा जाता रहा हूँ मैंने इसी विधान सभा में यह कहा था कि अगर आपको इस दुनिया में जिंदा भगवान देखना हो तो आप किसी आदिवासी मां, बहन और बेटी को जाकर देखिये, उन गरीब आदिवासी को देख लीजिए, आपको भगवान क दर्शन हो जाएंगे। ये जबरदस्ती टीका चंदन वाला भगवान, भगवान तो वह भी है, लेकिन इनसे जिंदा भगवान कोई नहीं मिलेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं आवास में कहना चाहूंगा कि हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिलवाया । हमने दो सालों में उसकी मंजूरी दी, लेकिन पूर्व की सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। उस समय आपने मंजूरी क्यों नहीं दी ? क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम था और माननीय मोदी जी की फोटो थी। आपने इतनी नफरत से इस कार्यक्रम को निरस्त किया। हमारे गरीब लोग जो बेघर-बार थे, उनको घर नहीं मिला। यह बहुत ही अफसोस की बात है। राजनीति में इतनी ज्यादा नफरत भी ठीक नहीं होती है। नफरत से इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमने भर्ती में भी बच्चों को 5 साल की छूट दी है। हमने 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फॉरेस्ट में भी 643 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हम सेमीकन्डक्टर, आई.टी. फार्मा, ए.आई. जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। नया रायपुर में हमारी सरकार ने बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ 680 करोड़ की लागत से एम.ओ. यू. किया है। हम सबको बहुत हाई-फाई ईलाज कराना होता है तो हम लोगों को हैदराबाद, बॉम्बे और दिल्ली जाना पड़ता है। यहां बॉम्बे हॉस्पिटल की सुविधा मिलने से मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोग ईलाज करवायेंगे, यहां पर बालको का कैंसर हॉस्पिटल भी है और एम्स भी खुल गया है तो हम लोग इसे मेडिकल हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, नहीं तो आये दिन हम लोग प्लेन पकड़ते हैं और हैदराबाद जाते हैं। हमारे रायपुर को मेडिकल हब बनाना है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में दो वर्ष में 2 हजार 73 मरीजों का ईलाज हो चुका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन में पिछले दो वर्ष में 31 लाख 44 हजार से अधिक क्लेम प्रकरणों में 4 हजार 551 करोड़ रूपए का भुगतान किय गया है। इसका महत्व ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। जिसके घर में कोई बीमार हो, अगर वह हार्ट का मरीज हो, कैंसर का मरीज हो, किडनी का मरीज हो और अगर उसके घर में पैसा न हो तो वह अपने लोगों, प्रियजनों को मरते देखता है, लेकिन उसको कोई मदद नहीं करता है। तब हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी मदद करते हैं और आपने उन गरीबों को एक बार और जिंदगी देने का काम आपने किया है इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न कैडरों में 1639 पदों पर नियुक्ति प्रदान की है एवं 2300 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बाबा गुरू घासीदास के आश्रम, धाम को भी पुण्य भूमि को सहेजने का काम चल रहा है। वहां आप 162 करोड़ के विकास काम करवा रहे हैं।(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, यहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में 7 करोड़ से अधिक पेड़ लगे। अब इसका विरोध इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस एक पेड़ मां के नाम अभियान का आव्हान किया । उन्होंने यह थोड़ी कहा था कि आप उनकी मां के नाम से पेड़ लगाईये। उन्होंने यह कहा था कि हर कोई अपनी मां के नाम से पेड़ लगाईये। यदि किसी की मां जिंदा है तो आप पेड़ लगा लीजिए और यदि किसी की मां जिंदा नहीं है तो भी एक पेड़ लगा लीजिए। अपनी मां की पूजा करिये। अपनी मां की याद में उस पेड़ को लगाईये। प्रधानमंत्री जी ने कहा है और नरेन्द्र मोदी जी आपके विरोधी हैं तो यह एक अलग विषय है। यह कहा जाता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो मां के कदमों में है(मेजों की थपथपाहट) और उस जन्नत को...।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- इन तीनों महतारियों ने पेड़ लगाया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह महतारियां ठीक हैं।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो पेड़ कटा है, वह किसके नाम से कटा है?

श्री धर्मजीत सिंह :- वह सब गड़बड़ घोटाले के नाम पर है। वह गड़बड़ घोटाले में पेड़ कटता है। मैं कुछ बातों की ओर और ध्यान आकृष्ट करूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा।

श्री सुशान्त शुक्ला :- वह जो पेड़ कटा था, वह बाबा के नाम का था तभी तो हमारा विधायक मंत्री बनकर आया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, और भी बहुत से विकास के काम हैं, उसको हमारे अन्य साथी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं । खासकर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, आप लोग जरूर सुनिएगा । आप लोग सुनिए न, मैं बढ़िया-बढ़िया बात बताने जा रहा हूं । ये लोग हमारी गलती निकालते हैं । पी.एस.सी. में भर्ती का काम आपकी सरकार में आपको मिला था । आपने ठीक से भर्ती क्यों नहीं की ? नेताओं के बच्चे क्यों डिप्टी कलेक्टर बन गए और एक गरीब का बेटा जो डिप्टी कलेक्टर के लायक है, वह बेचारा बाहर रह गया । इतना बड़ा अफरा-तफरी कैसे किसी सरकार के संरक्षण में हो गया । मैं आपकी ओर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था और आपकी सरकार को भनक तक नहीं लगी और वहां पर हमारे गरीब बच्चों के साथ अन्याय किया गया, लेकिन हमने उसको बदल दिया । हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को पारदर्शी बनाया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यापक जांच करा करके उसको हमने सजा देने का काम किया है । (मेजों की थपथपाहट) ये है-विष्णु देव सरकार में और आप में अंतर ।

सभापति महोदय, हमारी पार्टी में बहुत भिन्नता है, ये मंत्री नहीं आये, वह नहीं आये । वह इस रंग का कपड़ा पहने, वह उस रंग का कपड़ा पहनें । यहां पर ये नहीं बैठे, वे नहीं बैठे, ये सब चलता है । इस सदन में मैं यहां पर बैठा करता था । यहां पर टी.एस. बाबा बैठते थे । टी.एस. बाबा के ऊपर वहां बैठे बृहस्पत सिंह ने आरोप लगाया था कि मेरे हत्या की साजिश टी.एस. बाबा ने रची । उसका क्या हुआ? या तो वे असत्य कह रहे थे या बाबा हत्या करा रहे थे या बाबा सही थे तो वे असत्य बोल रहे थे । दोनों ही आप के लोग थे । इस सरकार में ऐसा तो नहीं हो रहा है । हमारे मंत्रियों या विधायकों के ऊपर इस प्रकार की बातचीत हम लोग नहीं करते हैं और इस तरह से छवि करके टी.एस. बाबा को यहां से इस्तीफा देकर एक विभाग को छोड़कर यहां से जाना पड़ा था । (शेम-शेम की आवाज) आबकारी की गड़बड़ी हुई, डी.एम.एफ. में गड़बड़ी हुई, रेत में घोटाला हुआ । इस प्रदेश में उस वक्त एक नया कल्चर शुरू हुआ-सी.डी. का। सबसे पहले अजीत जोगी के खिलाफ सी.डी. चली, जो मंतुराम पवार वाली थी । उसे गली-गली, घूमा-घूमा कर देखा गया । उसमें एक तीर से दो निशाना हुआ । अजीत जोगी को भी निपटाओ और रमन सिंह को भी निपटाओ। क्या हुआ, वह मामला कहां है ? वह मामला कोर्ट भी गया, पर उस मामले का क्या हुआ ? दूसरा सी.डी. एक नेता को बदनाम करने के लिए आया । ये क्या है ? प्रजातंत्र में हमारे मतभेद हो सकते हैं, प्रजातंत्र में हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं । प्रजातंत्र में हम एक दूसरे के बारे में बोल ही सकते हैं, लेकिन मुझे जब भी अवसर मिला है, मुझे जब भी अवसर मिलेगा तो मैं भूपेश बघेल जी को श्री भूपेश बघेल जी ही बोलूंगा क्योंकि वे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, सदन के विपक्ष के नेता हैं । मैं तू तड़ाक की भाषा में कभी बात नहीं करूंगा ।

सभापति महोदय, उस सरकार जिस सरकार के लोग कृतज्ञता ज्ञापन में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उस सरकार में जब इंकम टैक्स के अधिकारी रेड करने के लिए आये तो उनकी गाड़ियों जो गोल बाजार के पास 10-15 गाड़ी खड़ी थी, उसको पुलिस वाले जाकर लॉक कर दिए, ताला लगा दिए थे ताला । इसी प्रदेश की वही पुलिस, पर सरकार अलग थी । आप संवैधानिक संस्थाके लोगों को काम नहीं करने देना चाहेंगे। सभापति महोदय, पुलिस वाले गाड़ियों को लॉक कर दिए कि आप कहीं जा ही नहीं सकते । इसी कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश में सी.बी.आई.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर रोक लगा दी थी कि सी.बी.आई. नहीं आ सकता, ई.डी. नहीं आ सकता, एन.आई.ए. नहीं आ सकती । चुनाव आयोग खराब है । सेना खराब है, सेना के ऊपर भरोसा नहीं है । सेना से हिसाब पूछा जाता है, देश के लिए बलिदान देने वाले के साथ प्रमाण पूछा जाता है। सभापति महोदय, ई.ओ.डब्ल्यू. पर प्रश्न उठाते हैं। ए.सी.बी. पर प्रश्न उठाते हैं। संविधान में इन सब संस्थाओं की व्यवस्था है। अगर इन संस्थाओं की व्यवस्था किसी सरकार के बनने या बिगड़ने से खत्म नहीं होती है। अगर हम इसके ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था का पालन कैसे, कौन, कहां पर कैसे करेगा ? इसका जवाब इनको जरूर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है।

समय: 2.11 बजे **(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन में वापस आये)**

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, कल एक गोबर वाला प्रश्न भी उठा। श्री दलेश्वर साहू जी ने कल यहां गोबर वाला प्रश्न उठाया। हमारे वन मंत्री जी कहां हैं ? कल गोबर वाला प्रश्न उठा तो मैं उस प्रश्न के बारे में बता देता हूं। वह प्रश्न मरवाही का है। वह प्रश्न इनकी सरकार के समय का है। मरवाही में उसमें निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई है। अब मंत्री जी उसमें देख लें, जांच करायें और कार्रवाई करें। लेकिन यह इनके कार्यकाल का है। वहां पर एक रेंजर, एस.डी.ओ. बनता है। एस.डी.ओ. बनने के 15 दिन बाद उसको डी.एफ.ओ. का चार्ज दे दिया जाता है। डी.एफ.ओ. का चार्ज वहां के एक धर्मगुरू दाढ़ी वाले ने दिलवा दिया, उसको डी.एफ.ओ. बनवा दिया। वह वहां पर खुला खेल खेलते रहे। मैं कई बार बोला तब भी नहीं मानें। ये हाल है। दलेश्वर जी, आप यहां प्रश्न पूछ रहे हो, आप जोर-जोर से हमारे वन मंत्री जी के ऊपर चढ़े बैठ रहे थे। ठीक है, आप प्रश्न पूछिये। लेकिन वह आपके कार्यकाल का है।

सभापति महोदय, राम वनगमन पथ, पता नहीं राम से, मैं तो आपके प्रति जो यहां बैठे हैं, उन पर पूरी श्रद्धा रखता हूं। परन्तु राम के बारे में आपकी पार्टी लाईन क्या कहती है, यह समझ में नहीं आ रहा है। राम तो इस देश की आत्मा है। राम वनगमन पथ बनवाये हैं तो आप राम टाइप मूर्ति तो बनवा देते। वह मूर्ति ही राम टाइप नहीं है। उसमें आपको तख्ती टांगना पड़ेगा कि ये रामचन्द्र जी हैं या फिर मैं रामचन्द्र हूं मुझे पहचानों, ऐसा लिखवाना पड़ेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप लोग 17 साल में क्या किए हो, यह तो बताओ ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामविचार नेताम :- ये लोग ऐसी मूर्ति लगाये थे पता नहीं कि कहां से खोजकर लाये थे। अब हमारी सरकार है तो हम लोग बहुत सी चीजों में परिवर्तन कर रहे हैं। प्रभु राम की प्रतिमा लगाने वाले हैं। इनका बस चले तो किसी की भी मूर्ति लगाकर बोल देंगे कि यही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं अब बस अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे महंत जी बता चुके हैं। यहां आटो एक्सपो लगा। एक नया प्रयोग हुआ। अच्छी बात है। उसमें हजारों लोग गाड़ी लिया। वह सब क्यों लिया ? क्योंकि उनके पास धान का 3100 रूपया प्रति क्विंटल का पैसा था। (मेजों की थपथपाहट) यहां पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था हुई। हम लोग मुम्बई, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद के बारे में पढ़ते थे। यहां उसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। अगर यह अच्छा हो और अगर उसमें कुछ कमीबेशी हो तो गृह मंत्री जी उसको दूर करियेगा। हो सके तो हमारे बिलासपुर में भी व्यवस्था करा दीजियेगा। माननीय गृहमंत्री जी, आप बिलकुल विचलित मत होईये। ये नशा करने वाले, दारू बेचने वाले, अफीम, चरस, गांजा बेचने वाले, यहां छत्तीसगढ़ में नाईजिरयन कनेक्शन है। मैं इनकी सरकार के समय भी बोलता था। एम.एल.ए. कालोनी के पास ही जहां मुख्यमंत्री जी का घर है, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, वहां पर बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप बत्ती दो। आप जिस टाईप का दे सकते हो, बत्ती दो। आप उसमें कोई कमी मत करिये, क्योंकि ये लोग पूरी नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं और हमें इनको बर्बाद नहीं होने देना है। यह काम सिर्फ आपका और हमारा नहीं है, इनका भी है। आप ऐसे तत्वों को कुचल दीजिये। इनको पूरा साफ करिये।

सभापति महोदय, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। माखन लाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर में एक कविता लिखी थी। थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं यह सरकार और वह सरकार तो बोलना पड़ रहा है। एक पुष्प की इच्छा है कि-

"चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं"

"चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं"

"चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं"

"चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊं"

"मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

"मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक" (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, यह उन्होंने बिलासपुर की जेल में लिखा था।

श्री रामकुमार यादव :- ए दरी के बजट सत्र हा कवि सम्मेलन कस लागत हे?

श्री धर्मजीत सिंह :- कवि सम्मेलन में उल्टा-सीधा बोलते हैं। यह एक पुष्प की अभिलाषा है। उस अभिलाषा को आपने कैसे कुचला है, अभी यह बताऊंगा । यह माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर की जेल में लिखा था और इस पुष्प को हम चाहे देवता के सिर पर चढ़ाएं, चाहे सम्मान के प्रतीक के रूप में शहीदों के शव पर चढ़ाएं। सभापति महोदय, आपकी जब सरकार थी, रायपुर में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, एक किलोमीटर गुलाब की फूल पर किसने चला था? क्यों आपने बिछवाया था? फूल को इस तरह से उसकी अभिलाषा को रौंदन करने का काम आपने किया। सभापति महोदय, उसके राजनीतिक फायदे हो सकते हैं, पर अगर वह नहीं बिछता तो राजनीतिक नुकसान भी नहीं होता, पर इस प्रदेश में सत्ता की राजनीति में फूलों के ऊपर भी एक नेता को चलाया गया था। आधे किलोमीटर लंबे गुलाब के फूल की पंखुड़ियों के ऊपर पैर रखते हुए वे लोग पैदल चले थे। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी गलतियों को जरूर बताएं। आप विपक्ष में हैं। आपके बगैर इस सदन का जो चार्म है, वह खत्म हो जाता है। इस सदन में आप जब नहीं रहते हैं, तो हमको अच्छा भी नहीं लगता है। आप हमारे सबसे बड़े आलोचक हों, यह हम चाहते हैं और आपकी आलोचना से, आपके कहे गए कार्यों से हम जरूर आगे बढ़ने का काम करेंगे। सभापति महोदय, कमियां हर जगह होती हैं, उन्हें ठीक किया जाता है। गिनाया नहीं जाता, बहुत ज्यादा मत गिनाइएगा। कमियां बता दीजिएगा, हम उसको दूर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री साफ हृदय के आदमी हैं, गरीबों का दर्द देखे हैं, जानते हैं और उपमुख्यमंत्री जी, सलाह इधर भी बता रहा हूं ।

'सलाह हारने वाले से लिया करें,

जीतने वाले मुश्किलों के बारे में नहीं बताते हैं।'

जो जीतने वाले हैं, वह मुश्किलों के बारे में नहीं बताते हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए हम आपसे सलाह लेंगे, आपकी आलोचना सुनेंगे, कोई गलती होगी तो हम स्वीकारेंगे और गलती नहीं होगी तो आपको बताएंगे। लेकिन हमारा आपका सबका एक उद्देश्य है, हमारी सरकार के मुखिया का एक ही उद्देश्य है कि इस छत्तीसगढ़ में एक चमकता हुआ प्रदेश बने। इस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ के दूर-दराज गांव में बैठे हुए लोग जो विकास की आस में बैठे हुए हैं, उन तक विकास की दस्तक पहुंचे । सभापति महोदय, सरकार जो गरीबों के आंख से आंसू पोंछना चाहती है, उस आंख के आंसू पोंछ दिए जाएं। जिनकी कोई आवाज नहीं मिलती है, उनको यहां से आवाज दी जाए। जिनको कोई सहारा नहीं मिलता है, उनको सहारा दिया जाए और यह काम हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। इसमें हमें आपका भी साथ चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) इस प्रदेश का विकास करने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए और मुझे आशा है कि आप रचनात्मक आलोचना जरूर करेंगे। श्री विष्णुदेव साय एक अच्छे, नेक, भले मुख्यमंत्री को अपना सहयोग प्रदान करके प्रजातंत्र का जो यहां पर धर्म है, उसका हम पालन करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, 26 साल बाद मैं कृतज्ञता ज्ञापन पेश कर रहा हूं और शायद हो सकता है कि यह हमारी जिंदगी का आखिरी कृतज्ञता ज्ञापन हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी। श्री उमेश पटेल जी। एक मिनट।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- उमेश जी, एक मिनट।

सभापति महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 22 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। संशोधन बहुत ही विस्तृत हैं। मैं पूरे संशोधन को नहीं पढ़ूँगा, केवल संशोधन प्रस्तुतकर्ता के सदस्यों के नाम तथा संशोधनों की संख्या को ही पढ़ूँगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे, उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जाएँगे :-

क्र.	सदस्यों का नाम	संशोधनों की संख्या
1.	श्री भूपेश बघेल, सदस्य	20
2.	श्री कवासी लखमा, सदस्य	08
3.	श्री उमेश पटेल, सदस्य	20
4.	श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य	100

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

5.	श्री भोलाराम साहू, सदस्य	10
6.	श्री दलेश्वर साहू, सदस्य	24
7.	श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य	23
8.	श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य	34
9.	श्री विक्रम मंडावी, सदस्य	37
10.	श्री इंद्रशाह मंडावी, सदस्य	11
11.	श्री संदीप साहू, सदस्य	12
12.	श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य	30
13.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य	10
14.	श्री जनकराम ध्रुव, सदस्य	17
15.	श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य	07

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री धरमजीत सिंह, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री उमेश पटेल।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की अष्टम् सत्र में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में कुल 106 पॉइंट हैं। 106 पॉइंट में से शुरुआती 10 पॉइंट दूसरी चीज़ों के लिए हैं, लेकिन 11वें पॉइंट से लेकर 28वें पॉइंट तक आपने खेती-किसानी और मत्स्य पालन के बारे में बात की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि किसानों के प्रति इस सरकार का जो व्यवहार है, उसके बाद राज्यपाल से यह किसानों के बारे में कैसे बोलवा पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ का किसान पहली बार इतना प्रताड़ित हुआ है, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे धान बेचने की बात हो। हर जिले में, हर विधायक अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में और मैं सारे विधायक की बात कर रहा हूँ, शहरी क्षेत्रों को छोड़कर वे सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में इस बार धान खरीदी में परेशानी में रहे होंगे। रोज़ हमें 40-50 किसानों का फोन आता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

था कि टोकन काट दिया गया है, लेकिन मेरा धान नहीं बिक रहा है, रकबा समर्पण करा दिया गया। इस सरकार ने किसानों को लगातार तरह-तरह की परेशानी दी है। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले तो आपने खाद की व्यवस्था को लेकर दु:ख दिया। पहले किसानों को डी.ए.पी. खाद नहीं मिली। किसान डी.ए.पी. के लिए परेशान हुए। चलिये, किसी तरह से जैसे-तैसे करके डी.ए.पी. की कमी हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद यूरिया में भी वही परेशानी हुई। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम महतारी वंदन योजना में पैसा दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना में हम 12,000 रूपये दे रहे हैं, पता नहीं आप क्या कर दे रहे हैं, जिससे उनका जीवन बदल जा रहा है। एक तरफ आप 12,000 रूपये दे रहे हैं और दूसरी तरफ से 22,000 रूपये निकाल रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी मंत्री थे और अपने 5 साल के कार्यकाल में महतारी वंदन का 500 रूपये भी नहीं दे पाये और आज वह 12 हजार की बात कर रहे हैं ? पहले आईना देख लेना चाहिये कि अपनी सरकार में क्या किये थे?

सभापति महोदय :- आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं अपना आईना रोज देखता हूँ और इस चेहरे पर दाग नहीं है ।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भईया, चेहरे की बात नहीं है । चांद सुहाना लगता है, दिल पुराना लगता है, कहां इधर-उधर की बात लगाये हो। ये बता कि कारवां क्यों लूटा? (मेजों की थपथपाहट) छोड़ इधर-उधर की बात, ये बता कारवां क्यो लूटा?

श्री उमेश पटेल :- कारवां लूटा, इसलिये हम लोग इधर बैठे हैं । ठीक है, हो गया ना । छत्तीसगढ़ के लोगों ने हमें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिये हमें यहां भेजा है और हम विपक्ष की भूमिका निभायेंगे । हम आपको वह सारी चीजें बतायेंगे, जहां आप कमी कर रहे हैं । किसानों को जो पीड़ा हुई है, मुझे उसे सदन के भीतर रखने का पूरा अधिकार है ।

श्री राजेश मूणत :- आप यह बताईये कि कांग्रेस पार्टी में नेता कौन है, नेता प्रतिपक्ष बैठे रहते हैं और पड़ोस वाले घोषणा करके चले जाते हैं ? पहले तय तो कर लो कि नेता कौन है ? हाऊस में बैठे रहते हैं, दूसरे नेताजी घोषणा करके चल देते हैं। पहले आपस में तय कर लो कि नेता कौन है?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप समय देख लेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- अपनी बात रखिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले दुख इन्हीं ने दिया है । मेरे प्रभारी मंत्री जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं । वह सब पर भारी हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, आप लोग प्रदेश भर में घूम-घूम कर किसानों को, आमजनों को जो बरगलाने का काम करते रहे हैं, सिर्फ बरगलाने का काम किया है । इसके बावजूद प्रदेश की जनता इनकी बातों पर नहीं आई, इनके ऊपर कभी भरोसा कर ही नहीं सकते हैं । आप लोग तो भरोसे के लायक है ही नहीं? अपना भरोसा खो दिये हैं और इसलिये प्रदेश के किसान, नवजवान, बच्चे, बुजुर्ग, सभी गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिये भी लड़कर यहां पर आये हैं और उसके लिये काम कर रहे हैं । सभापति महोदय, हमने 3100 रूपये में धान खरीदी किया है, आप बताईये कि देश के किस राज्य में यह हो रहा है ? (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है । (मेजों की थपथपाहट) हम लोगों ने इस सरकार में 3100 रूपये में धान खरीदी भी किया और उनका पुराना बोनस बाकी था, वह भी दिया । भविष्य में उनके लिये जो भी बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, वह भी करेंगे । खाद-बीज का कहीं भी कोई शिकायत नहीं है।

श्रीमती कविता प्राणलहरे :- आप लोगों को किसान ढूंढ़ रहे हैं?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इन लोगों ने पहला दु:ख यह दिया कि डीएपी की व्यवस्था नहीं की है और उसके बाद यूरिया की व्यवस्था नहीं की है । इस साल कितना धान बेचे और कितना पैसा आया, कम से कम वह जरूर बताना । आप रिकार्ड देख लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- किसान पुत्र बोल रहा है ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, एकदम सही है । मैं इसको आंकड़ों सहित बताऊँगा। सरकार ने खाद और बीज की कमी जानबूझकर की है ताकि किसानों का उत्पादन कम हो और उत्पादन कम करने के पीछे कारण क्या था कि 1900 रूपया में इन्होंने धान को नीलाम किया था और 1200 रूपया प्रति क्विंटल उनको नुकसान झेलना पड़ा । इस बार इरादे से कि उत्पादन कम हो, ताकि हमें धान खरीदी कम करनी पड़े, इन्होंने जानबूझकर खाद की कमी की है । सभापति महोदय, मैं इंद्रदेव को प्रार्थना करूँगा और धन्यवाद दूँगा कि उनका आर्शीवाद छत्तीसगढ़ को पड़ा । हर साल से अधिक बारिश इस साल हुई है । किसानों के उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं आई है । अभी हमारे धर्मजीत भईया नहीं है, वह इस बात को बोल रहे थे कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हम महतारी वंदन को 12 हजार रूपये दे रहे हैं, 12 में उनका जीवन बदल गया, उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो गई । माननीय सभापति महोदय, सामान्यतौर एक एकड़ में दो बोरी डीएपी की जरूरत पड़ती है और एक बोरी यूरिया की जरूरत पड़ती है । मार्केट में जो यूरिया 300 रूपया का है, उसे 1200 मे खरीदा है और डीएपी जो 800 रूपए में मिलता है उसको तीन-तीन हजार रुपए में लिये हैं। अगर कोई चार-पांच, आठ-दस बोरा लिया है तो 22-25 हजार का तो वहीं उसका नुकसान हो गया। सभापति महोदय, लोकसभा चुनाव में, महतारी वंदन चालू किया था। अब बात कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं बोल देता हूँ। उस समय एक आदमी से मैंने पूछा कि आपने किसको वोट दिया? उन्होंने कहा मैं तो आप लोगों को किया हूँ, लेकिन मेरी घरवाली बीजेपी वोट कर दी। मैंने बोला क्यों भाई ? उन्होंने कहा कि वो पैसा मिल रहा है, कैसे करें एक बार वोट दे देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, अभी उसको तगड़ा झटका लगा है। मैंने पूछा अब किसको दोगे? आपकी पत्नी किसको वोट देगी? उन्होंने कहा इस बार अगर दूसरे को वोट दी तो टांग काट दूँगा। (हंसी) आप समझ रहे हैं? किसानों की ये स्थिति बन चुकी है । धान खरीदी को लेकर उनके मन में इतनी पीड़ा है। मेरे सार्वजनिक जीवन में जब से मैं आया हूँ इतनी अव्यवस्था आज तक मैंने कभी नहीं देखी। किसी का टोकन नहीं कट रहा है। प्रबंधकों को बाप रे ? उनको तो ऐसा लग रहा था कि भैया यहां से कब छोड़कर जाएं। हर दिन, आज टोकन कटेगा, कलेक्टर बोल रहा है कटेगा, एसडीएम बोल रहा है, बेटा एक भी टोकन कटना नहीं चाहिए । मंत्री जी, आप लोगों ने आखिरी के 15 दिन तो रुला दिया । हमको चक्का जाम करना पड़ा। शक्ति में चक्का जाम हुआ है, मेरे यहाँ चक्का जाम हुआ है, मतलब सभी विधानसभा में चक्काजाम हुआ। मंत्री जी, आपके विधायक लोग भी परेशान थे, आप क्या बात करेंगे ? आपके जनप्रतिनिधि, आप जब बोल रहे थे तो जितने ग्रामीण विधायक हैं वे एक भी ताली नहीं बजाए शहरी वाले ही बजा रहे थे क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। (हंसी) एक भी ग्रामीण विधायक ने ताली नहीं बजाया क्योंकि उनको भी पता है क्या स्थिति बनी है।

श्री आशाराम नेताम :- मैंने ताली बजाई थी।

श्री उमेश पटेल :- आप तो सही में खड़े जो गए। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- लेकिन उन्होंने जो ताली बजायी है, वह-वह वाली नहीं बजायी है। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आप लोगों के आंकड़ों के अनुसार, आपने जो बोला है मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। वर्ष 2024-25 में 25 लाख 49 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, ये आपकी ही सरकार ने की। इस वर्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2025-26 में 25 लाख 24 हजार किसानों ने 141 लाख मीट्रिक टन खरीदी की। मतलब आप लोगों ने लगभग 9 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी कम की। आपके मंत्री क्या बोलते हैं? उत्तर क्या देते है?

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति जी, जो गड़बड़ी होती थी, जो अनियमितता किया जाता था, चोरी किया जाता था, कोचियागिरी के माध्यम से जो खरीदी होती थी, जिसमें मैं नहीं कहना चाहता लेकिन बहुत सारे [XX][3] भी इसमें इन्वॉल्व होते थे। उसे हम लोगों ने रोका और सख्ती के साथ रोका। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह घोर आपत्ति है। इन्होंने आरोप लगाए हैं, अगर ऐसी बात है तो इसका सबूत पटल पर रखें। इन्होंने धान की चोरी का आरोप लगाया। अगर इनके पास कोई सबूत है तो पटल पर रखें। इसमें चर्चा होगी लेकिन आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- धान की चोरी कहां हुई धान तो मुसवा खा गए।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- सभापति महोदय, 7 करोड़ के धान को कौन सा चूहा खाया है। यह भी बता दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, इन्होंने गलत आरोप लगाया है। इनके पास अगर किसी तरह के सबूत हैं तो पटल पर रखें। हम चर्चा करेंगे, हम भागेंगे नहीं। आप इस तरह के गलत आरोप मत लगाइए। आपने कहा इन सब लोगों के...।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप अपनी बात रखिए न।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इन्होंने हमारे विधायकों को सीधा इशारा करके आरोप लगाया है। सभापति महोदय मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ । अगर ये आरोप लगाए हैं तो पटल पर रखें।

श्री राजेश मूणत :- क्या चीज ?

श्री उमेश पटेल :- सबूत है तो रखिए। इस तरह की कोई कार्रवाई किसी ने की है, इस तरह का कृत्य किसी ने किया है तो उसको पटल में रखें । आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं ? सब लोग माननीय सदस्य हैं।

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। श्री उमेश पटेल :- इन्होंने इशारा करते हुए कहा है।

श्री लखेश्वर बघेल :- आप एक मंत्री हैं और जवाबदार पद में हैं। आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा बताइए ? इनको साबित करना चाहिए, पटल पर रखिये।

श्री उमेश पटेल :- अगर आपके पास सबूत है तो पटल पर रखिये। आपने ऐसे ही आरोप लगा दिया।

श्री लखेश्वर बघेल :- आप एक मंत्री होते हुए, एक जवाबदार व्यक्ति होते हुए भी आरोप लगा रहे हैं तो उसको पटल पर रखिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इन्होंने साफ-साफ इशारा किया है।

श्री रामविचार नेताम :- मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इन्होंने ऐसा इशारा करते हुए बोला कि **[xx]**[4]

श्री रामविचार नेताम :- भाई, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं और इस तरह से जो लोग हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है और इसलिए बहुत सारे जो आप बता रहे हैं कि इतना कम हुआ है तो इस वजह से भी कमी हुई है।

सभापति महोदय :- अनियमितता हुई है, उसको रोके हैं तो इसलिए कम हुआ है। मंत्री जी यह कह रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह बात नहीं है। इन्होंने इशारा करके हमारे सदस्यों को कहा है। आप कह दीजिये कि आपने हमारे सदस्यों की बात नहीं की है तो हम आगे बढ़ जायेंगे।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप तो सीनियर सदस्य हैं। मंत्री जी ने विधान सभा में किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है। आप अपनी बात रखिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, क्या इशारा का कोई मतलब नहीं है? अगर मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप यह बताइये कि आपने किसकी तरफ इशारा किया है?

---

[4] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आपका नाम नहीं लिया। लेकिन अगर वह इशारा कर रहे हैं। वह कह दे कि उन्होंने सदस्यों के लिए नहीं बोला है।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात रखिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मंत्री जी यह बोल दे कि यह सदस्यों के लिए नहीं है तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी।

श्री लखेश्वर बघेल :- एक मिनट। हमने कहा है कि 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। आपने तो कहीं कोई शर्त नहीं लिखा है कि आप जितना उत्पादन करेंगे, उतना करेंगे। चाहे हम चोरी करके लाये, कहीं से भी लाये, लेकिन हम 21 क्विंटल दे रहे हैं। उत्पादन जितना हो रहा है, आपने नहीं लिखा है कि 21 क्विंटल नहीं लेना है।

श्री बालेश्वर साहू :- आप तो स्वीकार कर रहे हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य स्वीकार कर रहे हैं कि वह ला रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बात कीजिये।

श्री लखेश्वर बघेल :- बात उसकी नहीं है। आपको 21 क्विंटल लेना है। आप शर्त लगा कर दीजिये। आप तो अनावारी करा लिये, सब कुछ करा लिये, अधिकारियों से चेक करा लिये, सब कुछ करा लिये, लेकिन उसके बाद भी नहीं लिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उमेश भाई, आपने जो कहा है तो फिर आप आपका ही समर्थन कर रहे हैं। (हँसी) यानी चोरी करके लाए। हमने तो नहीं कहा कि कोई चोरी करके लाया है। आप खुद बोल रहे हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि हम चोरी करके लाये हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- इससे आप सारे सदस्यों का तो आप अपमान कर ही रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- आप इशारा कर रहे हो। एक मिनट भैया, आप इशारा कर रहे हो। महोदय जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए न। फिर आप बोल लीजिये।

श्री राजेश मूणत :- यादव जी, हम आपकी बात सुनने के लिए ही तो बैठे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट सुन लीजिये। इशारा की बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 9 मुसवा तो कैसे होगा? अगर मैं 9 मुसवा को ढूंढ रहा हूँ करके बोलूं तो कैसे होगा? मैं 14 मुसवा बोलूं तो कैसे होगा?

श्री बालेश्वर साहू :- भैया, आप कोई भी इशारा को अपनी तरफ क्यों मानते हैं? कोई भी इशारा को अपनी तरफ क्यों समझते हो?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, कोई भी इशारा को नहीं, उनका इशारा समझ में आ रहा था। इतना भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।

सभापति महोदय :- उमेश जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने कहा है, लेकिन मंत्री जी का कहना वह नहीं है कि मैंने किसी का नाम लेकर इशारा किया है। लेकिन उसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने इशारा किया है और आपको उससे आपत्ति है तो मैं उस शब्द को विलोपित करता हूं। आप आगे बढ़िये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, धान खरीदी में इनकी तरफ से तरह-तरह का प्रपंच किया गया। सबसे पहले किसानों के रकबे को समर्पण कराया गया। आज आप हर सोसाइटी में जायेंगे तो देखेंगे कि आपने यह जो खरीदी कम की है, आप स्वयं बोल रहे हैं। आप जाइये और किसानों की पीड़ा को समझिये कि आखिरी के 5-7 दिनों में क्या स्थिति हुई? कलेक्टर कलेक्ट्रेट के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने ए.डी.एम. और किसी अन्य अधिकारी को भेज रहे थे। वह उनको फेस नहीं करना चाहते थे। क्या आपको पता है कि आपके नीचे के अधिकारी आपको क्या बोलते हैं? तीन महीने से हमको यहां पर लगा कर रखे हैं। हम किसान को कैसे बोले कि तुम रकबा समर्पण करो, रकबा कम करो। आपके पटवारी रोते थे, क्योंकि उसको रोज फेस करना है।

श्री लखेश्वर बघेल :- वह बोलते थे कि ऊपर का ऑर्डर है। कौन सा ऊपर? ऊपर वाला या इधर वाला। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल -:सभापति महोदय, पटवारी रोते थे। तीन महीने से आपने पूरे राजस्व विभाग को और सबको लगा रखा था, किसलिए? ताकि धान खरीदी कम होनी चाहिए। सभापति महोदय, धान का उत्पादन तो कम हुआ नहीं है । इनका कहना है कि इन्होंने 9 लाख मीट्रिक टन चोरी रोक ली। मंत्री जी, आपको मैं लिखित में उदाहरण के रूप में दूंगा कि कितना-कितना धान समर्पण कराया गया और कितने-कितने लोग आज तक धान नहीं बेच पाए। आपको पता है? जो कर्जधारी हैं, उनका धान बचा हुआ है । जिन्होंने सोसाइटी से कर्ज लिया, आज वह कर्जदार हैं। आप क्या बात करते हैं कि आपने 9 लाख मीट्रिक टन चोरी रोक ली? जो चोरी करने वाले लोग थे, वे तो अधिकारियों से मिलकर शुरू में ही धान बेच डाले। आपने आखिरी के 15 दिन में असली किसानों को रोका है। असली किसान दु:खी हुआ है। सभापति महोदय, ये समस्या हुई है। ये किसानों की बात करेंगे? वह भी 11 से लेकर 28 प्वाईंट तक? आपका तो इसको लिखने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए।

श्री रामविचार नेताम :- एक तो आपको स्पष्ट कर दूं कि कृषि मंत्री या कृषि विभाग उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है।

श्री उमेश पटेल :- आपको कहने का मतलब पूरे..।

श्री रामविचार नेताम :- इस प्रदेश में हम लोग किसानों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जैसे भी, जैविक खेती करवा रहे हैं, प्राकृतिक खेती करा रहे हैं। उसके माध्यम से उनको अच्छा रेट मिलें और अच्छी आय हो। खाद का अनावश्यक जो अपव्यय हो रहा है, उसमें अत्यधिक खाद का प्रयोग हो रहा है, उससे हमारी धरती पूरी छलनी हो रही है, समाप्त हो रही है।

श्री उमेश पटेल :- इसीलिए आपने खाद नहीं दिया।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, धीरे-धीरे पूरे देश का नजरिया बदल रहा है। पूरे देश भर में ऑर्गेनिक खेती को, प्राकृतिक खेती को और लोगों को उस ओर बढ़ाने की दिशा में हमारा कृषि मंत्रालय ...। रही बात धान खरीदने की, तो भैया खरीदने वाले मामले पर मुझको ही सब मत बोलिए, इधर कश्यप जी को भी बोलिये (हंसी)।

श्री उमेश पटेल :- आप सबसे सीनियर मंत्री हैं। आपको बोलने का मतलब सिर्फ आपको नहीं बल्कि मैं पूरे शासन की बात कर रहा हूं। अब आप पहले तय कर लीजिए कि मैं आप दोनो में से किससे बात करूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- मालिक यह हैं, हम लोग केवल तौलने वाले हैं।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, उत्पादन तो बढ़ गया।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, डंडी मारने का काम इधर होता है।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, उत्पादन तो बढ़ा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री ने उत्पादन के बाद जो खरीदी में डंडी मारी है ना वहां दिक्कत हुई है। हां, सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री दोनों मिलकर मारी हैं। वह हमारे प्रभारी मंत्री हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ उदाहरण रखूंगा। अलग-अलग विधानसभा के हिसाब से जांजगीर चांपा जिले की ही बात करता हूँ। जांजगीर चांपा में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 34,022 हैं। जिन्होंने के.सी.सी. लिया है, वे 10,182 हैं और जो के.सी.सी. लिए हैं और धान बेच पाए हैं, वे 9,748 हैं। के.सी.सी. धारक किसान जिन्होंने धान विक्रय नहीं किया, वे 434 हैं। सभापति महोदय, बकाया ऋण 2 करोड़ से ऊपर का है । अब केवल एक जांजगीर चांपा विधान सभा के जो 434 किसान बचे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये चोरी कर रहे थे? क्या चोरी करने के लिए के.सी.सी. ऋण लिए थे? आपके खाद्य मंत्री और आपने अभी जो बयान दिया है, वह किसानों के लिए घाव में नमक डालने के बराबर है कि हमने चोरी रोकी इसलिए 9 लाख मीट्रिक टन धान कम हो गया। आप रिकॉर्ड देखकर आईये। सभापति महोदय, हर साल धान की खरीदी बढ़ी है। ये पहली बार है कि धान की खरीदी कम हुई है और लगभग 7 प्रतिशत कम हुई है। यह लोग दबाव में बीच में दो दिन धान खरीदी खोले थे।

श्री केदार कश्यप :- कोई दबाव नहीं है। काखर दबाव है?

श्री उमेश पटेल :- जनता का दबाव था इसलिए दो दिन खोले। सभापति महोदय, दो दिन खोले, उसमें भी किसान कम बेच पाये, इनके कोचिया लोग ज्यादा बेचे हैं।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति जी, हम लोगों ने जो दो दिन खोला, किसानों को अवसर दिया। हमारे प्रदेश किसान मोर्चा के, किसान कल्याण समिति के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया और उसके देखते हुए कि पूरे प्रदेश की समस्या के बारे में किसानों के हित में रखा है, इसलिए सरकार ने 02 दिन का अवसर दिया हे। किसान लोग खुश हैं कि उनकी समस्या का निपटारा हुआ है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति जी, 02 दिन खोला गया लेकिन धान खरीदी नहीं की गई। कलेक्टर ने आदेश कर दिया कि खरीदी नहीं करना है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, धान खरीदी के दौरान एन.आई.सी. से 200 क्विंटल लिमिट होती है, उसमें 100 किसानों को धान बेचना है, कम्पयूटर में लिमिट टोकन काटने के समय 200 क्विंटल का रखा था। ये जो आदेश है फिर गिदौरी में अलग से रकबा काटा, फिर उसके बाद रकबा समर्पण, यानि इस सरकार ने किसानों को चौतरफा परेशान करने का काम किया। अभी भी ऐसे कई किसान हैं जिनकी लिंकिंग भी वसूली नहीं की गई है।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाईये। उमेश जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्री बालेश्वर साहू :- आज भी वह किसान न अपना धान बेच पाया है न कर्ज चुका पाया है। किसान आज भी विश्वास में है कि मान लो विधान सभा के दौरान खरीदी स्टार्ट कर देंगे तो मैं अपना धान बेचूंगा। हमारे क्षेत्र में कई किसान धान रखे हुए हैं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, इसमें से कितने किसान हैं जिनने धान नहीं बेच पाये हैं, उनके घर में बेटे की, बेटी की शादियां लगी थीं, ये मेरे विधान सभा की बात है, उनको शादी कैन्सिल करनी पड़ी है। अभी हमारे माननीय सदस्य के पास पूरी लिस्ट है, वह बतायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी एक सार बात बता देता हूं।

श्री रामविचार नेताम :- किसान न शादी कैन्सिल करय पड़िस, लेकिन माननीय विधायक एकर चिंता करो। तोर कैन्सिल हाईस का?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उनको लड़की नई मिलय, आप लड़की दिलवा दो।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- हम लोग इनकी शादी करायेंगे, लेकिन फिलहाल किसानों का धान नहीं बिक पाया, इस वजह से अपने बेटों, बेटी की शादी कैंसिल करनी पड़ी है। यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के सब लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के नेता बोल रहे हैं। कम से कम इन सबका समय इनको दे दें। मेरा आग्रह है कि आप उमेश जी बोलें।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, इसी विषय में एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- उमेश जी बोल रहे हैं न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, इसी में मात्र एक छोटा सा विषय है। एक लाईन का है, सुन तो लीजिए। माननीय मंत्री महोदय जी हम लोग जो बोल रहे हैं, उस पर विश्वास मत रखिये। आप एक बार हर समितियों से किस-किस किसान का पंजीयन है, कर्जा है और उनका धान नहीं बिका, आत्मसपर्मण कितना किया गया, गिदौरी में कितना काटा गया, एक बार खरीदीवार सूची तो मंगवा लीजिए। आपको भी पता चल जायेगा कि क्षेत्र के किसानों, यह हमारे ही क्षेत्र का विषय नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का है। कम से कम आपके संज्ञान में तो रहे। आने वाले विगत वर्षों में धान की खरीदी होगी, वह आपके संज्ञान में रहेगा कि किस तरह अधिकारियों के दबाव से धान की खरीदी की जा रही है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इसका सारांश मैं आपको बता देता हूं। जब धान किसान बेचने गया, आदेश आया कि लिमिट को पहले कम करो। लिमिट को कम कर दिया। फिर आनलाईन में जो 5 एकड़ से कम किसान हैं, वही पहले शुरू में बेचा। व्यवस्था बनाने के लिए वह ठीक है, उस पर मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप व्यवस्था बनाईये। लेकिन अंतिम समय में पहले उसका टोकन नहीं कटा, वह प्रबंधक के पास गया, वह बोला कि मेरे पास अधिकार नहीं है, आप पटवारी से मिलो। पटवारी के पास गया तो वह बोला कि मेरे पास अधिकार नहीं है, आप एस.डी.एम. से मिलो। एस.डी.एम. बोला मेरे पास अधिकार नहीं है, आप प्रबंधक से वापस मिलो। हमने प्रबंधक को सारी ताकत दे दिया है। वह 15 दिन घूमता रहा। कभी कलेक्टर का एक नया आदेश, कभी एस.डी.एम. का नया आदेश और रकबा समर्पण जिस फोर्सफुली किया गया है। अगर 10 एकड़ का किसान है तो सिर्फ उसका 6 एकड़ का धान खरीदा गया है और 4 एकड़ का समर्पण कराया गया है। ये स्थिति बनी है। आप नैतिक रूप से किसानों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जितना दु:ख और दर्द इस बार आप लोगों ने दिया है, आपके पास नैतिक साहस नहीं बचना चाहिए कि आप किसानों के बारे में कुछ बोल सकें। और मंत्री जी आप सबके लिये मेरा एक सुझाव है कि कम से कम यह मत बोलिए कि हमने चोरी को रोककर 9 लाख मीट्रिक टन कम किया है । आपने किसानों का काटकर 9 लाख मीट्रिक टन किया है, यह उनके लिये घाव में नमक देने जैसा हो रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्य विषयों पर भी आउंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, बिजली एक बहुत भारी समस्या होती जा रही है, बिजली के लिये मैंने अभी एक प्रश्न लगाया था । पिछले 4-6 महीने से लगातार बिजली विभाग में एक अभियान चल रहा है कि जिसका भी बिजली का बकाया 10,000 से ज्यादा है उसका काटो । जिसका 5000 से ऊपर है उसका काटो । गरीब लोगों के बिजली का बिल उनके लिये नासूर टाईप का बनते जा रहा है क्योंकि न तो वे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पटा पा रहे हैं और न उसमें किसी तरह की छूट हो रही है तो मैंने पता करने की कोशिश कि क्या यह केवल गरीब वर्ग के लोग ही नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आश्चर्यजनक रूप से मुझे पता चला कि इनके सरकारी विभाग हैं । इनके पंचायत एवं ग्रामीण विकास का यह केवल एक जिले की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ 94 लाख की बकाया राशि है । केवल नगरीय निकाय, नगरीय निकाय जिसमें नल-जल आता है उसका 66 करोड़ रूपए का बकाया है । नगर पालिका जो सड़क और बस्ती है उसमें 27 करोड़ का है ।

महिला एवं बाल विकास विभाग 2 करोड़ का, स्कूल शिक्षा 5 करोड़, उच्च शिक्षा 5 लाख, स्वास्थ्य विभाग 51 लाख, पुलिस विभाग 25 लाख, आदिम जाति कल्याण 54 लाख, राजस्व विभाग 29 लाख, वन विभाग 42 लाख ऐसे करते हुए हर विभाग का जो टोटल बकाया राशि है वह 142 करोड़ का है, एक जिले का । एक जिले की बकाया राशि यह है और कभी किसी की हिम्मत हुई कि इनकी बिजली काट दी जाए? चलिए ठीक है, मैंने सोचा कि यह तो सरकारी विभाग ही है कैसे काटेंगे? मैंने बोला कि कहीं कोई उद्योग का तो ऐसा नहीं है । माननीय सभापति महोदय, केवल रायगढ़ जिले में जे.एस.डब्ल्यू. करके एक उद्योग है, 32 करोड़ की बकाया राशि है । अंजनी स्टील है, इसकी 10 करोड़ से ऊपर की बकाया राशि है । नौ दुर्गा इसकी 10 करोड़ रूपये से ऊपर की राशि है । क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत बची है? जिस तरह से एक गरीब आदमी का 5 हजार का बकाया राशि के लिए विद्युत को काट दिया जा रहा है, यह जे.एस.डब्ल्यू., अंजनी और इसका काटा गया है ? नहीं, इनका नहीं काटा गया । (मेजों की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यही गरीब की सरकार है, यही विकसित भारत है ।

श्री रामकुमार यादव :- चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, काजू-बादाम खाते हो ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, बिजली केवल गरीबों के लिये काटा जा रहा है, रोज परेशान हैं । सब विधायक लोगों के घर में आते हैं, उनकी स्थिति देखने से ऐसा लगता है कि किसी की 27,000 रूपये का बिल, यह जो स्मार्ट मीटर लगा है पता नहीं वह क्या मीटर है । 27,000, 28,000, 54,000, 1 लाख । एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आयी थी । उसका बिजली बिल देखकर मैं खुद पागल हो गया था । उसका 5 लाख का बिजली बिल बकाया था । मैंने उसको पूछा कि माँ तुम्हारे घर में कौन-कौन रहते हैं, कितने लोग हैं तो वह बोली कि मैं अकेली रहती हूं, मेरे घर में कोई नहीं है । न फ्रिज, न टीवी, न ए.सी., न कुछ नहीं । खाली पंखा है, ऐसे लोगों की बिजली को काटा जा रहा है । आप कितने इंसेंसेटिव होते जा रहे हैं, आप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसानों को लेकर इंसेसेटिव हैं । आप गरीबों को लेकर इंसेंसेटिव हैं, बिजली को लेकर मैंने आपको बताया । आपने इस बिजली में ही बड़ा पाईंट रखा है, आपने बिजली को लेकर एक बड़ा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना । मुझे तो इस नाम से ही हंसी आती है कि मुफ्त बिजली योजना मतलब जिसने भी बोला है, जिसने भी बनाया है । क्या इसको आईडिया भी है कि बिजली बिल कैसा आता है, क्या चार्जेस रहते हैं? उसमें फिक्स चार्ज क्या होता है, मीटर चार्ज कितना होता है ? एडजस्टमेंट कितना करते हैं ? कोल का जो ऑक्शन होता है उसका जो अगर एक एक्स्ट्राऑक्शन हो गया तो उसका कितना जोड़ते हैं ? उसके बाद यूनिट का बिजली बिल आता है । सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बनाओ भैया । सौलर लगाओ, आपके घर बिजली बिल नहीं आयेगा । भैया, बिजली बिल कैसे नहीं आयेगा ? आपने इसे लगाया है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैंने इसे लगवाया है, लेकिन मेरे यहां भी बिजली बिल आता है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मुफ्त बिजली बिल योजना, यह नाम देना ही गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको कोई आइडिया नहीं होगा। तीन किलोवॉट में आप अनुदान दे रहे हैं तो यह बहुत बढ़िया है । आपको केन्द्र सरकार से अनुदान मिल रहा है तो यह बहुत बढ़िया है। मैं अनुदान पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अप फ्रंट उसको पैसा लगेगा या नहीं? उसका आरो आई कितने साल में निकलेगा। यह अवधि 8 साल, नौ साल, 12 साल, 15 साल कितनी है? और आप उसके बाद भी सारे चार्जेस लेंगे। माननीय सभापति महोदय, जब शासन हमसे बिजली ले रहा है अगर आपके यहां सोलर एनर्जी है तो उसे ढाई रूपये में दे रहा है जब वही शासन हमको बिजली दे रहा है तो 8 रूपये ले रहा है। आप यह बताईये कि हमें कैसे बिजली मुफ्त होगा।

श्री रामकुमार यादव :- यही डबल इंजन के कारनामा हे।

श्री उमेश पटेल :- अगर मैंने ज्यादा यूनिट बना ली तो उसमें ढाई रूपये के हिसाब से पेमेण्ट करिये। और जब आप देंगे तो 8 रूपये के हिसाब से देंगे। तो यह कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना यह कैसे लागू होगा और यह मुफ्त तो तब होगा जब आपके सारे...।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय उमेश जी, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ। सोलर पैनल लगाने से वह आपके मीटर के साथ में जुड़ जाता है तो आपका जितने वॉट का लगा है। मान लीजिए आपके यहां 1 हजार रूपये का बिजली बिल आ रहा है, वह बिजली बिल 300-400 रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो जाएगा। वह खत्म नहीं हो रहा है। अगर हां, आपके यहां ज्यादा वॉट का लगा है तो आपके उसमें वह रिजर्व हो रहा है। वह आपकी आमदनी का जरिया बन रहा है। इसमें ऐसा है।

सभापति महोदय :- उमेश जी, सुनील जी भी बोल रहे थे कि यह कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। बाद में अनुदान मांगों पर भी काफी डिटेलवाईस चर्चा हो जाएगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बाहर नहीं गया हूँ।

सभापति महोदय :- यह प्वाईंट है तो समय का भी ध्यान रखें। आप काफी अच्छा बोल रहे हैं। आपने आधे घण्टे से ज्यादा बोल लिया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क बारे में कहा गया है। ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं यही कहूंगा कि माननीय सोनी जी जो आप बता रहे थे वह तब की बात है जब चार्जेस पूरे जीरो हो जाएं। अगर मान लीजिए आपके घर में 3 किलोवॉट की खपत है उसमें 3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगा दिया और अगर सही से रोशनी है, क्लाउड नहीं है तो आपका जीरो होना चाहिए। लेकिन जीरो की स्थिति बनती ही नहीं है उसमें जो अलग चार्जेस हैं, उसके फिक्स चार्जेस होते हैं आपके अलग-अलग चार्जेस होते हैं वही तो अगर आपने 3 फेस का कनेक्शन लिया है तो आपके चार्जेस एक हजार से ऊपर ऐसे ही रहेंगे। वह कभी जीरो नहीं हो सकता है, मुफ्त नहीं हो सकता है। आपको बिजली विभाग को पैसा देना ही पड़ेगा और अगर इनका सेटलमेंट टाईम मार्च का है तो आप मार्च के समय सेटलमेंट करेंगे तो 2 रूपये 50 पैसे के साथ करेंगे और जब खुद बेचेंगे तो 8 रूपये लेंगे। तो जो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली जो योजना है, वह सिर्फ सरकार को सस्ती बिजली हम लोग बनाकर दें, इसलिए इस योजना को बनाया गया है ताकि इनको ढाई रूपये में बिजली मिल जाये। अगर आप यह सोचिये कि सबके घर में सोलर एनर्जी मिल गयी तो सरकार को फिर काफी सस्ते में बिजली मिल जायेगी, जो आज उसमें 3 रूपये 10 पैसे के आसपास लग रहा है। वह ढाई रूपये में मिल जायेगा। यह प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना ही बेकार है।

माननीय सभापति महोदय, आपने प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि के बारे में बात की है। प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना में यह सोचता हूँ कि इसमें कब पैसा आता है और कब पैसा नहीं आता है, यह पता ही नहीं चलता है। उसमें 6-6 महीने, 8-8 महीने से पैसा नहीं आता है। यहां लोगों को यह पता नहीं है कि इसके लिए हम किसके पास जायें ? उनका 8 महीने से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोगों का पैसा नहीं आ रहा है तो उसमें कृषि विभाग बोलता है कि भईया, हमने बनाकर भेज दिया है। मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूँ।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको केवल यह बता रहा हूँ कि उसका समय फिक्स है। साल में इस महीने में आपके खाते में इतना पैसा आएगा।

श्री राजेश मूणत :- यह डायरेक्ट ट्रांसफर है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, यह डायरेक्ट ट्रांसफर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केन्द्र सरकार की कोई बात नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप धरातल में जांच करवाईये।

समय : 3:00 बजे

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, आप धरातल में जांच कराईए कि कितने किसानों को लाभ मिल रहा है । उसमें बहुत सारे बिन्दु हैं, जिससे किसान वंचित हैं ।

श्री सुनील कुमार सोनी :- वह अलग विषय है, आप दूसरे विषय की बात कर रहे हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जब माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि केन्द्र सरकार की राशि साल में तीन बार निश्चित समय पर डायरेक्ट ट्रांसफर होती है । या तो आप खुद धरातल पर नहीं हैं और हमें धरातल बता रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- चलिए, मैं आपको किसान का नाम लिखित में देता हूं, जिसके खाते में आठ महीने से पैसा नहीं आया है । जब बात कर रहे हैं तो अथेंटिक होकर बात कर रहे हैं, मैं यहां पर हवा में बात नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में युवाओं के लिए बात की गई है । इसी सत्र में इसी विधान सभा में तत्कालीक शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 33 हजार शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं, अब वह संख्या कम होकर 5 हजार हो गई । अब वह भर्ती कब होगी, उसका ठिकाना नहीं है । डी.ए. के लिए कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो उनको आप लोग रात में उठाकर ले गए, उनको जेल के अंदर डाल दिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह भी 9 बजे से 12 बजे के बीच ले गए हैं और 2 बजे बच्चियों को जेल में डाला गया और उनको 4 दिन तक जेल के अंदर रखा गया।

सभापति महोदय :- संगीता जी, उमेश जी उसी बात को बता रहे हैं । वे समय भी बता रहे हैं, विषय भी बता रहे हैं । आप उमेश जी को बोलने दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति जी, वे अपना बात रख रही हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उमेश भैया, एक मिनट ।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिए न । सबकी बातों को उमेश जी बोल रहे हैं। उमेश जी को बोलने दीजिए, फिर उन्हीं का समय कम होगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, एक ही मिनट लूंगा । छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा आन्दोलन हो रहा है । वे बोल रहे हैं कि या तो हमें नियुक्ति-पत्र दे दीजिए या मौत दे दीजिए । आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं, आप भी राजनीति में हैं । आज तक हड़ताल में कभी भी ऐसी मांग नहीं उठी, जो मांग संबंधितों के द्वारा किया जा रहा है । न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा है । केवल और केवल 2300 लोगों की नियुक्ति का मामला है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है ।

सभापति महोदय :- द्वाराकाधीश जी, आपका भी नाम है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे सदस्यों ने इस बात को रखा, मैं कहने वाला था । रात को 2 बजे तक बच्चियों को थाने में बिठाकर रखा गया। ये लोग असंवेदनशील तो किसानों के मामलों में हैं ही, ये लोग असंवेदनशील तो गरीबों के मामलों में हैं ही, ये लोग युवाओं के मामले में भी असंवेदनशील हैं। बेरोजगार युवा बड़ी उम्मीदों से इनकी ओर देख रहे हैं । जब ये लोग विपक्ष में थे इनके कुछ मंत्री हैं, जो उस समय ऐसी बात करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम दूध की नदियां बहा देंगे, सबको दूध से नहलाएंगे । कोचिंग सेन्टर में लंबी लाईन लगती थी और वही लोग अब बोलते हैं कि तुम लोग सब नालायक हो । तुम लोग कोई काम के लायक ही नहीं हो । ऐसा मंत्री लोग बोलते हैं, ऐसा जवाब मिलता है । ये असंवेदनशील युवाओं के मामले में भी है ।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, आप भी तो मंत्री रहे हैं । बेरोजगारी भत्ता ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- हमने दिया ।

श्री राजेश मूणत :- आपने क्या किया है, सर्वे कर लीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- हमने बेरोजगारी भत्ता दिया ।

श्री राजेश मूणत :- आपने कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे और विधान सभा में आपने उत्तर दिया था-20 हजार । आपने 5 लाख की होल्डिंग लगाई, बढ़िया फोटो लगवाए कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिए । जो धरातल में है, उसी बात करिए न ।

श्री उमेश पटेल :- मैं राजेश मूणत जी से पूरी चर्चा करने को तैयार हूं ।

श्री राजेश मूणत :- हम दोनों चर्चा करेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- मैं इनसे कहूंगा कि कृपया यह षष्टम विधान सभा है। हम 6वें विधान सभा के कार्यकाल की बात करें । हम लोग इधर आ चुके हैं, अभी रियालिटी में हम लोग विपक्ष में हैं और यह रियालिटी है कि आप लोग सत्ता पक्ष में हैं । आप लोगों को आईना दिखाना हमारा काम है । जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है । हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं ।

श्री राजेश मूणत :- आप अच्छा बोल रहे हैं । मेरा एक निवेदन है । विजन 2047 तक वहीं बैठना है, आप तैयारी करो । आप विपक्ष की राजनीति नहीं सीख सकते तो हमसे आकर ट्रेनिंग लीजिए । हम बता देंगे कि विपक्ष कैसा होता है ।

सभापति महोदय :- मूणत जी, उमेश जी को बोलने दीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, आप 2047 की बात कर रहे हैं । यहां आप प्राईमरी और नर्सरी स्कूलों को बंद कर रहे हैं । शिक्षकों को एस.आई.आर. में लगा रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई कहां करेंगे ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बैठिए । उमेश जी, आप बोलिए ।

श्री कंवर सिंह निषाद :- राजेश भईया 2047 तक खत्म।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप बोलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह सरकार युवाओं के लिए असंवेदनशील है। आज राघवेन्द्र जी ने एन.एच.एम. की वृहद रूप से बात की है। हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। इसके जो आकड़ें हैं, वे चौकाने वाले हैं। सिर्फ 6 महीने में सरकारी अस्पताल में सिर्फ 15 मोतियाबिंद का आपरेशन हुए हैं। कुल 3 हजार के आसपास हुए हैं। लेकिन जांजगीर-चाम्पा के सरकारी अस्पताल में सिर्फ 15 आपरेशन हुए हैं। सिकलसेल बहुत बड़ी बीमारी बनते जा रही है। उसकी स्क्रीनिंग तो काफी बड़ी संख्या में हो गई, लेकिन उसके आगे के प्रोसेस में हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन सबके पीछे कारण एक ही है, जो मैं समझा हूं, स्टाफ की कमी है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी समस्या स्टाफ की कमी है। आप उसको जल्द से जल्द भरने का उपाय करिये नहीं तो टारगेट पूरा नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, ''एक पेड़ मां के नाम'' इस पाइन्ट को भी अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय ने छुआ है। ''एक पेड़ मां के नाम'' के नाम पर 7 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का उल्लेख इस अभिभाषण में हुआ है। सभापति महोदय, आप अडानी को देने के लिए पेड़ कितने काट रहे हैं ? बिना अनुमति के पेड़ काट रहे हैं। तमनार में जिस तरह से लॉ एण्ड आर्डर का विषय बना, मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की घटना कहीं हो, ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों को पिटाई हुई है, वह अच्छा नहीं है। किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पुलिस के बूट की धमक होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पुलिस के बूट की धमक होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोगों में कम्पनी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला, जिस तरह से तमनार में पेड़ कटाई हुई तो लोग जाकर पेड़ से चिपक गये थे ताकि वह पेड़ न कटे। लोगों की दिनचर्या उस जंगल से होती है। इस तरह से बिना अनुमति के, जहां हमारी पांचवी अनुसूची है, वहां बिना अनुमति के लगातार पेड़ की कटाई हो रही है और हम इधर ''एक पेड़ मां के नाम'' लिख रहे हैं और इधर जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। आप तमनार चलिये, आप मेरे साथ आ जाईये मैं आपको दिखा देता हूं। आप बिलकुल आ जाईये। लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र है, आपको जब भी दौरा करना हो, आप कभी भी फोन लगाईयेगा मैं पहुंच जाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर यह सरकार हमारे आदिवासी के जल, जंगल, जमीन पर हमला कर रही है। ये आदिवासियों के प्रित भी असंवेदनशील है। मैं आपनी बात, यह आखिरी लाईन कहकर समाप्त करता हूं। यह सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है। किसानों की धान खरीदी से लेकर, खाद को लेकर असंवेदनशीलता दर्शाई है और आखिरी में इनके मंत्री लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने चोरी को रोका है। मतलब आप किसानों को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चोर बता रहे हैं। ये लोग गरीबों के प्रति असंवेदनशील हैं। यहां बड़े-बड़े उद्योगों का बिजली बिल कम किया जा रहा है और हमारे जो छोटे-छोटे हाऊस होल्डस हैं, उनके घरों की बिजली को काटा जा रहा है। ये लोग युवाओं के प्रति असंवेदनशील हैं, जिस तरह से युवा नौकरी की मांग को लेकर बैठे थे, उनको रात को उठाकर ले जाया जाता है। ये लोग आदिवासियों के असंवेदनशील हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर हमला कर रहे हैं। मैं इतना ही कहते हुए इस अभिभाषण का विरोध करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं यहां पर खड़ी हुई हूं और हम सबके लिए बहुत सुखद अनुभव रहा है कि नयी विधान सभा के इस पवित्र सदन में हम सबको रजत जयंती के वर्ष पर नयी विधान सभा में अपनी बातों को रखने का, पटल पर अपने विषयों को रखने का मौका मिला है और यह इस विधान सभा का पहला आदरणीय राज्यपाल जी का अभिभाषण था और कल हमें सौभाग्य मिला कि बजट सत्र की शुरुआत जो इस नए विधानसभा में जो हुई है, महोदय जी, अगर हम बात करें कि राज्यपाल जी के जो अभिभाषण में जिन विषयों की चर्चा हुई है, उनमें कहीं न कहीं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की एक साल की जो पिछली कार्य अवधि रही है और आने वाली सरकार की जो योजनाएं हैं, कहीं न कहीं उसकी छवि हम उसमें देख पाते हैं। लगातार हमारी सरकार के माध्यम से 'विज़न 2047' की बात की जाती है और लगातार जब 'विज़न 2047' की बात आ रही है तो विपक्ष में उसे मजाक बनाकर 2047 में हम भी देखेंगे, यह विषय आते हैं। महोदय जी, 2047 का जो मिशन है या जो विज़न है या 2030 का जो हम विज़न लेकर चल रहे हैं, वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का या फिर सिर्फ हमारी सरकार का विज़न नहीं है, अपितु पूरे छत्तीसगढ़ का और भारत की आत्मनिर्भरता 2047 में क्या होगी, उसको लेकर जो विज़न है तो मुझे लगता है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी बातें रखने का अधिकार है। लेकिन हम सब जिस देश के वासी हैं, जिस छत्तीसगढ़ महतारी के हम सब बच्चे हैं, उनको लेकर कोई दूरदर्शिता अगर हो तो मुझे लगता है कि कम से कम एक बार तो उसकी तारीफ तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि विपक्ष लगातार विषयों में...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सच होने पर तारीफ होगा न? उसमें सच तो है ही नहीं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती भावना बोहरा :- देखिए, सच को स्वीकार करेंगे तो तारीफ करने की हिम्मत भी अपने आप आ जाएगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सच का कोई भी पक्ष नहीं आया है।

सभापति महोदय :- द्वारिकधीश जी बैठिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- सच को स्वीकार करना सीखिए और सच की तारीफ करना तभी आएगा जब हिम्मत अंदर से होती है। क्योंकि अगर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर सरकार का कार्य अच्छा होता है, तो निश्चित ही चाहे विपक्ष तारीफ करे न करे, जनता उसकी तारीफ जरूर करती है। अभी महोदय जी, विषय चल रहा था कि किसानों की धान खरीदी को लेकर बहुत सारे विषय आए। आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, हमारे जो माननीय सदस्य हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और मुझे खुशी है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो पहला बिंदु है, वह किसानों को लेकर है, किसान को समर्पित है और शायद उसी कारण से आज अगर आप देखेंगे कि किसान के लिए यह जो घोषणा हुई कि जो अंतर राशि है, उनको होली के पहले मिल जाएगी, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 'कृषक उन्नति योजना' के तहत लगभग 25 लाख किसानों को जो होली के पहले मिलने वाली राशि है, बहुत खुश थे। (मेजों की थपथपाहट) हम भी किसान परिवार से आते हैं, जो गांव में आस-पास जहां हम जाते हैं, चूंकि लगातार मैं गांव की बात इसलिए कर रही हूं कि गांव और शहरीकरण का भेद यहां पर किया जा रहा था। जब भी हम कोई मतदाता हों महोदय जी, चाहे वह शहर के हों, चाहे वह ग्रामीण के हों, निश्चित ही उनके विकास की अपेक्षाएं अलग होती हैं, लेकिन सरकार से सबकी उम्मीद रहती है कि सरकार अच्छा काम करे, चाहे ग्रामीण एरिया हो, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो। तो चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि आज किसान उन चीजों को लेकर के खुश हैं कि उनके समर्थन मूल्य की जो राशि है, वह तो उनको मिल ही रही है, लेकिन जो धान की अंतर राशि है, वह विष्णु देव साय जी की सरकार होली के पहले देने वाली है। ना कि पिछली सरकार की तरह, हमारे ही धान का पैसा, धान की अंतर राशि हमको तीन से चार किश्तों में दी जाती थी। मुझे उम्मीद थी कि इस बारे में जरूर चर्चा होगी, क्योंकि यहां पर सब अपने को किसान पुत्र बता रहे थे...।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोग तो पंचायतों में बुलाकर देंगे बोले थे, तो?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती भावना बोहरा :- देखिए दीदी, अब पंचायतों में बुलाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि डायरेक्ट खाते में आपकी बेनिफिट आपको मिलने वाली है। अब यह नहीं है कि वहां से केंद्र से आता है एक रुपया और जाता है 25 पैसा।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आंटी को तो उनकी सरकार में मंत्री बनाकर उन्हीं के लोग ठग दिए थे । 500 रुपये तक नहीं दिया महिलाओं को बताओ, आप बात कर रहे हैं...।

श्री रामकुमार यादव :- ओ खाता ला तुम्हर 15 लाख रुपये देबो कह के खुलवाए रहव। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- यह अच्छी बात नहीं है ना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप 500 की याद मत दिलाओ। आपने 500 रूपये में सिलेंडर देने की बात कही थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मोदी की गारंटी में था।

श्री सुशांत शुक्ला :- छत्तीसगढ़ को ठगा। गढ़बो छत्तीसगढ़ का नारा देकर ठगबो छत्तीसगढ़ में आके आज विपक्ष में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। चलिए बैठिए।

सभापति महोदय :- भावना जी, आप बोलिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- 500 रुपये के सिलेंडर की भी मैं आगे बात कर देती हूं..।

सभापति महोदय :- भावना जी, इधर जवाब मत दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इस बजट में हम इंतजार कर रहे थे कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। इस बजट में हमने वेट किया, आप लोगों का इंतजार किया ।

श्री सुशांत शुक्ला :- छत्तीसगढ़ की महतारी 5 साल तक 500 रुपये का भी इंतजार की और माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह महतारियों को समर्पित वर्ष है ।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, उनको बोलिए दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, महतारियों को समर्पित कर रहे हैं, गौरव दिला रहे हैं। आप जाइए ना तूता में जब ढाई महीने से बैठी हैं महिलाएं, उनका कोई सुध नहीं ले रहे हैं। रसोइया संघ की महिलाएं ढाई महीने से बैठी है । उनको आप देख नहीं रहे हो? उनको मंत्री जी नहीं देख पा रहे हैं? आप उनको दीजिए। उनको बजट में रखना था। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशांत शुक्ला :- स्व-सहायता समूह में महिलाओं की शक्ति का अधिकार छीनने वाले लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं? यह कतई उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, महिलाओं का सम्मान करना है तो रसोइया संघ की महिलाओं को पैसा दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठिए। संगीता जी आप तो वरिष्ठ हैं। आप वरिष्ठ हैं, उसके बाद आप सीधे बात करते हैं, यह ठीक बात नहीं है। निषाद जी आप बैठिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप महिलाओं को बता दीजिए, अभी ढाई साल में कितना मिल गया है?

श्री सुशांत शुक्ला :- जितना आप दे नहीं पाए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, मिला है तो आप बता दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- जितना आप दे नहीं पाए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अगर मिल गया है तो बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जितना आप दे नहीं पाये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अगर मिला होगा तो बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जितना मिल गया है, वह आप ले नहीं पाए हैं।

सभापति महोदय :- निषाद जी, यह परंपरा नहीं है कि आप सीधे सवाल करेंगे। सुशांत जी, आप बैठिए। भावना जी, आप बोलिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी। सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य ने जिस विषय पर भी चर्चा की है, मैं ज़रूर उस विषय पर आऊंगी क्योंकि हम इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मुझे हमारी महिला सदस्यों से, बहनों से यह उम्मीद थी कि कम से कम वे एक बार तो इस विषय पर मेज़ थपथपाते कि यह वर्ष महतारियों को, माताओं को समर्पित है। मुझे लगता है कि एक बार हम सबको अभिनंदन ज़रूर करना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- देखिए, हमको गर्व है। अभी 8 मार्च को महिला दिवस आ रहा है। यह सरकार हम महिलाओं का दर्द देखती हैं, लेकिन हमको बहुत दर्द होता है कि यह सरकार महिलाओं की बात नहीं सुन रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती भावना बोहरा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि यह दर्द दो साल पहले कहाँ था? जब यहीं रायपुर के एक मैदान में बैठकर हमारी बहनें अपना बाल कटवाकर मुंडन करवा रही थीं, तब इनका यह दर्द कहाँ था? (शेम-शेम की आवाज) वे लोग उस समय की यह बात ज़रा याद कर लें। क्योंकि कोई भी सरकार हो, यदि महिलाओं के प्रति सहानुभूति है तो उनको अपनी सहानुभूति दिखानी चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, आज महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि हर समय महिलाएं आपके प्रति देख रही हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- कितनी खराब हुई है, ये भी बता दीजिए?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमारी मितानिन बहनें और आंगनबाड़ी की महिलाएं वेट कर रही थीं। भूपेश बघेल जी की सरकार में मितानिन बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा था। इस बजट में उनको होली में खाली कर दिया गया है।

सभापति महोदय :- चलिये, ठीक है।

श्रीमती भावना बोहरा :- संगीता जी, मैं आगे आपकी बात में ज़रूर आऊंगी। मैंने पहले जो विषय सोचा है, उसको मैं पहले एक बार रखती हूँ।

सभापति महोदय :- भावना जी, आप मन इधर-उधर मत भटकाइये। आप अपनी बात को रखिये और अब आप राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मैंने पहले ही बोला कि सच्चाई बोलने के लिए मन को थोड़ा-सा भावुक भी होना चाहिए, तब सच्चाई स्वीकार हो सकती है, जो कि हम विपक्ष से कम ही उम्मीद रखते हैं। सभापति महोदय, जहाँ तक हम इस साल को गौरवपूर्ण महतारी वर्ष बनाने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि पिछली सरकार में 08 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महतारी वंदन योजना की शुरुआत जो हुई थी। आज निरंतर उसका 24वां किश्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है। अभी कुछ समय पहले हमारे आदरणीय सदस्य यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। मैंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई क्योंकि मैंने उस समय उनको बीच में टोकना सही नहीं समझा, लेकिन अभी उस बात को मैं ज़रूर बोलूँगी कि उस बात पर मुझे आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि उसको उन्होंने वोट से जोड़ा। उन्होंने महतारी वंदन योजना के बारे में यह कहा। अभी सदस्य उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने अपने साथ वाले व्यक्ति से पूछा कि आपने वोट किसको किया? उनके साथ एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने वोट आपको किया, मतलब मैंने कांग्रेस को वोट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया, लेकिन मेरी जो पत्नी है, उन्होंने भा.ज.पा. को वोट दिया क्योंकि वह महतारी वंदन योजना का बेनिफिट लेना चाहती थी। जब उनके पति ने उस महिला से पूछा कि अब आप किसको वोट देंगी, तो उनके पति के जो शब्द थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरीके से शब्द का प्रयोग करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अगर तुम भा.ज.पा. को वोट करोगी तो मैं तुम्हारी टांगें काट दूँगा। सभापति महोदय, अगर आप हास्यास्पद भी इस भाषा को प्रयोग करें तो उसमें एक महिला होने के नाते मुझे घोर आपत्ति है। जिस सरकार में, जिस पार्टी में आप रहते हैं, कहीं ना कहीं उस पार्टी की छवि आपकी बातों में, आपके निर्णय की क्षमताओं में दिखती है। मुझे विपक्ष से उम्मीद यही थी, जिस तरीके से उनका बयान अभी हमारे सामने आया है। उसके अलावा भले ही महिलाएँ सामने न बोल पाएँ। अभी आंगनबाड़ी की बात चल रही थी। पोषण ट्रैक ऐप, जो बच्चों के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, आंगनबाड़ी की क्रियान्वयन को लेकर प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में लगाये जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार के माध्यम से यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया गया है, जिसस आंगनबाड़ी में पारदर्शिता आएगी।

माननीस सभापति महोदय, अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजन, जो लगभग हम सब के जिलों में संपादित हुआ। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जोड़े उपस्थित थे। (मेजों की थपथपाहट) हमको एक ऐतिहासिक दिन देखने को मिला क्योंकि जब हम कबीरधाम जिले में उपस्थित थे, तब वहाँ पर हम सबको सुखद अनुभव हो रहा था। जहाँ से आप मंच से सामने देख रहे थे कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ जोड़े उपस्थित थे और सबसे ज्यादा सुखद पल ये था कि जिस जोड़े के माता-पिता वहाँ बैठे थे, जिनको बेटी के जन्म के बाद यह चिंता होती थी कि वे विवाह कैसे होगा, कैसे क्या सामान देना है, खाना पीना भोजन कैसे कराना है, आज वो निश्चिंत दिखाई दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ कन्या विवाह योजना संपन्न हो रही है, वहां किसी मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बात की और उन बेटियों को आशीर्वाद दिया, उनका उत्साहवर्धन किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अनोखी पहल है। इस बार गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत सराहनीय पहल है, जो ऐतिहासिक दृश्य हम सबने उस दिन देखा था। उसके अलावा महतारी सदन की बात करूँ तो आज भले ही हमारी बहने जो विपक्ष में हैं, वह तारीफ न करे । लेकिन हर कोई संतुष्ट है कि नया 212 महतारी सदन का जो निर्माण हो रहा है, वह उनके जिले में ही होना है । सभापति महोदय, हम किसान के बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे । पहले खेती का मतलब धान और फसल के उत्पादन से था, आप देखेंगे कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यहां पर पशुपालन को बढ़ावा देने की बात आई है । राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के साथ जो अनुबंध हुआ है, पहले हम सहकारिता को दरकिनार करते थे, लेकिन सहकारिता में भी कितने स्कोप हैं । अमूल गुजरात को बहुत बड़ा उदाहरण है, दुग्ध डेयरी समिति का गठन जो छत्तीसगढ़ में किया गया है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वह गुजरात की तर्ज पर एक बहुत बड़ा माईल स्टोन तय कर सकता है । हम धान और सब्जी की फसल से आगे बढ़कर पशुपालन में भी अग्रणी राज्य हो सकते हैं । सभापति महोदय, हम वनांचल क्षेत्रों से आते हैं और वहां बहुत बड़ी संख्या हमारे बैगा आदिवासी भाई-बहनों की है, जब हम उनकी परेशानियों की बात करते हैं, सबसे अधिक परेशानी वहां एप्रोच रोड की है। केन्द्र सरकार के द्वारा बनाये गये प्रधानमंत्री जन-मन योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो क्षमता और क्रियान्वयन हमें दिखाई देता है । सभापति महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बहुत चर्चायें हुई है, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ को 5 नये मेडिकल कॉलेज मिले हैं, हमारे कवर्धा को भी इसमें शामिल किया गया है, मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ । नवा रायपुर में बाम्बे हॉस्पीटल के साथ जो एम.ओ.यू. किया गया है, यह बहुत प्रशंसनीय पहल है । सभापति महोदय, जो सामर्थ्यवान है वह दिल्ली, बैंगलौर और अन्य सभी जगहों पर ईलाज कराने के लिये जाता है, लेकिन जो मध्यमवर्गीय परिवार है या जो गरीब परिवार है उनके ईलाज की जब बारी आती है तो एक बहुत बड़ी राहत चाहे हम एम्स की बात करें चाहे बाम्बे हॉस्पीटल के साथ जो एम.ओ.यू. हुआ है उसकी बात करें, कहीं न कहीं उन लोगों को लाभ होगा । सभापति महोदय, हम आयुष्मान योजना की जो बात कर रहे हैं, भले ही आयुष्मान योजना का विपक्ष द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है, जब आप लोगों के पास जाते हैं और उनका आवेदन आता है, जब उनसे पूछा जाता है कि इतना बिल लगा है तो आपने कितना पटाया, वह बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि उन्हें पैसे नहीं लगे हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत अपना ईलाज कराया है। सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है, वह सब को समझ आती है, सब को दिखाई देती है । सभापति महोदय, इसी तरह से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हजारों की संख्या में लगातार ईलाज हो रहे हैं, इसके अलावा महतारी वंदन योजना के विषय में कहना चाहूँगी कि लगातार यह विषय आ रहे थे कि इसका लाभ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसमें नई चीजें जो सामने आई है कि इसका जब सर्वे हुआ तो पता चला कि जो इसमें शामिल हुये उन सभी को उसका लाभ मिला, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अलग से जो संवेदनशीलता दिखती

है, वह यह है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उन क्षेत्र की महिलायें उस लाभ से फुड बेचती हैं, वहां की हमारी 7 हजार बहनों को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- भावना जी, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन के लिए मैं एक विषय जरूर सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। ये वही योजना है पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि 500 रूपये हर माता-बहन को साल भर प्रतिमाह देंगे। ये बात उन्होंने कही थी, 1 रूपए एक माता-बहन को नहीं दिया (शेम-शेम की आवाज) और उसके बाद विष्णुदेव जी की सरकार ने जो माननीय सदस्या बता रही हैं वह कार्यक्रम शुरू किया था।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, विषय बिल्कुल सत्य है क्योंकि लगातार उस समय भी जब हम क्षेत्र में रहते थे, जब विधानसभा के सदस्य नहीं बने थे, जब क्षेत्रों में जाना होता था तो महिलाएं यही पूछती थी कि कांग्रेस की सरकार ने हमें ये वादा किया था कि हमें 500 रूपये मिलेगा तो वो कब मिलने वाला है। आज जब हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब महिलाओं को 1000 रूपये उनके खाते में डायरेक्ट दे रही है तो कभी शायद इन विषयों पे चर्चा ना करके सिर्फ उसे एक मजाक का जरिया बनाते हैं कि आपको महतारी वंदन 1000 मिल रहा है तो इसमें होता क्या है? महोदय जी, उसमें होता क्या है उस महिला से पूछिए जिसका कोई सहारा नहीं है जिसको अपने बच्चे की स्कूल की फीस भी देनी है या फिर जिसको अपने घर का कुछ सामान लाना है उसके लिए 1000 रूपए बहुत बड़ी राशि होती है शायद ये विपक्ष के सदस्य शायद इन चीजों को नहीं समझते।

सभापति महोदय, एक विषय जंगल की कटाई का आ रहा था। मैं उस विषय पर जरूर बोलना चाहूंगी, अभी बहुत हल्ला हुआ कि जंगल कट रहे हैं 'एक पेड़ मां के नाम' इसको भी आप लोगों ने मजाक बना दिया। सभापति महोदय, बहुत आश्चर्य होता है विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, कभी लोकतंत्र चलता है ये बात बिल्कुल सत्य है लेकिन ऐसे विषयों का मजाक बनाना बहुत आश्चर्यजनक है कि 'एक पेड़ मां के नाम' कोई व्यक्ति अगर अपनी मां को याद करके एक पेड़ लगा रहा उसमें किसी को हर्ज क्या हो सकता है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वह कांग्रेस हो लेकिन वनों की कटाई की जो बात आ रही है। अभी आदरणीय हमारे सदस्य सामने बैठे हैं, आपने कहा कि एक पेड़ मां के नाम तो जरूर लगा रहे हैं लेकिन पेड़ किनके नाम

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

पर काटे जा रहे हैं? महोदय जी, हम कवर्धा से आते हैं, हमारे कवर्धा के विधायक माननीय सदस्य भी उपस्थित हैं। हमसे ज्यादा जानकारी शायद इस बात की किसी को नहीं होगी कि कवर्धा के जंगलों में जितने पेड़ कटे हैं वह किनके नाम पर पिछले दो साल पहले कटे हैं वह भी अगर जानकारी हो तो इन विषयों पर भी जरूर जब आपकी बारी आएगी आप लोग अवगत कराएं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। राज्यपाल जी के भाषण पर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और कहीं ना कहीं जो उनके विषय थे जो हम सब ने सुना, आने वाले छत्तीसगढ़ के एक साल का जो रोडमैप तैयार हुआ है, हम सब आने वाले समय पर उज्जवल छत्तीसगढ़ के लिए कामना करते हुए, हमारे रजत जयंती वर्ष जो महतारी गौरव दिवस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, उन सब का अभिनंदन करते हुए अपने सदस्यों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के भाषण जो सरकार ने राज्यपाल से बुलवाए हैं वह पूरा असत्य का पुलिंदा है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज विष्णुदेव साय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो साल पूरा किया है। अभी हमारे पटेल जी ने पूरा विस्तार से बताया, आजादी के बाद अंग्रेज हुकूमत में भी किसान इतना परेशान नहीं हुए जितना इस साल हुए हैं। घर-घर में छापा मारना, धान की खरीदी नहीं करना, इससे पूरे सरगुजा से लेकर छत्तीसगढ़ के धान खरीदी के समय गांव के लोग रोज गाड़ी, चक्का जाम, आंदोलन करते थे।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, दादी को कैसे पता है कि ऐसी समस्याएं थी?

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, इस साल धान खरीदी में इतनी परेशानी हुई कि आज़ादी के पहले कभी नहीं हुई।

श्री अनुज शर्मा :- दादी आपको क्या-क्या परेशानी हुआ वह तो बताईए ?

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, मैंने सबसे पहले इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दी थी। चाहे किसी भी दल से हो, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी खुश होंगे। लेकिन इस सरकार में, आदिवासी मुख्यमंत्री के सरकार में, एक एस.डी.एम. ने आदिवासी व्यक्ति को मार-मारकर मर्डर कर दिया, ऐसा कोई सपना में भी नहीं सोचा था। सरकारी आदमी कोई बचाएगा कि आदिवासी को मार डाले? तो इस प्रकार आदिवासी लोगों,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहे किसान हो, चाहे कुली का काम करने वाले लोग हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हो, लोकतंत्र में उनको हड़ताल करने का अधिकार है। लेकिन सरकार को पहले देखते हैं। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल को देखने के बाद लोग हड़ताल करते हैं। लेकिन इस सरकार में पहले साल से रायपुर में कोई न कोई वर्ग एक न एक हड़ताल कर रहा है। न व्यापारी खुश है, न कर्मचारी खुश है और न किसान खुश है। कोई भी वर्ग खुश नहीं है। इसलिए यह जो लंबा-चौड़ा अभिभाषण राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया, वह पूरा असत्य है। हमारे बस्तर के लिए मैं गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी और यहां की सरकार को एक बात के लिए बधाई देता हूँ। लेकिन उसके अलावा एक काम कुछ नहीं हुआ। हम बस्तर के लोग वर्षों से जल रहे थे, वर्षों से परेशान हो रहे थे। लेकिन आज बस्तर शांति का टापू बनने जा रहा है, उसके लिए मैं गृह मंत्री जी और यहां की सरकार को बधाई देता हूं। नक्सलाइट का जो मुद्दा था, वह कैसे बंद होगा, कैसे लोग जियेंगे, इस बात से हम लोग परेशान थे। लेकिन आज वहां के लोगों के द्वारा चैन से जीने की कोशिश जरूर हुई है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने भी यह सोचा नहीं था कि यह बंद होने वाली चीज होगी। लेकिन 2026 का गाइडलाइन था और मेरे ख्याल से वह लगभग पूरा हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) अच्छे काम के लिए तो मैं राजनीति से ऊपर उठकर धन्यवाद दूंगा। बस्तर के लोग उस बात के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन अब और परेशान हैं कि बस्तर का जंगल बचेगा या नहीं बचेगा? बैलाडीला पहाड़ बचेगा या नहीं बचेगा? अबूझमाड़ बचेगा या नहीं बचेगा? अब आदिवासी लोग और परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को सरकार ने नक्सलाइट से मुक्त किया। पहले बंदूक के डर से लोग रोज रात को सो नहीं पाते थे, खेती नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी हम खेती करेंगे, मुर्गा बाजार जाएंगे, शादी करेंगे। लेकिन अभी यह सरकार अबूझमाड़, बैलाडीला पहाड़, जंगल को खाली करने के लिए सोच रही है। सभापति महोदय, आपने महाभारत में देखा होगा कि खासकर आदिवासी लोगों के पास चाहे धान रहे या नहीं रहे, वह खेती करे या नहीं करे, लेकिन हम लोग जंगल की पूजा करते हैं। हम लोग जंगल को मानते हैं और जंगल है तो जीवन है। इसलिए मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जिन्होंने पहले आंध्रप्रदेश, तेलंगाना पलायन किया था, वह लोग भी अब वापस आने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि वहां के जंगल को उजाड़ने का काम मत करें। बस्तर में तिहार में माननीय राष्ट्रपति जी भी आई थीं। यह कौन सा तिहार है? हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी उधर से ही आते हैं और हम भी आते हैं। वहां का तिहार अगले महीने होगा। आम का तिहार। आम का पंडुम। हम लोग आम को पंडुम बोलते हैं। आम पकता है और हम लोग आमा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खाते हैं तो पंडुम होता है। हमसे भी जुड़े जाते हैं तो हम भी पंडुम मनाते हैं। आप माननीय राष्ट्रपति जी को भी ले आये और पंडुम तिहार मना रहे हैं। हम तो गांव-गांव में बोकरा, मुर्गा काटकर पंडुम मनाते हैं। जब आम का पंडुम होता है तो चाहे कलेक्टर हो, एस.पी. हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यदि वह उस गली से जाते हैं तो हम उनको वहां से जाने नहीं देते हैं, उनका रास्ता छेकते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। हम उसको पंडुम बोलते हैं। यह कौन सा नया पंडुम हो गया कि कबड्डी खेलाकर पंडुम मना रहे हैं। इस तरह से गुमराह करने की बात और भटकाने का काम [XX][5] और बी.जे.पी. कर सकती है। लोगों को, समाज से समाज को लड़ाओ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, ईसाई, मुस्लिम में ध्रुवीकरण कराओ। इस प्रकार हमारा बस्तर शांति का बस्तर है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अभिभाषण में ऐसा कोई भी प्वाइंट नहीं है और यह आपत्तिजनक है कि आप किसी ऐसे राष्ट्रीय संगठन का नाम यहां पर उल्लेखित कर रहे हैं, जो सांस्कृति राष्ट्रवाद की व्यवस्था के साथ देश में काम कर रहा है। मैं इस विषय पर आपत्ति लेता हूं। मैं प्वाईंट ऑफ ऑर्डर में आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसको विलोपित किया जाये। यह अभिभाषण का हिस्सा नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- इसमें है। (व्यवधान) का हवाला है इसमें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, लखमा जी ने सिर्फ बात का उल्लेख किया है। उनकी कोई राजनीतिक द्वेष भावना नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है। इसमें विलोपन वाली कोई बात नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- इसको विलोपित किया जाये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इसमें कोई द्वेष भावना नहीं है। लखमा जी ने अपनी बात का उल्लेख किया है।

श्री रामकुमार यादव :- भाषण के दौरान आप लोग भी कांग्रेस का नाम लेते हैं।

---

[5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशांत शुक्ला :- कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है। (व्यवधान) आप उसके प्रतिनिधि हैं। उसने यहां 5 साल तक यहां सत्ता में राज किया है। आप किसी पर भी ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। सभापति महोदय, इसे विलोपित किया जाये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इसमें कोई भी विलोपित करने वाली बात नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- इसमें आप भी कांग्रेस और लेते हैं।

सभापति महोदय :- मैंने आपकी आपत्ति सुन ली है। आप बैठ जाईये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, तो वहां भी किसान लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि विकास तो नहीं करना है, लोगों की धान खरीदी नहीं करनी है, लोगों को पीने का पानी नहीं देना है। जब मैंने उस बात को बोला तो शुक्ला जी, आपको मिर्ची लग गई। धन्यवाद।

समय: 3.36 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मिर्ची तो किधर-किधर लगी है, यह तो वही बता सकते हैं जिनको लगी है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, ज्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि जो जल जीवन मिशन योजना है। जब इसकी शुरुआत हुई, तो लोग बोल रहे थे कि आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन यदि पीने का पानी नहीं रहेगा तो आदमी गरीब हो, अमीर हो, चाहे पंडित हो, पुजारी हो, सेठ हो, चाकर हो, वह पानी तो जरूर पियेगा। कोई रोटी नहीं खाने वाला है, कोई कुछ नहीं खाने वाला है, लेकिन वह पानी तो जरूर पियेगा।

श्री केदार कश्यप :- दारू भी पियेगा।

श्री कवासी लखमा :- दारू दूसरे लोग पीते हैं। हमारे गृह मंत्री जी से पूछिए, वह कहां से पियेंगे। वह मुर्गा थोड़ी न खाएंगे। आप और मैं खा सकते हैं। वह तो पंडित आदमी हैं। जल जीवन मिशन योजना के लिए गाँव के लोगों ने भारत सरकार को बहुत साधुवाद दिया है। आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी और हमने भी गाँव-गाँव जाकर अपने भाषण में बोला होगा कि अब आपकी पत्नी घुंडी में पानी नहीं लायेगी, घर में नल लगेगा और पाईप को घुमाएंगे तो सुर-सुर पानी निकलेगा। लेकिन वह टंकी तो बन गई लेकिन वह टंकी गिर रही है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में 9 हजार करोड़ रूपये का घोटाला करके खचाखच-खचाखच अलमारी भराकर किस मंत्री के घर में फाईल जली है, यह तो बता दीजिये।

सभापति महोदय :- सुशांत, बैठिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, पीने के पानी के लिए बहुत लोग पूछते हैं। लेकिन अभी कोई भी ग्राम में, किसी भी घर में जाकर देखिये। कभी पाईप टूटा मिल रहा है, ठेकेदार पाइप फेंककर भाग गया, दीवार को खोद दिये, गली, रोड को खराब कर दिये लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय रहते सरकार ...।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह किसकी सरकार में हुआ है, यह तो बताईये ? 30 प्रतिशत, 36 प्रतिशत above में काम लेकर ठेकेदारों को यू.पी., बिहार ...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 2 साल में तुमन का करत हव ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- भ्रष्टाचार के (व्यवधान) आप है और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं बोल रहा हूं ना आप बैठिये तो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप 2 साल से क्या कर रहे हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह कहां की बात हुई, आप बताईये ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये तो।

श्री सुशांत शुक्ला :- जल जीवन मिशन में घोटाला यह करें और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- शुक्ला जी, ये 2 साल में का करत हस ? बइठे-बइठे आलू छिलत हस का ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप भी बैठिये। अंबिका जी, बैठिये तो।

श्री सुशांत शुक्ला :- तुंहर घोटाला ला साफ करे हन, जल जीवन मिशन मा तुंहर कर्म ला ठीक करे हन।

श्री कवासी लखमा :- अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में नया कानून बनाया उसका हम सब लोग तारीफ करते हैं।

सभापति महोदय :- लखमा जी, एक मिनट। लखमा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत पुराने विधायक हैं, मेरा आग्रह है कि उनके भाषण में अभी आप लोग टोका-टाकी न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग भी बैठिये और उनको बोलने दीजिये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सड़क गांव-गांव में बनी, उसका नाम अभी-भी लोग लेते हैं। इसलिए जो योजना अच्छी बनती है जैसे प्रधानमंत्री सड़क, जल जीवन मिशन, यह अभी वर्तमान प्रधानमंत्री की योजना है, उनका लाभ उन गरीब लोगों को मिले। हमारी सरकार के 5 साल गये। आपकी सरकार 5 साल के लिए आयी तो क्या हमारी योजनाओं को छोड़ देंगे ? जो सरकार चली गयी तो क्या उसका काम नहीं करना है ? इसलिए स्व. राजीव गांधी ने पंचायती राज को लाया और पी.व्ही.नरसिंह राव जी ने पंचायती राज को लागू किया, ग्राम पंचायत राज चालू हुआ। लेकिन आज पंचायत के सरपंच हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत हो, आपकी पार्टी के लोग जीते हैं इसलिए विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन वह जो ग्राम का सरपंच है, जिला पंचायत को 1 रुपये नहीं मिल रहा है। वह लोग रोज हड़ताल कर रहे हैं। जो 40वें वित्त आयोग का पैसा डॉयरेक्ट पंचायत को आता था, वह भी कलेक्टर ऑफिस में, जिला पंचायत में दूसरे लोग काम रहे हैं। ये क्या हो गया है? पंचायती राज किधर जा रहा है? इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज में उनको अधिकार दिया गया है। एक मुख्यमंत्री को चेक काटने का पावर नहीं है, सिर्फ सरपंच को चेक काटने का पावर है। अक्सर कई लोग अगली बार चुनाव लड़ने के लिये तैयार नहीं होंगे। मैं वार्ड मेंबर से चुनाव लड़ा था, सरपंच चुनाव लड़ा था। मैं समझता हूं कि सरपंच को जितना अधिकार है एम.एल.ए. लोगों के पास कुछ पावर नहीं है। पट्टा बनाने का, बिजली का बल्ब लगाने का, सड़क बनाने का अधिकार है। लेकिन आज सरपंच लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पंचायत में कोई पैसा ही नहीं है। ये क्या हो गया? इसलिए आज जंगल, जमीन का जो वन पट्टा है, हमारी सरकार में पट्टे की बहुत मांग कर रहे थे। खासकर बस्तर में उस समय नक्सलाइट के कारण लोग पट्टा लेने के लिए तहसील ऑफिस नहीं आ रहे थे। आज वह पट्टा मांग रहे हैं। चाहे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बीजापुर के लोग, अबूझमाड़ के लोग, नारायणपुर के लोग हों। माननीय वन मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि वह उस क्षेत्र के ही हैं, उनको पट्टा मिले। उन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों की भावना बनी है कि छत्तीसगढ़ राज्य कैसा राज्य है, अधिकारी लोग राज चलाते हैं। अभी एक मंत्री बोल रहे थे कि हम कलेक्टर को नहीं बोल सकते। आज हम लोग अभी बहिर्गमन किये थे। एक अधिकारी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए थे। देश मे दो, तीन लोग ही वीटो पावर में हैं। एक तो देश में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री और जिला में कलेक्टर है। आज मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, यहां अधिकारी आये नहीं थे। ये क्या हो गया है? अधिकारी लोगों को राज चल रहा है या मुख्यमंत्री का राज चल रहा है या बी.जे.पी. पार्टी की सरकार चल रही है? मैं एक बार टूर में गया था, उस समय प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी विधान सभा अध्यक्ष थे, सभापति महोदय आप भी थे। हम लोग आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गये थे। मैं आस्ट्रेलिया में ऐसी धोती मारकर एक जगह घूम रहा था। वह लोग बोले कि आप कहां से आये हो? मैं बोला कि हिन्दुस्तान से आया हूं। वह बोले कि हिन्दुस्तान में कहां से हैं? मैं बोला कि हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ से आया हूं। छत्तीसगढ़ तो हिन्दुस्तान में है ही नहीं। मैं उन लोगों से पूछा कि आप लोग कहां से हैं? वह लोग बोले कि हम गुजरात से हैं। हम लोग 40 साल से आस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को मालूम नहीं है मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है। वहां के लोग बोल रहे थे कि वहां अधिकारी राज चलता है, वहां नेता लोगों का राज नहीं चलता है। वहां पर मेरे को बोल रहे थे, अभी भी मेरे को याद है। इसी प्रकार आज यहां सचमुच में पता चला है कि यहां मुख्यमंत्री, गृहमंत्री बैठे हैं और अधिकारी नहीं हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, टोकाटाकी न करें।

श्री कवासी लखमा :- मैं इस बात का उल्लेख किया हूं, अगर सदन को ऐसा कुछ लगता है तो उसको विलोपित कर दें। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय :- हां, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री सुशांत शुक्ला :- दादी, वरिष्ठ विधायक हैं, उनको बड़ी जल्दी याद आया कि न्यूजीलैंड में किसने, कब कहां, क्या बोला था। अभी मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार में युवराज और युवरानी आये थे, 01 किलोमीटर तक फूल बिछा था, तब यहां पर किसकी चलती थी?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आधी सरकार जेल पर थी, आधी सरकार बेल पर थी और यह आज बात कर रहे हैं किसकी चलती है। हम भी तो पूछना चाहते है कि पिछली सरकार में किसकी चलती थी?

सभापति महोदय :- हो गया, अब लखमा जी बोलिये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलकर दो मिनट लेता हूं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में सड़कें नहीं बन रहीं हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, यहां पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री नहीं हैं, सरकार तो यहां है। मेरे विधानसभा में 400 पुल । मलगल नदी, गादीरास, झीरमपाल उसी नदी में और एक पुल कांजीपानी और एक कांजीपानी में, बोर्री नदी में, एक बारू नदी में बोगलाघाट जैसे ही सरकार बदली वह पुल को कैंसिल कर दिया, स्लेब डलने का बचा है, पूरा कंपलीट हो गया था तो यह सरकार की कैसी सोच है ? मैं उस पुलिया में अकेला भी जा सकता हूं, कांग्रेस पार्टी का आदमी जा सकता है, जनता के जाने के लिये पुल बनता है । सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि वह पुल पुन: बने तो इस प्रकार की भावना रखने से विकास और जनप्रतिधि की उम्मीद कम होती है तो हमारे पहले वक्ता ने बहुत विस्तार से बताया । यह धान खरीदी मामला और बिजली बिल 1-1 महीने में 1-1 हजार रूपये बहिनी लोगों को दे रहे हैं । 1 हजार रूपये नहीं, 20,000 रूपये दो, कोई दिक्कत नहीं है । सरकार का पैसा है, छत्तीसगढ़ की जनता है, उनको मिलना चाहिए लेकिन 1 हजार रूपये देकर बिजली बिल इतना बढ़ा दिये । 12,000 रूपये, 5 लाख रूपये, एक विधवा महिला के पास 5 लाख रूपये का बिल आया तो 1 हजार रूपये देने से क्या मतलब है ? तो इसलिये 1 हजार रूपये देने के साथ हमारा बिजली बिल को कम करो न, हम लोगों ने कम किया था । इसको बढ़ाने का काम क्यों किये? क्योंकि एक तरफ से दो और एक तरफ से लो तो दोनों तरफ से आज हमारे तेंदूपत्ता की नीति ।

माननीय सभापति महोदय, जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मध्यप्रदेश था, उन्होंने ठेकेदारी बंद किया था मतलब तत्कालीन मध्यप्रदेश में तो सरकारी तेंदूपत्ता लेना है, समिति लेना है तो उस कानून को जब छत्तीसगढ़ बना, अजीत जोगी जी की सरकार थी तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि तेंदूपत्ता सरकारी वाला लेने से यह पैसा लोगों को नहीं मिलता है, ज्यादा तोड़ते नहीं हैं । सरकारी काम, सरकार जैसा ही तुड़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राईवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे में कितना ज्यादा अंतर रहता है । उसी प्रकार तेंदूपत्ता की नीति, चूंकि उस समय केवल दंतेवाड़ा जिला था । एक जिला बीजापुर-सुकमा मिलाकर एक जिला था, माननीय रमन सिंह जी ने बीजापुर अलग कर दिया, सुकमा भी अलग कर दिया । धन्यवाद लेकिन हम लोग तो जिला मांगे नहीं थे । जिला अलग कर दिया लेकिन जब वर्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2004 में सरकार बदली तो माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, वह नीति को पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया । जो दंतेवाड़ा में चल रहा था, पूरे मध्यप्रदेश में शिवराज जी ने चालू कर दिया लेकन पिछले साल से हमारे बस्तर में बंद कर दिये, वहीं ज्यादा तेंदूपत्ता है । वहीं के हमारे वन मंत्री जी हैं तो इस साल भी वहां टेंडर नहीं हुआ । पूरे छत्तीसगढ़ में टेंडर हो गया और तेंदूपत्ता वहीं ज्यादा टूटना है । उसके पहले साल में केवल सुकमा वनमंडल में 100 करोड़ रूपये लोगों को पैसा मिला था । हमारे बीजापुर में धान खरीदी सबसे कम, छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में सबसे कम खरीदी हुई है, दंतेवाड़ा में । हम लोग धान खरीदी कम करते हैं, हमारे गृहमंत्री जी अभी बस्तर में बहुत घूमे हैं, उन्होंने देखा होगा कि धान की खेती अच्छी नहीं है। उबड़-खाबड़ रहता है, खेत को ठीक नहीं करते हैं, उन लोग वन उपज से जीवित रहते हैं तो इसीलिये पिछले साल, उसके पहले साल में 100 करोड़ सुकमा वनमंडल को मिला था, 52 करोड़ बीजापुर को मिला था । फर्स्ट नंबर सुकमा वनमंडल था, पहला नंबर बलरामपुर था । वहां 3 विधानसभा है, और सुकमा जिला 1 विधानसभा का है, 100 करोड़ मिला था । पिछले साल 10 करोड़ का तेंदूपत्ता नहीं टूटा, इस साल भी यही हाल हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता ठेकेदारी हुआ । हमारे बस्तर संभाग में कांकेर से लेकर बस्तर में नहीं हुआ तो ऐसे कैसे होगा? एक तरफ तेन्दूपत्ता ज्यादा होता है और वहां पर सरकारी रेट कम है। यहां पर तो एक कानून चलना है । एक राज में दो कानून कैसे चलेगा? तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अभी भी समय है। उधर भी तेन्दूपत्ता की ठेकेदारी हो। उसी प्रकार हमारा जो टोरा, ईमली, महुंआ है हमारे क्षेत्र में ही ज्यादा होता है । हमारी सरकार के समय हम लोग जंगलों से 52 प्रकार वनोपज खरीदते थे। अभी यह धीरे-धीरे कम हुआ है। हम कह रहे थे कि इसमें प्रतिस्पर्धा हो और इसे समिति भी खरीदी करे, महिला स्वसहायता समूह भी खरीदी करे और सेठ-साहूकार भी खरीदी करे, जिनका ज्यादा रेट होगा उससे आदिवासी लोगों को लाभ मिले। ऐसी योजना बनानी चाहिए। अभी बस्तर में जो तेन्दूपत्ता का निजीकरण, उसका टेण्डर नहीं हुआ। अभी समय है अगर यह सरकार कर सकती है तो उसे करे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जो अभिभाषण दिया है। हमें अनुदान मांगों पर भी बोलना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार की हालत अच्छी नहीं है। यहां चाहे कर्मचारी, किसान हों, मजदूर हों, चाहे नवजवान हो, सभी परेशान हैं। उस समय तात्कालीक शिक्षा मंत्री ने कहा था, अभी रायपुर की बात बता रहा हूँ उन्होंने कहा था कि प्रदेश में 35 हजार शिक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। फिर मंत्री बदल गये और अब दूसरे मंत्री कह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे हैं कि प्रदेश में 5 हजार शिक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। अब अगर 5 हजार शिक्षाकर्मियों की भर्ती होगी तो कब होगी ? इसका कोई पता नहीं है। अभी यहां पर आदिवासी लोगों, गांव के किसानों, महिलाओं के ऊपर जो इतना अत्याचार हो रहा हैं यहां बलात्कार, मर्डर, के मामले इतने अधिक हैं कि यह बिहार को पीछे छोड़ रहा है। पहले हम लोग बिहार का सुनते थे कि वहां पर मर्डर हो गया, वहां गोली चल गयी यहां तो आदिवासी को मार रहे हैं। ऐसे में यह सरकार कैसे चलेगी, हमारे आदिवासी लोग कहां जाएंगे? वहां जंगलों में रहने वाले लोग हैं। यहां पर बड़ी-बड़ी रेल लाईनें आ रही हैं, यहां बड़े-बड़े उद्योग आ रहे हैं, लेकिन हमारे बस्तर तक रेल लाईन नहीं पहुंची है। हमारे बस्तर के सुकमा तक रेल लाईन जा रही थी, वह भी बंद हो गयी। वहां तक रेल लाईन का विस्तार होना चाहिए, लेकिन वह बंद हो गयी। मैं सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि बस्तर तक रेल लाईन का विस्तार करे। हमारे रावघाट से दुर्ग तक तो रेल लाईन पहुंच गयी क्योंकि वहां राव घाट में कच्चा माल होता है, लेकिन बस्तर तक जाने के लिए कोई रेल लाईन नहीं है। हमारा बस्तर केरल राज्य इतना बड़ा है वहां पर न रेल लाईन है, न बस्तर तक हवाई मार्ग की कोई सुविधा है । कभी-कभी हमारे केशकाल घाट में गाड़ी इतनी जाम होती है, पहले वहां पर बाईपास रोड बनने वाला था, अब वह भी वहां नहीं बन रहा है। वहां केशकाल घाटी में जल्दी एक बाईपास सड़क बनायें और जो बिजली का बिल है, उसको हाफ करे, मैं इसी गुजारिश के साथ, इतना कहते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद् । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर धन्यवाद् ज्ञापित करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस सदन के समक्ष राज्य सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं का विस्तृत रूप से एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया है। माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण केवल संवैधानिक, केवल औपचारिकता ही नहीं था, बल्कि वह विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का दस्तावेज है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण की जो प्रतिबद्धता दिखायी दी है, वह हमारी सरकार की नीति और नियत दोनों को दर्शाता है। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज, दूरस्थ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अंचलों के विकास पर जो जोर दिया गया है, वह छत्तीसगढ़ की आत्मा के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र जिला जशपुर का प्रतिनिधित्व करती हूँ। हमारा क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा और श्रमशील मानव संसाधन का क्षेत्र है। जब माननीय राज्यपाल जी ने आदिवासी युवाओं के कौशल विकास, महिला स्व सहायता समूह की मजबूत शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख किया तो सरगुजा की एक प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार केवल योजना नहीं बना रही है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की वास्तविक प्रयास कर रही है।

माननीय सभापति जी, इस नए विधान सभा के नए सदन में माननीय राज्यपाल जी अभिभाषण दे रहे थे तो हमें यह महसूस हो रहा था कि यह नए छत्तीसगढ़ विधान सभा के नये भवन का नया आगाज़ है और नई दिशा की ओर जाने वाली हमारी छत्तीसगढ़ विजन 2047 तक विकसित भारत में मील का पत्थर साबित होगा तो यह भवन साक्षी बनेगा । आज इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । यह छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा होने के नाते जब किसान विकास करेगा, तब छत्तीसगढ़ विकसित होगा और छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत देश भी विकसित होगा । जब महिलाओं की बात होगी, अगर महिला सशक्त बनेगी तो छत्तीसगढ़ को विकसित बनने से कोई रोक नहीं सकता है । छत्तीसगढ़ युवाओं का प्रदेश है । अगर युवा विकास करेगा तो निश्चित है कि छत्तीसगढ़ मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा । अगर गरीबों के उत्थान की बात होगी तो गरीब सशक्त बनेंगे, तभी छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ेगा ।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में माननीय राज्यपाल जी ने 106 बिन्दुओं पर अपनी बात रखी है । सभी बिन्दुओं को समाहित करते हुए इसमें उल्लेख किया गया है । यह अभी विकसित छत्तीसगढ़ की नींव बन रही है । अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा । जब नींव बनकर नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ेगा, तब समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ विकास कर रही है और विकसित छत्तीसगढ़ बनने में यही बात मील का पत्थर साबित होगी।

सभापति महोदय, मैं किसान परिवार से आती हूं। किसान होने के साथ-साथ मैं आदिवासी भी हूं, आदिवासी होने के साथ-साथ मैं महिला भी हूं। मैं इसीलिए कह सकती हूं कि आज हमारी सरकार ने किसानों के धान को 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से 3100 रूपए प्रति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्विंटल में खरीदी की गई है । इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उसका बयां किसान की कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। जब गांव का किसान धान बेचने के लिए जाता है और उसके खाते में पैसा जमा होता है तो पैसा जमा होने के साथ ही उसको और अधिक प्रेरणा मिलती है कि आने वाले वर्ष में मुझे और अधिक धान का उत्पादन करना है । जो उसके मन में भाव उठता है, उसे किसान ही जानता है कि वह क्षण क्या होती है और वह खुशी क्या होती है।

सभापति जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक चीज और हो रही है इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं कि राज्य के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सालाना 10 हजार रूपए मिलना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। अगर भूमिहीन किसानों को साल में 10 हजार रूपए मिलते हैं तो वह उसके लिए बहुत होते हैं। यह हमारी सरकार की उल्लेखनीय योजनाएं हैं । इसे हमारे विपक्ष के साथियों को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने 5 सौ रूपये देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने की भी वादा किया था, लेकिन किसी को नहीं मिला। इसलिए यह बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, मैं एक चीज और बताना चाहती हूं। कोदो और रागी जैसे मिलेट की खेती को गरीब की खेती, आदिवासियों का भोजन माना जाता था। लेकिन आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका उल्लेख होता है। कोदो और रागी जैसे मिलेट की खेती का उल्लेख होता है तो यह सुनकर हम लोगों को गर्व होता है, खुशी होती है कि मिलेट को बड़े-बड़े लोग टेबल में सजाकर खाने के लिए रखते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि गांव में उगने वाली रागी और कोदो को आज पूरी दुनिया खोजने लगी है कि मिलेट क्या चीज है। आज विष्णुदेव साय जी की सरकार तथा इसको भी सामने लाने वाले हमारे देश के मुखिया श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसको श्री अन्न का नाम दिया है। यह बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, पशुपालन का विषय आता है। अगर आज किसान पशुपालन और डेयरी के साथ जुड़ता है तो हमारे किसानों का उत्थान ही देश का उत्थान है। मैं आज एक और चीज बताना चाहती हूं कि 73 हजार हैक्टेयर से अधिक सिंचाई सुविधा में विस्तार एवं पुनर्स्थापना के लिए 477 सिंचाई योजनाओं के लिए 1,874 करोड़ रूपये की भी स्वीकृति दी गई है। यह एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुत बड़ा विषय है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। किसान होने के नाते जब किसान विकास करेगा तब देश विकास करेगा, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। आज हमारे विपक्ष के साथी इस विषय में बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। हम लोग भी गांव में ही रहने वाले लोग हैं। गांव की जो परिस्थिति है, उसको शहर के लोग नहीं जानेंगे। गांव के लोग गांव की भाषा को जानेंगे। आज ग्रामीण क्षेत्र की माताओं-बहनों की हुनर को आगे बढ़ाने के लिए महतारी सदन बना है, मैं उसके लिए हमारे पंचायत मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। वह यहां पर बैठी हैं। जब गांव में महतारी सदन बनता है तो ऐसा लगता है कि दिल्ली शहर और रायपुर शहर यहां ही आ गया है। मेरे क्षेत्र में पहली बार महतारी सदन बना है। मैं महतारी सदन देखकर हैरान हो गई। मैं पहले कागज में देखी थी, लेकिन जब महतारी सदन बनकर तैयार हो गया तो मुझे लगा कि गांव में महतारी सदन बना है तो यह शहर का एक मकान बना है। इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। महतारी सदन महिलाओं का हृदय है। मैं इसके साथ ही साथ एक चीज और भी कहना चाहती हूं कि कम से कम हर विकासखण्ड में 3-3, 4-4 महतारी सदन बन जाये तो क्या बात है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मैं इसके बारे में हर बजट सत्र में बोलती हूं कि गांव का जो किसान होता है, वह अपनी बेटी की शादी करने की तैयारी करता है तो वह अपने खेत को गिरवी रखता है या अपने जेवर को गिरवी रखता है या तो फिर किसी से उधारी मांगता है, तब जाकर बेटी की शादी करता है। उस समय डॉ. रमन सिंह की पहली सरकार थी और आज आप उस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। जब डॉ. रमन सिंह प्रदेश के मुखिया थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ किया था। गरीब के दिल को कितना सुकुन मिला होगा, वह गरीब किसान ही जानता होगा कि एक बेटी का विवाह करने में कितना खर्चा लगता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से 6,412 जोड़ियों का सामूहिक विवाह हुआ, यह काबिले तारीफ है, मैं इसकी तारीफ करती हूं और मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। यहां महिला एवं बाल विकास मंत्री जी बैठी हैं, मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। महोदय जी, आज अगर मैं बस्तर की बात करूं, मेरे पूर्व वक्ता मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, बोल रहे थे कि बस्तर, बस्तर, बस्तर, तो बस्तर में विकास की कनेक्टिविटी को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिसमें से 146 सड़क पुल पुलिया निर्माण हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि सरगुजा संभाग बिल्कुल ही अलग भौगोलिक स्थिति है। वहां का रहन-सहन भी थोड़ा अलग है, क्योंकि कनेक्टिविटी से कोसों दूर था। मैं तो गांव से आती हूं, इसलिए बड़े अच्छे ढंग से जानती हूं कि पहुंच-विहीन किस चीज़ को बोला जाता है, यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है। पहले पहुंच-विहीन ऐसा हुआ करता था कि बरसात के पहले चार महीना का चावल पहले डंप किया जाता था, भंडारण किया जाता था और चार महीना बरसात के दिन कोई जा ही नहीं पाता था। ऐसी बस्तर और सरगुजा की स्थिति थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भी बनी, राज्य में भी बनी तो आज वह कनेक्टिविटी सब जगह जुड़ गयी है। आज कोई ऐसा कोई विषय ही नहीं रह गया है कि बरसात के पहले हम लोगों को चार महीना का चावल भंडारण करना है, ऐसा कोई विषय नहीं है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है और निरंतर आगे होते रहेगा। साथियों, आज एकलव्य विद्यालय की बात आती है, केंद्र सरकार की बड़ी अच्छी सोच है। आज मैं हमारे स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस सदन से बहुत धन्यवाद भी देती हूं। स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मेरा धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि एकलव्य विद्यालय आदिवासियों के लिए बनता है और मैं हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि उनसे पहले कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन किसी ने आदिवासियों को लेकर कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने आदिवासियों के लिए सोचा तो आदिवासी मंत्रालय भी बनाये और आदिवासी कमीशन भी बनाये और उसी के माध्यम से एकलव्य विद्यालय बना क्योंकि एकलव्य एक आदिवासी भील परिवार से आता था, इसीलिए उसके नाम से एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाया गया है और पूरे देश में बनाया गया है और बड़ा विकसित है। जिनका संसाधन सुविधा का कोई पैमाना नहीं है। आज चाहे खान-पान में हो, चाहे रहन-सहन में हो, चाहे उनका वहां रहकर विद्यार्जन करने का विषय हो तो आज एकलव्य विद्यालय भी है, इसके लिए भी आप लोगों ने बजट में प्रावधान रखा है, हमारे राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया गया है, इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल जी को बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय :- गोमती जी, समाप्त करियेगा। 14 मिनट से ज्यादा हो गया।

श्रीमती गोमती साय :- जी जी, जरूर। आज मैं नया रायपुर में बॉम्बे हॉस्पिटल के एम.ओ.यू. के लिए भी बात कर रही हूं, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य खराब होता है, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, तो बॉम्बे जाने में महीनों भर उनको इलाज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन आज इसके माध्यम से 680 करोड़ रुपये की लागत से अगर यह इंफ्रास्ट्रक्चर 300 बिस्तर का बनेगा, तो हमारे जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, यहां रहकर इलाज कराएंगे। सभापति महोदय जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। यह गांव-गांव तक पहुंचा है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। 2,426 किलोमीटर लंबाई की इसमें से 774 सड़कों की स्वीकृति मिली है, यह कोई छोटा विषय नहीं है। यह बहुत बड़ा विषय है, इसलिए उसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। क्योंकि जब यह रोड बनता है तो गांव में लगता है कि काला रोड आया है और गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे गांव में हमारे घर के द्वार तक पहुंचा है। तो यह बड़ा विषय है। आज बहुत सारा ऐसा विषय है जो बजट भाषण में भी बोलने का अवसर मिलेगा तो जरूर उल्लेख करेंगे। यही छत्तीसगढ़ की नींव है, विकसित भारत देश बनने में विकसित छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। माननीय सभापति महोदय जी, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी और राज्यपाल महोदय जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय का अभिभाषण हमें यह विश्वास दिलाता है कि छत्तीसगढ़ शांति, विकास, समृद्धि के नए युग में प्रवेश कर चुका है। हमारी सरकार ने जो दिशा तय की है, वह राज्य को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी और सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो अभिभाषण दिया है, मैं उनका स्वागत करने के लिए यहां उपस्थित हुई हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से अभी हमारे सदस्यगण हमारे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का अपने-अपने शब्दों में वाचन किया है और उन्होंने सभी विषय को समायोजित किया है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए संक्षप्ति में अपनी बात रखना चाहूंगी। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से दो सालों में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का विकास हुआ है, उस विकास को हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में समायोजित किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में, भारत में हम लोग अपने समाज में अपनी माँ को, अपनी बेटी को एवं अपनी बहुओं को भगवान के रूप में, देवियों के रूप में पूजा करते हैं। इस प्रकार हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में महतारी वंदन योजना के तहत हमारी बहनों, हमारी बेटियों व हमारी बहुओं के खाते में हर महीने 1000 रूपये डालने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना को 01 मार्च, 2024 से शुरू की थी और 18 मार्च, 2024 को महतारी वंदन योजना की पहली किश्त राशि को उनके खाते में डालने का काम किया था। आज हमारी विष्णु देव साय जी की सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना की राशि को उनके खाते में लगातार 24 किश्तों में डालने का काम किया है। सभापति महोदय, यहां तक ही नहीं, हमारे प्रदेश के सभी विकासखंडों में, सभी गाँवों में महतारी सदन भी बनाये जा रहे हैं। यहां हमारे पंचायत मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद दूँगी। (मेजों की थपथपाहट) सभी

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

जगहों पर जो महतारी सदन बनाये जा रहे हैं, वह महतारी सदन एक भवन ही नहीं, बल्कि यह हमारी महिलाओं की सशक्तिकरण और महिला नारी शक्ति की एक पहचान है।

आदरणीय सभापति महोदय, यहाँ पर हमारे सभी सदस्यों ने कृषि के बारे में बात की है। हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। जब किसान विकसित होगा, तभी हमारा छत्तीसगढ़ विकसित होगा। किसानों के लिए पशुपालन, मछली पालन और अन्य प्रकार की किसानों से संबंधित विषय हैं, आज इन सारी विषयों को इस भाषण में लिया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी एक वनांचल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह बलरामपुर जिला के अंतिम छोर सामरी विधान सभा है। वहाँ पर सभी गाँव जंगल से घिरे हैं और वहाँ पर आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा निवास करते हैं। सदन के भीतर तेंदूपत्ता का भी जिक्र हुआ है, मैं भी उस ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, मैंने भी तेंदूपत्ता तोड़ा है । जब मैं तेंदूपत्ता तोड़ रही थी तो सैकड़ा में 200 रूपया मिलता था, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो 5500 रूपये सैकड़ा देने का काम हमारे विष्णु देव साय सरकार ने किया है।

श्रीमती संगीता सिनहा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, तेंदूपत्ते का मानदेय बढ़ाने का कार्य माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था । बोनस भी नहीं आया है । बोनस कहीं पर भी नहीं मिल रहा है।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता तोड़ने के लिये जो 5500 रूपया दिया जा रहा है, यह उसी में समायोजित है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो भी आदिवासी किसान, भाई-बंधु लोग हैं, उस समय तेंदूपत्ता तोड़ते थे, उन पैसों को बचाकर रखते थे कि जब हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करने जायेंगे तो उनके स्कूल और कापी-पुस्तक सहित ड्रेस खरीदने के लिये इस राशि का उपयोग करेंगे । सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी इन सारी समस्याओं को दूर करते हुये सामूहिक विवाह योजना को भी इसमें जोड़ा है और पूरे प्रदेश में 6712 जोड़ों का विवाह किया है । आदिवासी अंचलों में जो हमारे गरीब आदिवासी होते हैं, उनको किसी से कर्जा लेना पड़ता था, बच्चों के बड़े होने पर विवाह की चिन्ता रहती थी कि उनका विवाह कैसे होगा, इसका समाधान हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारी बहन महिला बाल विकास मंत्री बहन लक्ष्मी रजवाड़े जी ने किया है । इससे आदिवासी परिवार की एक बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति मिली है । आदरणीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत जो सड़क बनाई जा रही है, मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं जिस विधान सभा से आती हूँ वहां पर सबसे पिछड़ी हुई जनजाति पहाड़ी कोरबा लोग निवास करते हैं । मुझे यह बताते हुये बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वहां पर 54 ऐसे प्रधानमंत्री जन-मन सड़क बनाई जा रही है तथा बहुत सड़के बनकर तैयार भी हो गयी है और इस योजना के तहत बहुत से कार्य हो भी रहे हैं । सभापति महोदय, हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है कि अंतिम छोर में निवास करने वाले पहाड़ी जनजाति को मूल धारा में जोड़ने के लिये आवागमन को प्राथमिकता देते हुये इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है । सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में पीएम जन-मन योजना के तहत कई सड़कें अभी बन रही है । बिजली बिल हाफ के बारे में कई लोग बोल रहे थे । मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछली सरकार अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार आयेगी तो हम बिजली बिल माफ कर देंगे। लेकिन बिजली बिल कहीं माफ नहीं हुआ। मैं ज्यादा न बोलते हुए एक उदाहरण भाषण से हटकर...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, बिजली बिल हाफ की योजना माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हुई थी और हमने हाफ किया था। जब आपकी नई सरकार बनी तो आपकी सरकार ने बिजली बिल हाफ को समर्थन दिया था लेकिन उसके बाद फिर 400 यूनिट बढ़ा दिए, उसके बाद फिर -200 यूनिट किए। आप लोग बिजली बिल का रेट बढ़ा रहे हैं, हमारी सरकार ने बिजली बिल को हाफ किया था।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- हमारी सरकार ने बिजली बिल की यूनिट को हाफ किया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने बढ़ाया है, अगर आप बिजली बिल को 500 यूनिट बोलते न तब हम बधाई देते। आपने 400 यूनिट को 200 यूनिट करके बड़े-बड़े पोस्टर लगवाए कि हमने बिजली बिल का यूनिट कम किया है।

सभापति महोदय :- देखिए उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, कुछ भी बोलेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे?

सभापति महोदय :- सुन लीजिए बर्दाश्त कर लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, नहीं सुन सकते।

सभापति महोदय :- उद्धेश्वरी जी, आप मेरी तरुफ देखकर बोलिए।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- जी, आपकी तरफ ही देखकर बोल रही हूं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बजट बुक से हटकर थोड़ा सा एक विषय पर बोलना चाहूँगी। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी ने बुक से हटकर जो बात कही, वह मेरे क्षेत्र का ही है। अभी उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब ने आदिवासी परिवार की हत्या की। अभी मेरे क्षेत्र में सामरी विधानसभा के हंसपुर ग्रामीण में जिस तरह की घटना हुई है, अभी 15 तारीख शिवरात्रि की रात में जो घटना हुई, उससे मैं भी बहुत दुखी हूँ। जो आदिवासी परिवार है जिसका हत्या हुई है, मैं उसको इस सदन के माध्यम से नमन करती हूँ। वहां पर जो भी एसडीएम रहे हैं, उनके द्वारा जो भी मारपीट हुई है, चाहे हत्या की हैं, जो भी हुआ है, उनके ऊपर तत्काल एफआईआर भी हुआ और एफआईआर के साथ-साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई और उनको जिला जेल में भेजा गया, जिला जेल के बाद उनको सेंट्रल जेल अंबिकापुर में भेजा गया है। जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैकुंठपुर में जब सरगुजा विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की, मैंने उसी दिन आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी सरल-सहज हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी, मेरे विधानसभा में हमारे आदिवासी के साथ इस तरह की घटना हुई है, यह बहुत ही दुखद घटना है और जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी सरकारी अधिकारी है, एसडीएम है, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड किया जाए। मैंने निवेदन किया था और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उन्हें तत्काल सस्पेंड भी किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय गृहमंत्री विजय शर्मा जी को बहुत-बहुत बधाई शुभकामनाएँ देती हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय विधायक जी, आपने उस आदिवासी परिवार के लिए सरकार से मुआवज़ा या नौकरी की माँग नहीं की?

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माँग की है, उनको तत्काल 1 लाख रूपये की सहयोग राशि भी प्रदान की गई है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बस-बस। हमारे आदिवासी का जीवन एक लाख में हो जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- उनके लिए और मुआवजा की भी मांग की है। तत्काल मुआवज़ा नहीं होगा, सहयोग राशि 1 लाख तत्काल उनके परिवार को दिया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- संगीता जी, देखिए वह कहाँ सामरी की विधायक हैं, एकदम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर की हैं, वह बढ़िया बोल रही हैं तो उनकी बात सुनिए ना थोड़ा। थोड़ा सुन लीजिए। आप बोलिए।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- धन्यवाद, सभापति महोदय जी, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए अवसर प्रदान किया है। सर्वप्रथम तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने बड़ी ही खूबसूरती से सरकार की कार्य प्रणाली और विजन को रखा है। जिसमें छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने का हम सुनहरा सपना सजा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। हम वर्तमान को नजरअंदाज करके आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अच्छी बात है कि हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेश बने, लेकिन केवल हवा-हवाई बात करने से नहीं बनेगा, बल्कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। सभापति महोदय जी, हम महतारी गौरव वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आज हमारी माता-बहनें सुरक्षित नहीं हैं। जिनकी सुरक्षा का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश के किसान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी उपज का भुगतान एकमुश्त और सीधे पंचायतों के माध्यम से करने का वायदा किया गया था, जो अधूरा रह गया है। आज भी हमारे किसान भाइयों का टोकन नहीं कट पाया है। वह कर्ज ले चुके हैं, लेकिन उनका धान नहीं बिका है और साथ ही आज किसान भाई खाद के लिए भटक रहे हैं। खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिस पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसका भी जिक्र होना था। सरकार कोदो और रागी जैसे मिलेट्स की खेती की संभावना तलाश रही है। अभी हमारी दीदी बोल रही थी कि कोदो से हमारी महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हमारे कांकेर जिले में एशिया का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट हमारे माननीय भूपेश बघेल जी सरकार के समय खुला था, आज कहीं न कहीं वह मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट बंद पड़े हैं और हमारी स्व-सहायता समूहों की महिलाएं उसको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संचालित कर रही थीं, लेकिन आज वह बंद पड़ी है और उनसे रोजगार का अवसर छीन लिया गया है। उसको चालू करने का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सभापति महोदय जी, एक ओर हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर गौवंश सड़कों पर भटक रहे हैं। जिनकी सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। उसी प्रकार प्रदेश की लाखों माता-बहनें जो महतारी वंदन योजना से वंचित हैं, उनको योजना का लाभ दिलाने की कोई रणनीति नहीं है। उसी प्रकार आत्म समर्पित माओवादियों के लिए बेहतर पॉलिसी तो बनाई गई, लेकिन उन्हीं से पीड़ित परिवारों के लिए कोई बेहतर कार्ययोजना का जिक्र होना था, जिससे कि नक्सल पीड़ित परिवारों का भी भविष्य बेहतर हो सके। सभापति महोदय जी, प्रदेश के अधिकांश स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं, जिनके जीर्णोद्धार का इसमें कोई जिक्र नहीं है और उन्हीं स्कूलों में कार्य करने वाले हमारे जितने भी सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उनको दूर करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की बात होनी थी, जो कि नहीं हुई और साथ ही हमारे मध्यान्ह भोजन कर्मचारी अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर विगत दो माह से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। मध्यान्ह भोजन कर्मचारियों को क्रमशः 2,000 और 1,400 रूपए मानदेय भुगतान किया जा रहा है, जिससे आज की महंगाई में परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं है और साथ ही आज हमारी महिलाएं लगातार धरने में बैठी हैं, लेकिन वहां पर कोई पूछ-परख नहीं हो रहा है। वहां पर हमारी दो रसोइयों की भी मृत्यु हो गई है। लेकिन इस पर भी उनकी मांगों पर कोई सहानुभूति विचार या उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इस पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में आम आदमी को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं होता है। सरकार जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने लाखों-अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, परंतु आज तक घरों में सिर्फ नल की टोटी लगाई गई है, पानी टंकी सूखी पड़ी है, बोर में पर्याप्त पानी नहीं है, पाइप की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और ठेकेदारों को राशि का भुगतान नहीं होने से यह सभी काम अधूरे पड़े हैं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। स्वास्थ्य केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसे दूर करने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना था। धमतरी से कांकेर तक रेल लाइन का विस्तार और रायपुर से जगदलपुर तक वायु सेवा को नियमित रूप से चालू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना था, जो कि नहीं हुआ। अभी हमारी दीदी कह रही थी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि हमारी सरकार आई है तो आदिवासियों की पूछ-परख बढ़ी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जब हमारी पूर्ववर्ती भूपेश भैया की सरकार थी, तो उन्होंने हमारे आदिवासियों की संस्कृति और संरक्षण के लिए देवगुड़ी और घोटुल जो चालू किया था, वह आज हमको नहीं मिल रहा है। देवगुड़ी जो पूरे बस्तर संभाग में चालू था, सबको मिला था पर अभी 2 साल से हमको देवगुड़ी और घोटुल नहीं मिल रहा है तो उसको भी चालू किया जाए। साथ ही अभी महतारी सदन की जो बात हो रही थी, जिसकी हमारी दीदी लोग बहुत तारीफ कर रही थी तो यहां पर माननीय उपमुख्यमंत्री जी बैठे हैं और मैंने उन्हें पिछले समय भी बोला था कि मेरे क्षेत्र में भी लोग आपकी तारीफ कर रहे थे कि उनको महतारी सदन मिल गया है और मैं भी चाहती हूं कि मेरे भानुप्रतापपुर को भी महतारी सदन मिले।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- आप भी तारीफ कर दीजिये।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- बिल्कुल, अगर मेरे क्षेत्र में भी मिल जाए तो जरूर मैं यहां इस मंच से तारीफ करूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरे को भी मिले और मुझे मिलेगा तो मैं भी तारीफ करूंगी। मैंने आपको पिछले समय भी बोला था और मैं भी चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में भी महतारी सदन दिया जाए । मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का घोर विरोध करते हुए अपने भाषण को समाप्त करती हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मैंने तो आपको टोका ही नहीं, अभी आप और बोल सकती थीं।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- जी।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के कृतज्ञता के अवसर पर सीधा-सीधा बस्तर को लेकर के बात करना चाहूँगा। चूंकि मैं बस्तर से आता हूँ। जब कभी-भी इतिहास के पन्ने में कोई शब्द लिखे जाएँगे तो 20वीं शताब्दी के अंत का और 21वीं शताब्दी के इस शुरुआत का और खास करके ये रजत वर्ष का उल्लेख जरूर होगा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 40 साल से कैंसर की तरह जो बीमारी नक्सलवाद के रूप में हमें सौगात में दी गयी थी, उसको पूरे तरीके से समाप्त करने की जो रणनीति है, वह कामयाब हो चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब विपक्ष ने सारे माहौल को नकारात्मक ढंग से पेश करने का प्रयास किया था, ऐसे समय में कवासी लखमा जी ने सरकार के इस प्रयास की तारीफ की है। मैं उनको बहुत-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस चीज को हम सब ने भुगता है । हमने बहुत नजदीक से देखा है। आज जिस जगरगुंडा से बस चलाने की बात हो रही है, जिस जगरगुंडा को फिर से ऊपर आने का अवसर मिला है, ये जगरगुंडा कभी बस्तर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। वहां पर बैंक हुआ करता था। वहां का बाजार करोड़ों रुपये का एक आय-व्यय का साधन हुआ करता था जिसको नक्सलवादियों ने पिछले 40 सालों से अपने कब्जे में लेकर के रखा था। आज 02 साल के भीतर ऐसा चमत्कार हुआ है और इस चमत्कार को कोई आसानी से नहीं लाया गया है। एक खुली चुनौती के साथ, एक डेडलाईन निर्धारित करके 31 मार्च तक आप या तो सरेण्डर कर लीजिए या तो बस्तर को छोड़कर के कहीं दूर चले जाईये, वर्ना मरने के लिये तैयार होईये। ये संकल्पशक्ति जो ज्ञान, गति से शुरूआत होती है और संकल्प में आकर के ठहर जाती है और इस संकल्पशक्ति का परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है जिसमें इसकी परिभाषा अलग-अलग प्रकार से बताई गई है। किसी ने कहा कि ये आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक असमानता का कारण था जिसकी वजह से नक्सलवाद आया। किसी ने कहा कि बेरोजगारी के कारण नक्सलवाद आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक इच्छाशक्ति की जो कमी थी, जिस समय देश आजाद हुआ, जिस समय कांग्रेस को काम करने का अवसर मिला था, उन्होंने स्कूल में ध्यान नहीं दिया, सड़क, पुलिया नहीं बनवाई, लोगों के वनोपज को ठीक से खरीदी करने की व्यवस्था नहीं की। उसी का ये नतीजा था कि हमको नक्सलवाद झेलना पड़ा। लेकिन आज हमारे लिये खुशी की बात है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है। इसमें अगर बस्तर ओलंपिक के माध्यम से 4 लाख युवाओं को जोड़ने का काम किया जाता है। इसका मायने होता है कि ये हमारे सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जब बस्तर और सरगुजा ओलंपिक की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- टेकाम जी, एक मिनट। हां, आप बोलिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, सरगुजा और बस्तर ओलंपिक की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ में भी समरसता लाने के लिये माननीय भूपेश बघेल जी ने ओलंपिक गेम शुरू किया था। मैं निवेदन करती हूं कि फिर से बस्तर, सरगुजा के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरूआत की जाये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- आपका सुझाव सही है।

सभापति महोदय :- आप रूकिये न। हां, आप क्या बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोल रहा था कि कांग्रेस का इतना विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस ने ही इनको कलेक्टर बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने इनको फंसा लिया। एक को तो मंत्री बना दिया है, एक को खाली भाषण देने के लिये रखे हैं, इसलिए उधर ज्यादा तरफदारी मत करिये।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। चलिये न आप बोलिये, बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री नीलकंठ टेकाम :- मैं आपका थोड़ा गणित ठीक करना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में कलेक्टर बना था। आपके कार्यकाल में तो मेरा इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया था। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर 4 लाख युवा बस्तर ओलंपिक के माध्यम से जुड़ते हैं, उसके अंदर छिपी हुई हुनर को लेकर के सामने आते हैं और उनको आशीर्वाद देने के लिये देश के राष्ट्रपति और गृहमंत्री आते हैं तो इसमें क्या बुरी बात हो जाती है ? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात हो जाती है ? क्या आपके कभी प्रधानमंत्री या मंत्री ने या कहीं के गृहमंत्री ने मोटरसाइकिलों से उस क्षेत्र का दौरा किया ? आपके पास एक भी फोटो होगी तो आप बता सकते हैं। किसी जमाने में इंदिरा गांधी जी ने अबूझमाड़ का, राजीव गांधी जी ने बस्तर क्षेत्र का दौरा किया था, उसको आज तक आप लोग भुनाते रहे हैं। जब भी मौका मिला आप बताते रहे हैं कि इंदिरा गांधी बस्तर की आदिवासी महिलाओं के साथ रेला नाचीं थीं। राजीव गांधी जी वहां पर जा करके आदिवासियों के हितैषी बने थे। लेकिन उनके अंदर का जो छिपा हुआ दर्द है, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि बस्तर वालों के लिये उसका जल, जंगल, जमीन, माइनिंग ही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग तो अभी अडानी, अंबानी को लाकर जल, जंगल, जमीन को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री नीलकण्ठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को बहुत-बहुत सलाम करता हूँ और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ किं इस तरह से जो बार-बार अडानी-अडानी का गुणगान करते हैं इनके सामने बस्तर के वनोपज को लेकर इतना बड़ी एक औद्योगिक व्यवस्था बनायी जाये ताकि इनके जुबान पर ताला लग जाना चाहिए। आज हमारे प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हुआ, ऊपर वाले की कृपा रही, माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद रहा। हमारे बस्तर में आम का बौर जबरदस्त आया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुआ है, वहां ईमली का फल जबरदस्त लगा हुआ है और अभी वहां पर चार का फूल भी महकने लगा है। मैं पक्की उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो संवेदनशील सरकार है, वह वनोपज की बेहतर खरीदी, प्रोसेसिंग, गोडाउनिंग, मार्केटिंग के लिए व्यवस्था बनायेगी। क्योंकि हम जो आलोचना झेल रहे हैं इनको उसका जवाब मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, इस आयोजन ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनायें, लेकिन इन सब के बीच में 7 जोड़े ऐसे शामिल हुएं, जो आत्मसमर्पित लोग थे, जिन्होंने सरकार के सामने समर्पण किया था। वह भी इस सामूहिक विवाह से लाभांवित हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सुखद संदेश है। वहां नक्सलवाद के समाप्त होने के तुरंत बाद जहां पर आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था, वहां पर इपिक कार्ड नहीं बन पा रहा था, लोगों के स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा था, अब वहां यह सारे काम शुरू हो चुके हैं। अब बस्तर के लोगों को यह सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगीं। यहां 60 हजार महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है।

सभापति महोदय :- माननीय टेकाम जी, एक मिनट।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री टेकाम जी बता रहे हैं कि वहां पर अब आधार कार्ड बन रहे हैं, इपिक कार्ड बन रहे हैं। मैं अभी बस्तर से होकर आया हूँ, वहां सब परेशान हैं। मैं यह फिर से कहना चाहूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि यह वर्ष 2047 तक बनेगा ।

सभापति महोदय :- यह आप बजट में बोल लीजिएगा।

श्री आशाराम नेताम :- बस्तर में कौन से गांवों का आधार कार्ड नहीं बना है। आप मुझे लिखित में दीजिए। मैं उसको बनवाता हूँ।

सभापति महोदय :- आप लोग आपस में बात मत कीजिए। आप कल बजट में बोल लीजिएगा।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बता दूंगा।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सदस्य की बात का ऐसे अवेहलना नहीं करना है। आप मुझे लिखित में दीजिये। वहां कौन से आदमी का आधार कार्ड नहीं बना है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। यह ठीक बात नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- माननीय आशाराम नेताम जी, एक आशाराम बापू जी अंदर हैं। आप सदन के अंदर में है आप यहां असत्य मत बोलिए।

श्री आशाराम नेताम :- यह आपके विचार हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। उनको बोलने दीजिए।

श्री नीलकण्ठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जो फायदा दिखायी दे रहा है उसके बारे में तारीफ करनी ही चाहिए। मैंने जैसे बताया कि माननीय लखमा जी ने तारीफ की है दादी, वैसे ही सब लोगों को सीखाने की जरूरत है। पहले आप बाहर इन सब को सीखा दिया करिये। उसके बाद यहां आपको इन लोगों को लेकर आना चाहिए। हमें तो यह बड़ी संतुष्टि भी है और इस बात की खुशी भी है और हमें भविष्य को लेकर एक भरोसा भी जगा हुआ है कि वहां पर एकलव्य और उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल के माध्यम से एक नये सिरे से बस्तर खड़े होने लगा है। वहां उड़ान और शिखर के माध्यम से हम उस मुकाम को फिर से हासिल करेंगे जो जाने-अनजाने में हमसे छिन लिया गया था। यह सरकार की दूरदृष्टि का नतीजा है, सरकार की भविष्य की जो सोच है यह उसका नतीजा है कि आज स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुख सुविधाओं के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। वहां पर जगरगुण्डा में एजुकेशन सिटी बनने जा रहा है। वहां अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी बनने जा रहा है, जहां से हमारे बच्चे तैयार होकर निकलेंगे। जब वहां से तैयार होकर निकलेंगे तब वह भ्रमित नहीं रहेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। उनको कोई बहका नहीं सकता है और किसी को अंधभक्ति में जी-हजूरी करने की जरूरत नहीं होगी। आज हमारे बस्तर में ऐसा समय आ गया है। हम जो अमृतकाल की बात करते हैं, वास्तव में छत्तीसगढ़ और बस्तर में वह अमृतकाल दिखने लगा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व में पूरे मंत्रिमण्डल और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष 2047 का एक खाका खिंचकर रखा है, वहां तक पहुंचने के लिए अधोसंरचना का विकास कैसे हो सकता है, कनेक्टिविटी में क्या करना चाहिए, मार्डन टेक्नालॉजी का एग्रीकल्चर में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और हमारे शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एस.टी.,एस.सी., ओ.बी.सी., महिलाओं, नवजवानों के लिए कैसे हम पॉलिसी बना सकते हैं, उसकी बात कही गई है। मैं चाहूंगा कि इस अभिभाषण को आप लोग तीन बार जरूर पढ़िए, उसके बाद कुछ चीज को समझ पाएंगे । फिर यहां पर आप लोग अपनी बात रखें । अच्छी बात के लिए तारीफ होनी चाहिए । कुछ कमियां रह जाती हैं, उसके बारे में आलोचना भी जरूर होनी चाहिए । हम सब लोग दोनों तरह की बात सुनने के लिए तैयार रहते

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं । खासकर जो हमारे नये विधायक चुनकर आये हैं, जिनका दूसरा साल चल रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अनुभव है। हमें विधान सभा का नया भवन देखने को मिल गया । वहां पर बड़ा मुश्किल से बैठने को मिलता था । हमारे लिए बहुत खुशी की बात है । इसके साथ ही साथ आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो नये-नये अवसर आ रहे हैं, चाहे ए.आई. के माध्यम से हो, चाहे एस.सी.आर. के माध्यम से हो, रायपुर से लेकर भिलाई तक के इतने बड़े एरिया को एक नये क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात आ रही है, सबका उल्लेख माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में लिखा हुआ है । यह नए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की बुनियाद बनेगी और आने वाले दिनों में जब विकसित राष्ट्र की बात आएगी तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के रूप में खड़ा होकर दुनिया के सामने आएगा । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ।

(मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतियों के बारे में विस्तार से बताया है। इसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं । सभी सदस्यगणों एवं राज्य की जनता को राज्य स्थापना और हमारी विधान सभा की रजत जयंती की बहुत-बहुत बधाई । हम सबने लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में विकसित छत्तीसगढ़ की ओर अपनी नई यात्रा आरंभ की है । विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे भागीरथ प्रयासों की झलक माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिखी है । पिछले दो सालों में हमने जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ महतारी के सभी सपूतों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं । उनकी मेहनत, भरोसे और सुझाव ने हमें भरपूर ऊर्जा प्रदान की है । हम पूरी तनमयता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जुटे हुए है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा प्रदेश धान का कटोरा कहलाता है । धान हमारी अर्थव्यवस्था के साथ सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है । हमारा प्रदेश ऐसे ही धान का कटोरा नहीं बना, इसके लिए पुरखों ने कड़ी मेहनत की है । पहली बार जब उन्होंने इस जमीन को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जोता होगा तो जानें कितने पत्थरों को उनको हटाना पड़ा होगा, उन्होंने कितनी बाधाएं को पार की होंगी । छत्तीसगढ़ की माटी को अपने परिश्रम से सींचने वाले ऐसे सभी पुरखों को मैं इस नई विधान सभा भवन से नमन करता हूं। विकास की जमीन तैयार करने के लिए भी ऐसे ही परिश्रम, प्रमाणिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृतव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विकास की बात करती है । वहीं कांग्रेस हमेशा विनाश की बात करती है । इसका उदाहरण हम छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने इस प्रदेश का कितना नुकसान किया है । भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना कांग्रेस सरकारों की कार्यशैली है । केन्द्र हो या राज्य, जहां भी कांग्रेस की सरकार रही है, आप पिछली इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनकी सरकारों ने लगातार भ्रष्टाचार करने का काम किया गया है । हमारे प्रदेश की रजत यात्रा भी इसकी गवाह है, जब अटल जी की सरकार ने हमें राज्य को तोहफा दिया, तब कांग्रेस की सरकार बनी थी । यह बड़ी जिम्मेदारी जो उनसे सम्हली नहीं। जनता का मोह भंग हुआ और जनता ने विकास को चुना। पहली विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। हमारी सरकार ने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमंखी विकास किया। फिर कांग्रेस की सरकार अपने झूठे प्रलोभन, जन घोषणा-पत्र के माध्यम से फिर सरकार में आई, लेकिन उनके 5 साल का कार्यकाल कैसे रहा, इसको सब जानते हैं। यह उसी का परिणाम है कि आज उन लोग हमारे सामने बैठे हैं। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। 5 सालों में एक भी बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं प्रारंभ किया। बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए राहत की कोई उम्मीद नहीं, किसानों, युवाओं और महिलाओं की मेहनत के लिए राहत की कोई उम्मीद नहीं, बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए राहत की कोई उम्मीद नहीं, किसानों, युवाओं और महिलाओं के मेहनत के सम्मान की जगह केवल अपमान पिछले 5 सालों में मिला। सभापति महोदय, कांग्रेस का सिंडीकेट जनता को लूटता रहा। इनके लूट का खेल धरती के ऊपर भी था और धरती के नीचे भी था। इन्होंने कोयला का काला खेल खेला। नकली होलोग्राम लगाकर नकली शराब पिलाई। प्रदेश को सट्टे के लिए बदनाम कर दिया। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से आरंभ किए गए स्कूलों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। इन्होंने डी.एम.एफ. की राशि में भी भ्रष्टाचार किया। देश में छत्तीसगढ़ की पहचान आबकारी घोटाला, कोल घोटाला, महादेव सट्टा और डी.एम.एफ. आदि कितने ही घोटालों से बना दिया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार, पिछली सरकार ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छोड़ा, जहां भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बनती हो। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, वह अब राजकोष में जमा हो रही है। हमारी सरकार इसके माध्यम से कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर संचालन कर रही है।

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। जब वर्ष 2021 में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय आबकारी में 5,110 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होता था। लेकिन आज वर्ष 2025-26 में मात्र दो साल के कार्यकाल में इसको बढ़ाकर 11 हजार करोड़ रूपये किया है। (मेजों की थपथपाहट) उसी तरह से खनिज में वर्ष 2021-22 में 12,305 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होता था और इस वर्ष 2025-26 में बढ़कर 16,500 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है। पिछली सरकार ने राजीव गांधी जी के नाम पर युवा मितान क्लब बनाया था। लेकिन हमेशा की तरह यहां भी भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश बनाये रखा। मुझे केवल एक जगह पर राजीव गांधी मितान क्लब की राशि खर्च होते दिखी और वह था राहुल जी की जब सभा होती थी तो युवा लोग टी-शर्ट और टोपी पहनते थे, उसी में युवा मितान क्लब की राशि का खर्च दिखता था, बाकी उसमें भी पूरा बंदरबांट हुआ। भ्रष्टाचार के बाद जो थोड़ा समय बचता था उसमें कुर्सी के लिए लड़ते थे। पूरे 5 साल कुर्सी के लिए, इनकी ढाई-ढाई साल वाली रस्सा-कस्सी चलती रही और इनकी लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता पीसती रही।

सभापति महोदय, भर्ती परीक्षा में किया गया अपराध सबसे जघन्य अपराधों में होता है। क्योंकि यह केवल एक युवा के सपनों की हत्या नहीं होती है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को भ्रष्टाचार के गर्त में पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। युवाओं के भविष्य से खेलने वाले ऐसे लोगों को पिछली सरकार में संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई, यह ताज्जुब की बात है। युवाओं के सपनों का कत्ल करने वाली कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भर्ती परीक्षा में किया गया भ्रष्टाचार युवाओं के सपनों को तोड़ने के साथ अयोग्य लोगों के लिए सिस्टम में दरवाजे खोलने का काम करता है। माननीय सभापति महोदय, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के कचरे को साफ किया है। हमेशा कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के मामलों में मछलियां तो पकड़ ली जाती हैं, लेकिन मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं। प्रदेश को लूटने वाले मगरमच्छ अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। ((मेजों की थपथपाहट) कुछ कतार में हैं, जो बहुत ही जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जनता की गाढ़ी कमाई में सेंध लगाने का हक किसी को भी नहीं है। हमने भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लीकेज रोकने के लिए अनेक सख्त उपाय किए हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने और पारदर्शिता लाने में हमारा दृढ़ संकल्प और तकनीक हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास में भ्रष्टाचार के साथ एक बड़ा रोड़ा नक्सलवाद की समस्या भी रही है । लेकिन आज पूरा देश जानता है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छाशक्ति, उनका आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन के कारण आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है । (मेजों की थपथपाहट) हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने डेडलाइन तय कर दिया है कि इसी साल 31 मार्च को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है । (मेजों की थपथपाहट) जब हम लोग सरकार में आए और दिसंबर, 2023 में और अगले ही महीना हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहां पर नक्सलवाद को लेकर समीक्षा बैठक लिये तो पता चला कि देश का 77 प्रतिशत नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में है और इसका कारण यह था कि पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ने की कोई दृढ़ इच्छाशक्ति सरकार की तरफ से दिखाई नहीं गई । लेकिन डबल इंजन की सरकार का लाभ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मैं इस अवसर पर हमारे जवानों के अदम्य साहस को भी नमन करता हूं कि उनके अदम्य साहस के कारण आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है । (मेजों की थपथपाहट) 40 साल से भी ज्यादा समय तक हमारा जो बस्तर क्षेत्र जो केरल प्रांत से भी बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, जिसको हम धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, वह विकास से अछूता रहा । लेकिन हम अब आश्वस्त करना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से अब नक्सलवाद वहां पर समाप्त हो रहा है और हम लोग वहां पर विकास की गंगा बहाने वाले हैं । (मेजों की थपथपाहट) नियद नेल्लानार योजना शुरू किए हैं ये गोंडी में है इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव और इसके माध्यम से आज लगातार वहां पर सुरक्षा कैंप खुले हैं और हमारे 400 से भी ज्यादा गांव आबाद हुए हैं और नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से हम लोग बुनियादी सुविधाएं वहां लोगों को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं । जहां वहां कभी लोग जाते नहीं थे, जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन आज वहां सड़कें बन रही हैं, वहां बिजली पहुंच रही है, वहां घरों में पानी पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, राशन पहुंच रहा है । वहां सिर्फ गोलीबारी की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज वहां पर स्कूल की घंटी बज रही है । इस बार पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर 43 गांव में राष्ट्रीय ध्वज वहां पर फहरा है । (मेजों की थपथपाहट) अस्पताल वहां पर खुल रहा है । तो इस तरह से वहां विकास की गंगा बह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रही है और तो और वहां पर जो हिड़मा जो बड़ा सी.सी. मेम्बर था, उसकी मां आज हमारे खोले गए अस्पताल में इलाज करा रही है । (मेजों की थपथपाहट) हम लोग अच्छा पुनर्वास नीति भी लाए हैं और इसके कारण 2700 से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और उनकी चिंता सरकार कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, जब हिंसक गतिविधियां होती हैं तो इनसे केवल जान-माल का ही नुकसान नहीं होता है, इनसे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य खराब हो जाता है । माओवादी हिंसा ने हमारी सुंदर धरती के साथ ऐसा ही किया । स्कूल जला दिए थे, स्कूल नष्ट कर दिए थे और वहां पर हथियारों की फैक्ट्री खोल दिए थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, वहां भी विकास का सूर्योदय हो रहा है और लगातार वहां पर विकास के काम हो रहे हैं । वहां पर अलग से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की तो दो वर्षों में स्वीकृति हुई ही है, लेकिन हमारे जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनके लिए भारत सरकार से अलग से 15000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है और उसका भी काम चल रहा है । (मेजों की थपथपाहट) आपको हम यह बताना चाहेंगे कि दो साल से हम लोग वहां पर बस्तर पंडुम करा रहे हैं । पिछले साल बस्तर पंडुम में 47000 कलाकार पंजीयन कराए थे, इस साल बढ़कर 54000 कलाकार हो गए । (मेजों की थपथपाहट) बस्तर ओलंपिक कराए । बस्तर ओलंपिक में पिछले साल 1,65,000 लोग पंजीयन कराए थे, इस साल 3,91,000 लोग उसमें युवा लोग पंजीयन कराए । (मेजों की थपथपाहट) यह इस बात का प्रमाण है कि वहां के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका सबका स्वागत है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस साल के बस्तर पंडुम का शुभारंभ हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया और उसका समापन हमारे देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, उधर बहुत आरोप लगता है कि वहाँ पर नक्सलवाद इसलिए समाप्त किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उद्योगपतियों को बैठाना है। लेकिन हम आज इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को और विशेषकर बस्तर की जनता को यह बताना चाहते हैं कि यह सब विरोधियों का दुष्प्रचार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) (माँ दंतेश्वरी का जयकारा लगाया गया) बल्कि हम बस्तर के क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं, वहाँ के किसानों के खेतों में पानी पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर सिंचाई का साधन बढ़ाना चाहते हैं। बस्तर में सैकड़ों तरह के Forest Produce हैं, हम लोग उनका वैल्यू एडिशन कराके वहाँ पर लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कराना चाहते हैं। (मेजों की थपथपाहट) वहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, वहाँ पर अनेकों जलप्रपात हैं, वहां कुटुमसर की गुफा है, वहां अबूझमाड़ जैसा Dense

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

Forest है और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यू.एन. ने पर्यटन के क्षेत्र में जो Best 20 Villages का चयन किया है, उसमें हमारा बस्तर का धुड़मारास गांव है। इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? (मेजों की थपथपाहट) उस क्षेत्र में होम-स्टे बड़ा प्रचलित है। जो Foreigner tourist आते हैं, वे यहाँ पर कोई बड़े होटलों में रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ लोकल लोगों के घर में रहकर उनके जैसा खाना-पीना और उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 लाया है, उसमें हम लोग पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं। (मेजों की थपथपाहट) हम लोग होम-स्टे को बढ़ाना चाहते हैं। होम-स्टे से वहां का परिवार सीधे-सीधे आर्थिक रूप से लाभान्वित होगा, इसलिए उस क्षेत्र में और बस्तर के क्षेत्र में भी हम लोग होम स्टे को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज पूरे देश में जनजातीय संस्कृति में कितनी रुचि है, इसका उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि जो नया रायपुर में Tribal Museum बनाया गया है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने 01 नवंबर को हमारे प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन लोकार्पण किया। आज वहां लगातार हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह इस बात का प्रमाण है कि देश के लोग हमारी जनजातीय संस्कृति से वाकिफ होना चाहते हैं। यह संग्रहालय देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उस संग्रहालय को देख कर गए हैं और जब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी तब वे उसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे थे। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह से इस म्यूजियम में हमारे ट्राइबल के जो महापुरुष हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर शहीद हुए थे, ऐसे 14 क्रांतिकारियों का उसमें सचित्र चित्रण हुआ है। सबको इसको जाकर देखना चाहिए।

सभापति महोदय, हम विरासत के साथ विकास के भी पक्षधर हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की बोली, भाखा, खान-पान, रीति-रिवाजों को सहेजने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी सुंदर संस्कृति के केंद्र में हमारे भांजा श्रीराम हैं। प्रदेश के नागरिकों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि अभी तक 42,000 लोग रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) हम लोग प्रभु श्रीराम जी को अपना भाचा मानते हैं। जब 500 साल के संघर्षों के बाद रामलाल वह भव्य मंदिर में विराजे और उनकी प्राण-प्रतिष्ठा हुई, उस समय छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अनेकों तरह से खुशियों का इजहार किया। यहां से अयोध्या सुगंधित चावल गए, अनेकों लोगों ने महीनों भर तक वहां पर मुफ्त में लाखों लोगों को भोजन कराया। इस तरह से उनको बड़ी खुशी हुई है और आज हजारों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं।, इतना ही नहीं हमारे जो बूढ़े-बुजुर्ग होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ यात्रा कर लें, गंगा स्नान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करके आ जाये । पिछले 15 सालों में डॉ.रमन सिंह जी ने इस योजना की शुरूआत की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे बंद कर दिया था । अब इसे फिर शुरू किया गया है और आज यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि 5000 से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ ले चुके हैं। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस की बंदरबांट और करप्शन की बात कर रहा था, इन लोग राम वन गमन पथ को भी नहीं छोड़े हैं । राम वन गमन पथ की बड़ी बात करते हैं, राम वन गमन पथ के विकास के लिये करोड़ों रूपये खर्च किये हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता है । यहां तक कि वहां पर प्रभु श्री राम जी का जो मूर्ति लगा है, उसमें भी कमीशन खा गये है । अभी हमारी सरकार वहां पर एक सुंदर मूर्ति लगाने जा रही है, इन लोगों ने कहीं भी भ्रष्ट्राचार को नहीं छोड़ा है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- इनका तो एक ही विषय कमीशन था ।

श्री विष्णुदेव साय :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ बाबा गुरूघासीदास जी की धरती है, उन्होंने मनखे-मनखे एक समान का उपदेश मानव समाज को दिया है । आज गिरौदपुरी धाम जो बाबा गुरूघासीदास की जन्मस्थली है और तपोस्थली भी है, आज वहां पर जितना विकास हुआ है, वहां का जोड़ा जैतखंब है और वह कुतुबमीनार से भी ऊँचा है । वहां पर जो भी विकास के काम हुये हैं, वह सभी हमारे 15 साल के कार्यकाल में हुये हैं । अभी गिरौदपुरी और भण्डारपुरी में 162 करोड़ के विकास काम हो रहे हैं । इस तरह से यहां पर पूज्य गुरूघासीदास बाबा जी के मान सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है । सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिये चित्रोत्पला फिल्म सिटी का भूमि पूजन हुआ है और आने वाले समय में नया रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण होगा और यहां पर कई फिल्म के शूटिंग भी होने वाले हैं । सभापति महोदय, हम लोगों ने मीडिया के साथियों को एक्सपोजर विजिट भी कराये हैं, रायपुर में साहित्य उत्सव भी हुआ है, इसकी चर्चा पूरे देश में है । सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत हमारे देश में की है और आज गांवों का सौभाग्य है कि हर गांव डामर रोड से जुड़ रहा है, गांव के पुराने लोग डामर रोड देखने के लिये तरसते थे । हमारे दादा-दादी और पूर्वज "बासी" पकड़कर डामर रोड कैसे होता है, उसे देखने दूर तक जाते थे, लेकिन इस देश का और इस देश के गांवों का सौभाग्य है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण आज गांव-गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ रहा है । माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, आज इस देश में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से अछूता है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हर वर्ग के लिये योजनाओं की शुरूआत की है, उसी तरह से जो PVTG के लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसी पांच जातियां हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है । जहां उनको कोई देखता नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके विकास के लिये भी चिन्ता की है और पीएम जन-मन योजना में वहां सड़कें, बिजली, पानी के साथ ही 2 लाख रूपये का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, इस तरह से इनका भी विकास हो रहा है । सभापति महोदय, सुशासन तिहार के तहत हम ऐसे कई PVTG गांवों में गये थे, जहां पर लोग बहुत खुश थे, उस समय नई-नई सड़कें बनी हुई थी, वहां प्रधानमंत्री आवास बने हुये थे, उनके घरों में बिजली पहुंची थी, उनके चेहरों में जो खुशी दिखती थी, उससे बहुत आत्मसंतुष्टि होती थी । वैसे तो सारी योजनाओं का लाभ हमारे जनजाति समाज को भी मिल रहा है लेकिन फिर भी किसी तरह से संसाधन की कमी न रहे इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, जो 80 हजार करोड़ का है, उसकी भी शुरुआत इस देश में की है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ का 6,691 गांव इसमें शामिल है, यहाँ पर हर तरह का विकास का काम होने वाला है। ये विकास का काम हमारे प्रदेश में चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में साढ़े 12 से 13 लाख लोग और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में, गरीब, जनजाति समाज के लोग तेंदूपत्ता से जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र में तेंदूपत्ता को हरा सोना भी कहते हैं। लेकिन पिछले समय कांग्रेस की सरकार ने जरूर 4,000 मानक बोरा किया गया था लेकिन दो दिन तेंदूपत्ता खरीदते थे, लोग तेंदूपत्ता बेच भी नहीं पाते थे। लेकिन हम लोग 4,000 की जगह पर उसकी कीमत 5,500 मानक बोरा किए हैं और पूरा तेंदूपत्ता खरीदते हैं। (मेजों की थपथपाहट) इतना ही नहीं, चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। अब इनको क्या पता कि गर्मी के दिनों में जंगलों में लोग जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं, उनके पैरों में जूते-चप्पल नहीं होते हैं और कई बार ये देखने को मिला कि कांटा-खूटी लग गया, घाव हो गया तो गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाती थी, पैर तक काटना पड़ता था। कांग्रेस की सरकार ने चरण पादुका योजना भी बंद कर दी थी, उसको भी हमारी सरकार फिर से शुरू की है। सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ भी न्याय किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा था। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दो साल के अंदर स्वीकृत हुए हैं और 10 महीना में ही हम लोग 5 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरा किए जो कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड बना। (मेजों की थपथपाहट) उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो यहाँ पर भुखमरी होती थी। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अविभाजित मध्य प्रदेश में दो बार विधायक था तो मालूम है कि उस समय हमारे ही जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा लोग भूख

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से मर गए थे और विधानसभा से एक टीम का गठन हुआ था और उसमें जांच में पाया गया था कि सही में लोग भूख से मरे थे। लेकिन आज जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 2003 में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया तो PDS की ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर लागू किए कि आज यहाँ पर भुखमरी बिल्कुल नहीं है। आज यहां पर 1 रुपया किलो में चावल मिल रहा है और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नि:शुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था भी की है, आज यहाँ पर 73 लाख परिवार को उसका लाभ मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने किसानों से जो वादा किया था उसको भी पूरा किया है। तीसरा साल हम लोग किसानों का 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और 3100 रूपए धान का कीमत देने वाले हैं। इस साल 25 लाख 24 हजार किसानों का 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और 33,431 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। जो अंतर की राशि है, इसको भी होली के पहले, 10 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि होती है, 25 लाख 24 हजार किसानों के खातों में होली के पहले इसको भी अंतरित कर देंगे। (मेजों की थपथपाहट) पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो जो अंतर की राशि होती थी, उसको चार किश्तों में देते थे और कभी-कभी उसमें भी गोलमाल कर देते थे, एकाध किश्त इधर-उधर गोल कर देते थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, लहरिया का दिमाग खराब हो गया है। वे वहां बैठकर मुंडी घूमा रहे हैं।

श्री विष्णुदेव साय :- गाना शुरू कर देंगे।

(कृषि मंत्री) श्री रामविचार नेताम :- यहाँ फिल्म सिटी बन रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- दूसरा, आप यह देख लीजिए कि फिल्म इंस्टीट्यूट बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी 150 करोड़ का बना रहे हैं। वह आपका ही काम देगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बिल्कुल-बिल्कुल जाबो।

श्री रामविचार नेताम :- संगीता जी, तुहुं ला रोल मिलही। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कका, तोला का के रोल मिलही? ते खलनायक भर मत रहिबे। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- तोला मिलही। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, जनता में चिंता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- खलनायक के रोल बर तो ओदे हे।

सभापति महोदय :- माननीय सभापति महोदय, फिल्म इंस्टीट्यूट में इनका नहीं है, यह म्यूजिक डायरेक्टर हैं। (हंसी)

श्री विष्णुदेव साय :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है और हम लोगों ने 477 सिंचाई योजनाओं के लिए 1874 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। महानदी और इंद्रावती नदी को भी जोड़ने का काम हम लेने वाले हैं और इससे हमारे बस्तर क्षेत्र में लोगों के खेतों में पानी पहुंचेगा। (मेजों की थपथपाहट) मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिंचाई के क्षेत्र में मात्र 5,700 करोड़ रुपये स्वीकृत किये और हम लोगों ने मात्र 2 साल में 10,700 करोड़ रुपये सिंचाई के क्षेत्र में स्वीकृत किए हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार किसानों के प्रति कितनी चिंतित है और हम लोग पाइप इरिगेशन प्रणाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी, जो बस्तर की चिंता करते हैं और आज बस्तर में यदि शांति बहाल हो रही है तो उसमें माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बस्तर में सिंचाई की बड़ी परियोजना आएगी तो निश्चित रूप से हमारे बस्तर क्षेत्र में एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं महतारी वंदन योजना की बात करूं तो आज बड़ा गौरव होता है कि 2 साल के अंदर में 69 लाख माता-बहनों को हम लोग 24 किश्त दे चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) 15,000 करोड़ रूपये से ज्यादा उनके खातों में पैसे भेज चुके हैं। जब हम लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां महिलाएं इतनी उत्सुक दिखती हैं, इतनी खुश दिखती हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि महतारी वंदन योजना का लाभ कैसे हो रहा है तो वह अनेक तरह से अपनी खुशी को जाहिर करती हैं। कोई कहती है कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोले हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं। किसी की सब्जी की छोटी दुकान है तो वह उसको बड़ा कर रही है। कोई सिलाई मशीन खरीद कर 4,000-5,000 रूपये महीना सिलाई-कढ़ाई से कमा रही है। सारंगढ़ में एक गाँव दानसरा है, वहां की महिलाएं महतारी वंदन के पैसे से चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बना रही हैं। इस तरह से आज महतारी वंदन योजना का लाभ हमारी बहनों को मिल रहा है। मैं पिछले दिनों नारायणपुर गया था, हमारे केदार भाई जी का क्षेत्र गया था तो वहां पर अबूझमाड़िया, जो PVTG में आते हैं, उनकी एक महिला से मैं पूछा तो वो बताई कि वो सिलाई मशीन खरीदी है और 4,000-5,000 रुपया महीना सिलाई-कढ़ाई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करके वो कमा लेती है। तो इस तरह से महतारी वंदन योजना का लाभ हमारी बहनों को मिल रहा है।

सभापति महोदय, हम लोग छत्तीसगढ़ के विकास में युवा ऊर्जा का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए विभिन्न पदों पर 32,000 से अधिक भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, उसको रोकने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ लोक परीक्षा अधिनियम भी लाने जा रहे हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक भी आने वाले समय में लाने वाले हैं। इस तरह से 30 तरह की परीक्षाएं होती हैं, उसको 5 श्रेणियों में बांटकर प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करेंगे। इससे युवाओं में मोटिवेशन भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग नई औद्योगिक नीति लाये हैं। यह इतना अच्छा है कि देश और विदेश में इसकी सराहना हो रही है। हम जापान और साउथ कोरिया भी गये थे, वहां भी इसकी सराहना हुई। अभी हम कह सकते हैं कि एक, डेढ़ साल के अंदर ही करीब 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिला है। (मेजों की थपथपाहट) केवल प्रस्ताव मिला ही नहीं है अपितु धरातल में काम भी शुरू हो गया है। इस तरह से हम लोगों ने नई उद्योग नीति में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे एक जगह आवेदन लगाने पर उद्यमी हो हर तरह का दस्तावेज उपलब्ध होगा। हम लोगों ने रोजगार पर ज्यादा ध्यान दिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगातार भर्तियां चल रही है, उसके बाद भी हमारे बेटे और बेटियों को हम लोग सरकारी नौकरी नहीं दे पायेंगे इसलिए उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम करेंगे इसलिए नई उद्योग नीति में यह व्यवस्था है कि यदि कोई उद्यमी 1000 करोड़ रूपये का निवेश लाता है या स्थानीय 1000 लोगों को नौकरी देता है तो नए उद्योग नीति में विशेष तरह का इंसेंटिव्ह देने का प्रावधान भी हम लोगों ने रखा है।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग नया रायपुर का एडुसिटी के रूप में विकास करने वाले हैं। हमारे यहां के जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे चांपा का सिल्क है, धोकरा आर्ट है और भी कई तरह के है तो उनकी मार्केटिंग करने के लिए अभी बजट में पाँच जो मेन एयरपोर्ट हैं, वहाँ भी उनका शोरूम लगाने का काम हम लोग करने वाले हैं ताकि उसका प्रचार-प्रसार हो और उसको मार्केटिंग मिले। हम लोग अपने युवाओं को अंतरिक्ष की तरफ भी ले जाना चाहते हैं और हमारे जो अंतरिक्ष यात्री सुभांशु शुक्ला हैं, वह दो बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। हम लोगों ने अभी छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ किया है इससे निश्चित रूप से हमारे युवाओं को अंतरिक्ष ज्ञान की शिक्षा मिलेगी। हम लोगों ने अपने प्रदेश में नई शिक्षा नीति भी लागू की है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और नई शिक्षा नीति जो शिक्षा के साथ-साथ रोज़गारपरक भी है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने शिक्षा विभाग में युक्ति-युक्तिकरण भी किया है। इसके पहले स्थिति में भारी असमानता थी। कांग्रेस की सरकार में प्रदेश के सैकड़ों स्कूल शिक्षकविहीन हो गए थे। वे ऐसी ट्रांसफर नीति लाए थे कि सैकड़ों स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं थे और शहरों में ऐसा हो गया था कि शिक्षक ज़्यादा थे और बच्चे कम थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कैसी ट्रांसफर नीति लाए होंगे । लेकिन आज हम लोग युक्तियुक्तकरण के माध्यम से प्रदेश के हर स्कूलों में शिक्षकों को भेजने का काम किए हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की चिकित्सा पर भी बड़ी चिंता है। आयुष्मान भारत के माध्यम से आज अस्पतालों को 4,551 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। जेनेरिक दवाई और वेलनेस सेंटर की तरफ भी सरकार की चिंता है। हम लोग एक बड़ा काम करने जा रहे हैं और यह काम बजट में भी शामिल है। हमारे जो शासकीय कर्मी हैं, उनके लिए हम अब कैशलेस इलाज की सुविधा की भी व्यवस्था करने वाले हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से अभी तक 80 लाख से अधिक नागरिकों के बीपी-शुगर की जांच हो चुकी है। 20 लाख से अधिक नागरिकों के कैंसर की बीमारी का इलाज हुआ है। इस तरह हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित है। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने 21 हजार से अधिक कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य लाभ देकर पोषित करने का काम किया है। हम लोग प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, रेलवे के सेक्टर में भी पिछले दिनों बड़ा अच्छा काम हुआ है। आज करीब 45 हजार करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं में काम चल रहे हैं। इसमें रावघाट, जगदलपुर, खरसिया, परमलकसा जैसी जो महत्वपूर्ण रेल लाइनें हैं, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। इस तरह से हमारे प्रदेश में रेलवे में विस्तार हो रहा है। जो 32 रेलवे स्टेशन हैं, उनको विश्व स्तर का बनाने का काम चल रहा है और 5 स्टेशन का काम पूरा भी हो चुका है। दूरसंचार के क्षेत्र में 500 नये मोबाइल टावर की स्वीकृति हुई है। मैं एक चीज और अवगत कराना चाहूंगा जिसका बड़ा विरोध कांग्रेस के लोग मनरेगा को लेकर कर रहे हैं। लेकिन हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने विकसित भारत जी-राम-जी योजना लाये हैं और यह मनरेगा से कई गुना अच्छा है। 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार देने की इसमें गारंटी है। उसमें पहले 15 दिन में भुगतान करने का था, लेकिन अब एक सप्ताह में भुगतान तय किया गया है और इसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा वह लोग तय करेंगे कि कौन सा काम अपने पंचायत में लेना है। इस तरह से विकसित भारत जी-राम-जी योजना

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा लाया है। हम लोग नगर निगमों के उत्थान के लिये मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लाये हैं। उसी तरह से आगे हमारे जो नगरपालिका, नगरपंचायत को भी विकसित करने का काम करेंगे। रायपुर और बिलासपुर शहर को और स्मार्ट बनाने के लिये भी सरकार काम करेगी। माननीय सभापति महोदय, हम लोग अपने प्रदेश में और एनर्जी को बढाना चाहते हैं इसलिए पिछले समय जो इनवेस्टर कनेक्ट हुआ है, उसमें साढ़े 3 लाख करोड़ का एनर्जी के सेक्टर में एम.ओ.यू. हुआ है। उससे आने वाले समय में और ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे प्रदेश में होगा और हम लोग अपने पड़ोस के राज्यों को भी बिजली बेच पायेंगे। सभापति महोदय, हॉफ बिजली बिल की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग हॉफ बिजली से लोगों को मुफ्त बिजली की ओर ले जाना चाहते हैं। इसमें सोलर पैनल के लिये, सोलर ऊर्जा के लिये सब्सिडी भी है। 1 किलोवाट में 30 हजार रुपए भारत सरकार से और 15 हजार रुपये प्रदेश सरकार से सब्सिडी है।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद 9 का कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री विष्णु देव साय :- सभापति महोदय, मैं तो हमारे प्रदेश के लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि अपने घरों में सोलर पैनल लगवायें और मुफ्त बिजली की ओर जायें। आपको 25 वर्षों तक बिजली का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह से पेड़ों की कटाई की बड़ी बात होती है। हमारे विपक्ष के कुछ वक्ता कह रहे थे कि पेडों की कटाई हो रही है तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आज विकास के लिये पेड़ की कटाई भी जरूरी है। अब हमारे ही एन.एच. 43 देख लीजिए। पहले सिंगल रोड थी, अब उसको टू लेन बनाना है तो पेड़ नहीं काटेंगे तो कहां बनायेंगे। हवा में तो रोड नहीं बना सकते, जमीन में ही बनाना पड़ेगा। अब विकास भी चाहेंगे। आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का मैं बयान सुना हूं। जब वह मुख्यमंत्री थे तो इसी तरह का प्रश्न उनके पास भी आया था तो उन्होंने जवाब में कहा था कि आप बिजली मांगोगे तो बिजली कहां से आयेगी, कोयला से आयेगी और कोयला कहां से आयेगा, कोयला जंगल से आयेगा। पेड़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं कटेगा तो फिर आपको बिजली कहां से मिलेगी। विरोध भी करना चाहिए तो मर्यादित ढंग से करना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) आज मैं बताना चाहूंगा कि 1 लाख 3855 पेड़ अगर कटा है तो उसके बदले में 30 लाख पेड़ लगा है। उदयोग नीति में व्यवस्था है कि जितना पेड़ कटता है, उससे ज्यादा पेड़ लगता है। और आज "एक पेड़ मां के नाम" और ये जो उद्योग नीति के तहत पेड़ लगा है, इसके तहत हमारे प्रदेश में 683 वर्ग किलोमीटर ज्यादा जंगल बसा है। वनों से आच्छादित हमारा 44 प्रतिशत तो आलरेडी है लेकिन ढाई प्रतिशत फिर बढ़ा है। तो ये स्थिति हमारे प्रदेश में है। इसलिए विरोध भी करना चाहिए तो मर्यादित तरीके से करना चाहिए। उसी तरह से उमेश पटेल जी डी.ए.पी., यूरिया खाद की बात कर रहे थे और पिछले दिनों जरूर कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी जिसके कारण थोड़ी सी अड़चन हुई थी। लेकिन उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और रसायन उर्वरक मंत्री आदरणीय जे.पी. नड्डा जी भी थे । हम लोगों की मांग पर 50-50 हजार टन अतिरिक्त खाद भिजवाया था। हम लोगों ने नैनो यूरिया और नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से किसानों को कहीं कमी नहीं होने दी और इस साल हमारी सरकार चिंतित है कि इन सबकी समय पर व्यवस्था हो जाये। बलरामपुर की बात आयी थी, माननीय उद्धेश्वरी बहन उसका जवाब दे चुकी हैं और यह सरकार भ्रष्टाचार, या अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है अगर कोई भी दोषी होगा, जो जांच में सही पाया जायेगा, वह कितना भी बड़ा आदमी होगा, उसको बक्शा नहीं जायेगा। उस एस.डी.एम. की भी तत्काल गिरफ्तारी हुई, उसको निलंबित किया है। मैं बस्तर की बात कर चुका हूँ। वहां पर नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उद्योगपतियों को बसाना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से एक बार इस सदन के माध्यम से बस्तर के लोगों को किसी भी तरह से अफवाह में नहीं पड़ना है। यह सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, आप सबके सुख-दु:ख में साथ खड़ी है। निश्चित रूप से आप लोगों को कृषि, पर्यटन फॉरेस्ट प्रोड्यूस के माध्यम से आप सब लोगों का विकास किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी बताते हुए गौरवांवित महसूस कर रहा हूँ कि इनकी सरकार में घोटाले ही घोटाले हुए थे, लेकिन हम लोगों की पारदर्शी सरकार है इसलिए हमारी सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का अलग से गठन किया गया है। यहां सारा डिजिटलाईजेशन हुआ है यहां तक हमारा जो मंत्रालय है, वह भी ई-ऑफिस प्रणाली से चल रहा है। हम लोगों ने यहां पर पुलिस कमिश्नरी भी शुरू की है। उसका भी अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। रायपुर और बीरगांव निगम क्षेत्र को लेकर नया पुलिस कमिश्नरी का गठन हुआ है, उसका भी अच्छा परिणाम आ रहा है। (मेजों की थपथपाहट) अंत में मैं फिर से माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्यपाल महोदय का धन्यवाद् करते हुए, उन्होंने अपने अभिभाषण में हमारी सरकार के दो सालों के कार्यों, योजनाओं का आईना प्रदेश की जनता के सामने में रखा है। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस धन्यवाद् प्रस्ताव में जो भी सदस्यों ने भाग लिया, मैं उनका भी धन्यवाद् करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं समझता हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर एक साथ मत ले लिया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत किये जाएं।

(समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(मेजों की थपथपाहट)

(सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 26 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।)

(सायं 5 बजकर 30 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 26 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 7 शक संवत 1947) को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गयी)

दिनांक :- 25 फरवरी, 2026 **दिनेश शर्मा**

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) **सचिव**

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं